



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]
No. 17]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1990/वैशाख 8, 1912
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1990/VAISAKHA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1990

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th April, 1990

का. आ. 1083.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत
कब्जेदारों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 (1971 का 40),
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्र सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (1)
में उल्लिखित अपने राजपत्रित अधिकारियों को उपर्युक्त अधि-
नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सारणी के
कालम (2) में उल्लिखित क्षेत्र के संपदा अधिकारी के नाते
सौंपे गए कार्यों के निर्वाह के लिए अतिरिक्त संपदा अधिकारी
नियुक्त करती है।

सारणी

1	3
सहायक आयुक्त (मुख्यालय), उपायुक्त का कार्यालय, अंडमान जिला, पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र
सहायक आयुक्त (बंदोबस्त) जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर, नगरपालिका क्षेत्र।

[सं. यू-14016/3/90-ए. एन. एल.]
प्रकाश चन्द्र, निदेशक

S.O. 1083.—In exercise of the powers conferred by
Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised
Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Govern-
ment hereby appoints the officers mentioned in column (1)
of the Table being gazetted officers of Government to be
additional estate officers for the purpose of the said Act
who shall exercise the powers conferred and perform duties
imposed on the Estate Officer in respect of area mentioned
in column (2) thereof

Table

1	2
1. Assistant Commissioner (Hedged - Post Blair) Office of Deputy Commissioner, Office Andaman District, Port Blair.	Port Blair Municipal area.
2. Assistant Commissioner (Settlement) in the District Office, Port Blair.	Port Blair Municipal area.

[No. U-14016/3/90-ANL]

PARKASH CHANDER, Director

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 30 मार्च, 1990	1967 का. आ. 1282 का. आ. 1457 का. आ. 3253 का. आ. 3530 का. आ. 4151	तारीख 15-4-67 तारीख 29-4-67 तारीख 16-9-67 तारीख 7-10-67 तारीख 25-11-67
का. आ. 1084.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—	1968 का. आ. 821 का. आ. 1441 का. आ. 1870 का. आ. 3423	तारीख 9-3-68 तारीख 27-4-68 तारीख 1-6-68 तारीख 28-9-68
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1990 है।	1969 का. आ. 5008	तारीख 27-12-69
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।	1980 का. आ. 397	तारीख 7-2-70
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम से उल्लिखित किया गया है) में—	1971 का. आ. 3521 का. आ. 249	तारीख 25-9-71 तारीख 1-1-72
(1) नियम 29 में—	1972 का. आ. 990 का. आ. 1600 का. आ. 2789	तारीख 22-4-72 तारीख 1-7-72 तारीख 14-10-72
(क) उपनियम (1) के खंड (iii) में सदस्य (कार्मिक) दूर संचार बोर्ड शब्द और कोष्ठक के स्थान पर 'सलाहकार (मानव संसाधन विकास), दूर संचार विभाग' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;	1973 का. आ. 929	तारीख 31-3-73
(ख) दूसरा परन्तुक में, शब्द और कोष्ठक "सदस्य (कार्मिक, दूर संचार बोर्ड के स्थान पर" सलाहकार (मानव संसाधन विकास), दूर संचार विभाग" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।	1974 का. आ. 1648 1976 का. आ. 2742 का. आ. 4664	तारीख 06-7-74 तारीख 31-7-76 तारीख 11-12-76
(2) उक्त नियमों की अनुसूची के भाग 3 में—	1977 का. आ. 3062 का. आ. 3573 का. आ. 3574 का. आ. 3671	तारीख 8-10-77 तारीख 26-11-77 तारीख 26-11-77 तारीख 3-12-77
(क) श्रम सं. 9, 10 और 11 के सामने स्तम्भ 3 और 4 में, शब्द "महानिदेशक, दूर संचार" के स्थान पर "सदस्य, दूर संचार आयोग" शब्द रखे जाएंगे।	1978 का. आ. 2464 का. आ. 2465	तारीख 2-9-78 तारीख 2-9-78
(ख) श्रम संख्याक 9 और 10 के सामने स्तम्भ 4 में शब्द "सदस्य, डाक और तार बोर्ड के स्थान पर" सलाहकार (मानव संसाधन विकास), "दूर संचार विभाग" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।	1979 का. आ. 920	तारीख 17-2-79
[संख्या 11012/13/89-स्था. (क)]	1980 का. आ. 1769	तारीख 5-7-80
के. सरकार, उप सचिव	1981 का. आ. 264 का. आ. 2126 का. आ. 2203 का. आ. 2512	तारीख 24-1-81 तारीख 8-8-81 तारीख 22-8-81 तारीख 3-10-81
टिप्पणी: प्रधान नियम/आदेश, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 तथा उपखंड (2) में दिनांक 20-11-65 की अधिसूचना सं. 7/2/63-स्था. (क) में प्रकाशित किए गए तथा तदनन्तर निर्माणाधिकृत संख्या और तारीखों को संशोधित किए गए:	1982 का. आ. 168	तारीख 23-1-82
1066 का. आ. 1149 विनांक 13-4-66 का. आ. 1596 तारीख 4-6-66 का. आ. 2007 तारीख 9-7-66 का. आ. 2648 तारीख 2-9-66 का. आ. 2854 तारीख 1-10-66	1985 अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था. (क) तारीख 5-7-85 " " 11012/5/85-स्था. (क) तारीख 29-7-85 " " 11012/6/85-स्था. (क) तारीख 6-8-85 " " 11012/12/85-स्था. (क) तारीख 6-12-85	

अधिसूचना सं० 11012/8/85-स्था. (क) तारीख
11-12-85

" " 11012/24/85-स्था. (क) तारीख
26-11-86

1987 का. आ. 830 तारीख 28-3-87

का. आ. 831 तारीख 28-3-87

का. आ. 1591 तारीख 27-6-87

का. आ. 1825 तारीख 18-7-87

1988 का. आ. 3060 तारीख 15-10-88

का. आ. 3061 तारीख 15-10-88

1989 का. आ. 2207 तारीख 16-9-89

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Deptt. of Personnel and Training)

New Delhi, the 30th March, 1990

S.O. 1084.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) (Second) Amendment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, (hereinafter referred to as the said rules), (1) in rule 29 ;

(a) in sub-rule (1), in clause (iii), for the words and brackets "Member (Personnel) Telecommunications Board", the words and brackets "Adviser (Human Resources Development), Department of Telecommunications shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the words and brackets "Member (Personnel) Telecommunications Board", the words and brackets "Adviser (Human Resources Development), Department of Telecommunications shall be substituted.

(2) in part II of the Schedule to the said rules—

(a) in columns 3 and 4 against serial numbers 9, 10 and 11 for the words "Director-General, Telecommunications", the words "Member, Telecommunications Commission" shall be substituted;

(b) In column 4 against serial Nos. and 10, for the words "Member, Posts and Telegraphs Board", the words and brackets "Adviser (Human Resources Development), Department of Telecommunications shall be substituted.

[No. 11012/13/89-Estt.(A)]

K. SARKAR, Dy. Secy.

Note.—Principal rules order published vide Notification No. 7/2/63-Estt (A) dated 20-11-65.

Subsequently amended by Notification's published in the

Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) under the following number and date :—

1966 S.O. 1149 dated 13-4-66

S.O. 1596 dated 4-6-66

S.O. No. 2007 dated 9-7-66

S.O. No. 2648 dated 2-9-66

S.O. No. 2854 dated 1-10-66

1967 S.O. No. 1282 dated 15-4-67

S.O. No. 1457 dated 29-4-67

S.O. No. 3253 dated 16-9-67

S.O. 3530 dated 7-10-67

S.O. No. 4151 dated 25-11-67

1968 S.O. No. 821 dated 9-3-68

S.O. No. 1441 dated 27-4-68

S.O. No. 1870 dated 1-6-68

S.O. No. 3423 dated 28-9-68

1969 S.O. No. 5008 dated 27-12-69

1970 S.O. No. 397 dated 7-2-70

1971 S.O. No. 35217 dated 25-9-71

S.O. No. 249 dated 1-1-72

1972 S.O. No. 990 dated 22-4-72

S.O. No. 1600 dated 1-7-72

S.O. No. 2788 dated 14-10-72

1973 S.O. 929 dated 31-3-73

1974 S.O. 1648 dated 6-7-74

1976 S.O. 2742 dated 31-7-76

S.O. 4664 dated 11-12-76

1977 S.O. 3062 dated 8-10-77

S.O. 3573 dated 26-11-77

S.O. 3574 dated 26-11-77

S.O. 3671 dated 3-12-77

1978 S.O. 2464 dated 2-9-78

S.O. 2465 dated 2-9-78

1979 S.O. 920 dated 17-2-79

1980 S.O. 1763 dated 5-7-80

1981 S.O. 264 dated 24-1-81

S.O. 2126 dated 8-8-81

S.O. 2203 dated 22-8-81

S.O. 2512 dated 3-10-81

1982 S.O. 168 dated 23-1-82

1985 Notification No. 11012/15/84-Estt(A) dated 5-7-85

No. 11012/5/85-Estt(A) dated 29-7-85

No. 11012/6/85-Estt(A) dt. 6-8-85

No. 11012/12/85-Estt(A) dated 6-12-85

No. 11012/8/85-Estt(A) dated 11-12-85

No. 11012/24/85-Estt.(A) dated 26-11-86

1987 S.O. 830 dated 28-3-87

S.O. 831 dated 28-3-87

S.O. 1591 dated 27-6-87

1988 S.O. 1825 dated 18-7-87

S.O. 3060 dated 15-10-88

S.O. 3061 dated 15-10-88

1989 S.O. 2207 dated 16-9-89.

वार्निशिंग मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1990

का.प्रा. 1085:—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट पेंट तथा सम्बद्ध उत्पादों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानक चिह्न को मान्यता देने का प्रस्ताव यह धोतन करने के प्रयोजन के लिए करती है कि जहां उक्त पेंट तथा सम्बद्ध उत्पादों में भरे ऐसे डिब्बों या पैकजों पर ऐसा चिह्न लगा कर चिपका होगा, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन उस पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुषंग समझा जाएगा ;

और केन्द्रीय सरकार ने निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के नियम (2) की अपेक्षानुसार उक्त प्रस्ताव निर्यात निरीक्षण परिपद को भेज दिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके कि उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है ।

2. यह सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की वांछा रखता है तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिपद, प्रगति टावर, (11 वीं मंजिल), 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, -110008 को भेज सकता है ।

उपाबंध

भाग-1

1. संश्लिष्ट इनेमल ।
2. उष्मारोधी वार्निश, (वायु शुष्कन बिटुमन के प्रकार)
3. संश्लिष्ट वार्निश, परिसाधन (साधारण प्रयोजन) ।
4. इमल्शन पेंट (प्लास्टिक/ऐक्रिलिक इमल्शन) ।

भाग -2

1. सभी प्रकार के तैयार मिश्रित पेंट तथा इनेमल जिनके अन्तर्गत संश्लिष्ट इनेमल के सिवाय प्राइमर पूरक, अवलेपन तथा परिसाधन हैं ।
2. संश्लिष्ट वार्निश, परिसाधन (साधारण प्रयोजन) तथा उष्मारोधी वार्निश (वायु शुष्कन, बिटुमन प्रकार के) सिवाय सभी प्रकार के वार्निश (प्राकृतिक रेजिन या संश्लिष्ट रेजिन या दोनों से बनाए गए) ।

3. प्लास्टिक तथा ऐक्रिलिक के सिवाय सभी प्रकार के इमल्शन पेंट ।
4. पूरक प्राइमर या सर्फेसर सहित, नाइट्रोसेल्युलोज लेकर, स्वच्छ या रंजक ।
5. पेस्ट पेंट तथा पेस्ट डिस्टेम्पर ।
6. शुष्क डिस्टेम्पर, चूने के रंग तथा सीमेंट रंग ।
7. सीमेंट पेंट ।
8. पेंट विरलक ।
9. पेंट के लिए संश्लिष्ट रेजिन ।
10. पेंटों के लिए संसाधित तेल और पेंटों के लिए शुष्कन या अधिशुष्कन तेल ।
11. बिटुमनी लेपन ।
12. एल्युमिनियम पेस्ट ।

फाइल सं० 6/5/85--ई आई एण्ड ई पी)

ए०के० चौधरी, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st April, 1990

S.O. 1085.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) proposes to recognise Standard Mark specified by the Bureau of Indian Standards in relation to paints and allied products as specified in the Annexure to this notification for the purpose of denoting that where the cartons or packages containing the said paints and allied products are affixed or applied with such Mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specification applicable thereto under section 6 of the said Act;

And whereas the Central Government forwarded the said proposal to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this notification in the Official Gazette to the Export Inspection Council of India, 'Pragati Tower', (11th floor), 26, Rajindra Place, New Delhi-110008.

ANNEXURE

Part I

1. Synthetic enamels.
2. Insulating varnishes (airdrying, bitumen type).
3. Synthetic varnishes, finishing (general purpose).
4. Emulsion paints. (plastic/Acrylic emulsion).

Part II

1. Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers under-coating and finishing, except synthetic enamels.

2. Varnishes of all types (prepared from natural resin or synthetic resins or both), except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).
3. Emulsion paints of all types, except plastic and acrylic.
4. Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented, including fillers, primers or surfaces.
5. Paste paints and paste distempers.
6. Dry distempers, lime colours and cement colours.
7. Cement paints.
8. Thinners for paints.
9. Synthetic resin for paints.
10. Processed oils for paints and drying or semi-drying oils for paints.
11. Bituminous coatings.
12. Aluminium paste.

[F. No. 6(5)/85 EI&EP]
A. K. CHAUDHURI, Director

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1990

का. आ. 1086. मैसर्स एम. टी. सी. मूवर्स प्रा. लि. को मुक्त विदेशी मुद्रा के अंतर्गत एक रिकन्डीशन्ड बेलोटी-बी-75 सेल्फ प्रोपेल्ड हेवी ड्यूटी पावर ट्रेन टेलिस्कोपिक बूम और स्प्रेडर सहित उनके हिस्से पुर्जा और स्पेयरस सहित (प्रम सं. 4282) के आयात के लिए रु. 17,02,800/- रुपये (सत्तरह लाख, दो हजार आठ सौ रुपये मात्र) (इटालियन लीरा 150,000,000) के लिए एक आयात लाइसेंस सं. पी/सी. जी/2125929/सी/XX/14/एच/89/सीजी-1/एम एस दिनांक 28-11-89 स्वीकृत किया गया था।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन और विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपियां जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन और विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं अथवा ग़ुम हो गई हैं। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन और विनियम नियंत्रण प्रतियां किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं की गई हैं और इस प्रकार सीमा शुल्क प्रयोजन और विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों पर अंकित मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है;

3. अपने इस तर्क के समर्थन में लाइसेंस धारी ने नोटरी पब्लिक, दिल्ली के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि मूल आयात लाइसेंस सं. सी/सीजी/2125929/सी/XX/14/एच/89/सीजी-1/एम एस दिनांक 28-11-89 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन और विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां फर्म से खो अथवा ग़ुम हो गई हैं। गमय-नमय पर यथा संशोधित 7-12-1955 के आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के प्रवर्ध 9(गग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मैसर्स एम. टी. सी. मूवर्स प्रा. लि. को 28-11-89 को जारी उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति सं. पी/सीजी/2125929 एनद्वारा रद्द की जाती है।

4. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां पार्टी को भ्रम से जारी की जा रही है।

[म. सी. जी. - 1/22 (38)/87 - 88]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 5th April, 1990

S.O. 1086.—M/s. STC Movers Pvt. Ltd. were granted an import licence No. P/CG/2125929/C/XX/14/H/89/CG. 1/ M. S. dated 28-11-89 for Rs. 17,02,800 (Rupees Seventeen Lakhs Two Thousand and Eight Hundred only) (1). Lira 150,000,000 for import of One No. Reconditioned Belotti B-75 Self propelled Heavy Duty Power Crane with Telescopic Boom and Spreader with accessories & Spares (S. No. 4228) under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs Purpose Copy and Exchange Control Copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs Purposes Copy and Exchange Control Copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs Purposes Copy and Exchange Control Copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Customs Copy & Exchange Control Copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes Copy and Exchange Control Copy of import licence No. P/CG/2125929 dated 28-11-89 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes Copy & Exchange Control Copy No. P/CG/2125929 ated 28-11-89 issued to M/s. STC Movers (P) Ltd., is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes Copy & Exchange Control Copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGI/22 (38)/87-88]

का. आ. 1087.—मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि., 14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता, को वितीय संस्थान से ऋण के अंतर्गत ग्रेफाइट हेड डोक्टोरोइस इत्यादि के आयात हेतु सं. 62,29,900/- (बासठ लाख, उन्नीस हजार नौ सौ रु. मात्र) के लिए 17-2-89 का एक आयात लाइसेंस सं. पी./सी. जी./2124599 स्वीकृत किया गया था। फर्म ने लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है। यह किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत नहीं थी और इस कारण से सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है।

2. अपने इस तर्क के अनुसमर्थन में लाइसेंसधारक ने नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेने हुए स्टाम्प पेपर

पर एक हलफनामा प्रस्तुत किया है तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि 17-2-89 के आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2124599 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति फर्म से खो गई है या ग़ुम हो गई है 17-12-1955 के यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उप धारा 9 (गग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ग्रेफाइट इंडिया लि., 14 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता को जारी किए गए 17-12-89 के आयात लाइसेंस सं. पी/सी. जी./2124599 की उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की दूसरी प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सी. जी. 3/994/19/88 - 89]

एस. पी. शर्मा, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

S.O. 1087.—M/s. Graphite India Ltd., 14, Netaji Subhash Road, Calcutta were granted an import licence No. P/CG/2124599 dated 17-2-89 for Rs. 62,29,900 (Rupees Sixty-two lakh Twenty-nine thousand and Nine hundred only) for import of Graphite Head Electrodes etc. under Loan from financial institutions. The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy of the licence. It was not registered with any Customs authority and as such the value of Customs purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public. I am accordingly satisfied that the original Customs purposes copy of import licence No. P/CG/2124599 dt. 17-2-89 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended the said original customs purposes copy No. P/CG/2124599 dt. 17-2-89 issued to M/s. Graphite India Ltd., 14, Netaji Subhash Road, Calcutta, is hereby cancelled.

3. A duplicate customs purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CG.II/994/19/88-89]

S. P. SHARMA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

लाइ एंड मार्गरेक पीरि मंत्रालय

(मार्गरेक पीरि विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1990

क्र. धा. 1038.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/ किये गये हैं।

अनुसूची

क्र. सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	गजट अधिसूचना की संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक का निर्धारण अधिसूचित हुआ था	संशोधन की संख्या और तारीख	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 326-1968 प्राकृतिक और संश्लिष्ट सुगंधित सामग्री के नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण)	एम. धो. 2330 दि. 1969-06-14	संख्या 3 जनवरी 1985	(i) (पृष्ठ 9 से 17 खंड 3 से 3.6.2) —हटाये (ii) (पृष्ठ 41 से 42, खंड 16.2 से 16.2.2) —हटाये	1985-01-31
2.	IS : 326-1968 प्राकृतिक और संश्लिष्ट सुगंधित सामग्री के नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण)	एम. धो. 2330 दि. 1969-06-14	संख्या 4 फरवरी 1985	(1) (पृष्ठ 44, खंड 16.6 से 16.6.2) हटाये	1985-02-28
3.	IS : 722 (भाग 5)-1980 बिजली के एसी मोटरों की बिजलिष्ट भाग 5 प्रति-बंधित पावर गुणक रेंज के लिए कोस्ट चंडा मोटर, वर्ग 3.5 (पहला पुनरीक्षण)	एम. धो. 1294 दि. 1983-03-30	संख्या 1 जनवरी 1985	खंड 9.15 के बाद नया खंड 9.16 जोड़ा गया है।	1985-01-31
4.	IS : 770-1977 भारतीय कोयला और लिग्नाइट का वर्गीकरण और संश्लिष्टकरण (दूसरा पुनरीक्षण)	एम. धो. 2001 दि. 1981-07-25	संख्या 1 जनवरी 1985	खंड 3.5.2 संशोधित किया गया है	1985-01-31
5.	IS : 1622-1981 पानी के नमूने लेने और सूक्ष्मजैविक जांच की पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण)	एम. धो. 3994 दि. 1985-08-24	संख्या 1 जनवरी 1985	खंड 3.2.4.3 को संशोधित किया गया है और इन खंड के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है।	1985-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. IS : 2474-1982 इम के लिए धातु स्क्वलो की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	--	संख्या 1 अप्रैल 1985	वर्तमान प्रकृति 2 को एक नई में बदल दी गई है।	1985-04-30	
7. IS : 3716-1978 बिजुल रोशन सम्बन्ध के लिए अनुप्रयोग मापदंडिका (पहला पुनरीक्षण)	--	संख्या 2 अप्रैल 1985	(i) (पृष्ठ 8, खंड 1.2, पैरि 1)--- "केनर" शब्द हटाया। (ii) खंड 1.2 के बाद नया खंड 1.3 जोड़ा गया है और बाद वाले खंड को संख्या नवतमारी दी गई है। (iii) परिशिष्ट 8 के बाद वर्तमान परिशिष्ट 9 जोड़ा गया है।	1985-04-30	
8. IS : 4003 (भाग 2)-1978 पाइप रिबों की विशिष्टि भाग 2 भारी कार्य	एस.ओ. 2216 दि. 1981-08-22	संख्या 1 अप्रैल 1985	वर्तमान प्रकृति (पृष्ठ 1, खंड 3) को नई में बदल दिया गया है।	1985-04-30	
9. IS : 4217-1981 नोडन रोवरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3992 दि. 1985-08-24	संख्या 2 फरवरी 1985	सारणी 3 को संशोधित किया गया है।	1985-02-28	
10. IS : 4561 (भाग 1)-1968 तेल के डिब्बों की विशिष्टि भाग 1 इसके कार्य के तेल के डिब्बे	एस.ओ. 2766 दि. 1968-08-10	संख्या 1 जनवरी 1985	(i) (पृष्ठ 5, प्रकृति 2, स्पेड) "0.31" के लिए "0.30" करें	1985-01-31	
11. IS : 4800 (भाग 9)-1971 इनेमलकृत गोल खरेटने के तार की विशिष्टि भाग 9 180 मापमान सूचकांक वाले तार	एस.ओ. 3255 दि. 1973-11-24	संख्या 2 अप्रैल 1985	(i) खंड 5.5.1 को एक नये खंड में बदला गया है और बाद वाले खंडों को 5.5.2 और 5.5.3 को 5.5.3 और 5.5.4 के रूप में पुनः संख्या दी गई है। (ii) वर्तमान सारणी 1.2 और 3 (पृष्ठ 6.7 और 8) को नई में बदल दिया गया है। (iii) वर्तमान खंड 5.6 और 5.7 को नये में बदल दिया गया है।	1985-04-30	
12. IS : 4800 (भाग 10)-1977 इनेमल कृत गोल खरेटने तारों की विशिष्टि भाग 10 531: बंधन-तार	एस.ओ. 2116 दि. 1980-08-09	संख्या 2 मई 1985	(i) खंड 5.5.1 को नये खंड द्वारा बदला गया है और बाद वाले खंडों को पुनः संख्या 5.5.2 और 5.5.3 को 5.5.3 और 5.5.4 दी गई है। (ii) वर्तमान सारणी 3 और 4 (पृष्ठ 9) को नये में बदला गया है। (iii) वर्तमान खंड 5.7 का नये में बदला गया है।	1985-05-31	
13. IS : 5154-1980 सीसा प्रमल ट्रेन्शन बैटरियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 4242 दि. 1984-12-08	संख्या 2 जनवरी 1985	खंड 5.2 को संशोधित किया गया है।	1985-01-31	
14. IS : 6313 (भाग 2)-1981 धक्कों में शोकरगोवा मापी की रोति संहिता, भाग 2 निर्माणपूर्व रसायन उपचार माप (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2148 दि. 1985-05-18	संख्या 1 जानवरी 1985	(i) (पृष्ठ 12, खंड 6.7, पैरि 4) "ऊर्ध्वकार" शब्द को हटाया	1985-01-31	
15. IS : 6716-1981 बैट्रीफ्र प्रमल, तक-नोकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 2147 दि. 1985-05-18	संख्या 1 जनवरी 1985	खंड 7.1 संशोधित किया गया है।	1985-01-31	
16. IS : 6848-1979 रेल गाड़ियों में प्रकाश व्यवस्था और बायानुक्लन सेवाओं के लिए सीसा-प्रमल बैटरियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 3449 दि. 1982-10-31	संख्या 1 अप्रैल 1985	(i) (पृष्ठ 5, सारणी 1, क्रम संख्या 7) इसके सामने की सभी प्रविष्टियों को हटाया। (ii) (पृष्ठ 8, प्रकृति 2, टिप्पणी 1) 0.025 मिमी. को 0.01 मिमी. में बदला जाये।	1985-04-30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(iii) खंड 5.1.2 और 5.9.8 को नये से बदला गया है।	
				(iv) खंड 5.1.1.2 के बाद नया खंड 5.1.1.3 जोड़ा गया है।	
				(v) खंड 5.2 को संशोधित किया गया है।	
				(vi) परिशिष्ट डी (पृष्ठ 21) में टाइप परीक्षण के क्रम के बाद एक टिप्पणी जोड़ी गई है।	
				(vii) परिशिष्ट "क" के बाद नया परिशिष्ट "जो" जोड़ा गया है।	
17. IS : 7513-1974 पत्र-वाक्य संज्ञक के लिए प्राकृतिक संज्ञक	एस.ओ. 1092 दि. 1977-04-09	संख्या 1 जुलाई 1935		(i) 3.1.2.5, 4.2.2.7, 4.2.3.5, 4.4.7, 6.2.4.1 सी और 7.1.2.1 संशोधित किए गए हैं।	1985-07-01
				(ii) (पृष्ठ 7, खंड 3.7, "समन्वय" "संकेत" के अंतर्गत) द्रव्यमानों से "वर्तमान" के लिए संकेत हटा दें।	
				(iii) (पृष्ठ 15, खंड 5.1.1.4) इसके सामने वाली सभी प्रविष्टियाँ हटा दें।	
				(iv) खंड 9 को संशोधित किया गया है।	
				(v) खंड 8.3.2 के बाद टाइप-समक टिप्पणी जोड़ी गई है।	
18. IS : 7967-1976 समुद्री मटीय क्षेत्रों के प्रदूषण नियंत्रण करने की कमीटी	एस.ओ. 1598 दि. 1979-05-19	संख्या 1 जनवरी 1985		सारणी 1 संशोधित की गई है और सारणी के अंत में एक टिप्पणी जोड़ी गई है।	1985-01-51
19. IS : 8122 (भाग 1)-1976 कम्पाइन कटार गहवाई संकेत की परीक्षण संहिता, भाग 1 पारिभाषिक शब्दावली।	एस.ओ. 1822 दि. 1979-11-24	संख्या 2 फरवरी 1985		खंड 4.2.2.3 को एक नये में बदल दिया गया है।	1985-02-26
20. IS : 8190 (भाग II)-1980 कीटनाशक की पैकिंग की विशेषताएं, भाग II तरल कीटनाशक (पहला पुनरीक्षण)	एस.ओ. 4242 दि. 1984-12-08	संख्या 2 मई 1985		सारणी 1 और 2 संशोधित की गई हैं।	1985-05-01
21. IS : 8190 (भाग 4)-1979 कीटनाशक की पैकिंग की विशेषताएं, भाग 4 धूमक	एस.ओ. 2503 दि. 1982-07-17	संख्या 1 फरवरी 1985		वर्तमान सारणी 1 को नई सारणी में बदला गया है।	1985-05-11
22. IS : 8261 (भाग 1)-1976 पिन और तार की विशिष्ट कंसाल, ट्रेक्शन, भाग 1 निर्णय तार	एस.ओ. 97 दि. 1980-06-12	संख्या 1 मार्च		संकेत खंड 3 में 1 ; 2 तक नये में बदल दिये गये हैं।	1985-04-00
23. IS : 8261 (भाग 2) पिन और तार की विशिष्ट कंसाल, ट्रेक्शन, भाग 2 मार्गशिका तार	--संशोधित--	संख्या 1 मार्च 1985		(पृष्ठ 1, खंड 3)--वर्तमान खंड 3 और इसके उपखंडों को हटाये और निम्नलिखित में बदले : "3 संशोधित यह IS : 8261 (भाग 4 1985 पिन और तार, कंसाल, ट्रेक्शन भाग 4 सामग्रिया और यांत्रिक विशेषताओं के अनुसार हो।	1985-04-00
24. IS : 8261 (भाग 1)-1976 पिन और तार की विशिष्ट कंसाल, ट्रेक्शन, भाग 3 पिन और तार, अड़ना और बुझादार	--संशोधित--	संख्या 1 मार्च 1985		--संशोधित--	1985-04-00
25. IS : 8313-1977 स्थापन नोडन 7/24 स्थापन नोडन स्टैमिनीय और नोडन की विशिष्ट	एस.ओ. 1171 दि. 1980-11-15	संख्या 1 मार्च 1985		खंड 3 के बाद विशेषता स्थापन नोडन के नोडन जोड़े गए हैं।	1985-08-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	IS : 8693-1978 नट पिरोडियोमीटर की विशिष्टि	एस.ओ. 3408 दि. 1980-12-13	संख्या 1 मई 1985	खंड 2 1, 6, 1.5 और 8 1.2 (बी) संशोधित किए गए हैं।	1985-05-11
27	IS : 8963-1978 कनोस्पाइरोफोन तकनीकी की विशिष्टि	एस.ओ. 2274 दि. 1981-08-29	संख्या 1 फरवरी 1985	(i) (पृष्ठ 4, सारणी 1, खंड 5. मध्य शीर्षक) IS : 6940-1973 को IS : 6940-1982* करें। (ii) सारणी 1 (पृष्ठ 4 पर) *अंकित पादटिप्पणी को एक नई में बदल दिया गया है। (iii) टिप्पणी सहित खंड 3.1 और 4.1 नये बदल दिये गये हैं। (iv) (पृष्ठ 4 पर) *अंकित पादटिप्पणी नई में बदल दी गई है। (v) (पृष्ठ 5) *अंकित पादटिप्पणी नई में बदल दी गई है। (vi) खंड ए-3, 4, 1 को संशोधित किया गया है।	1985-02-28
28	IS : 9178 (भाग 1)-1979 खुली बल्क सामग्रियों के भंडारण के लिए इस्पात के डिब्बे के डिजाइन की कमीटी, भाग 1 भार की सामान्य अपेक्षाएं और मूल्यांकन	एस.ओ. 358 दि. 1983-01-15	संख्या 1 फरवरी 1985	खंड 6, 2, 1.2 के वर्तमान सूत्र को नए में बदल दिया गया है।	1985-02-28
29	IS : 9299 (भाग 3/खंड 3)-1982 निर्मित अश्वक अथवा उपकारित अश्वक कागज पर आधारित विद्युत् रोधन सामग्रियों की विशिष्टि, भाग 2 अलग-अलग सामग्रियों की विशिष्टि खंड 3 विद्युत् मशीनों के विद्युत् रोधन के लिए नम्य अश्वक फ्लेक टेप	एस.ओ. 3103 दि. 1986-09-13	संख्या 1 अप्रैल 1985	वर्तमान सारणी 5 (पृष्ठ 9) नई में बदल दी गई है।	1985-04-30
30	IS : 9553-1980 एनाक्थोर, तकनीकी को विशिष्टि	एस.ओ. 219 दि. 1984-01-21	संख्या 1 अप्रैल 1985	(i) (पृष्ठ 4, सारणी 1)-IS : 6940-1973* को IS : 6940-1982-करें। (ii) *अंकित (पृष्ठ 4) वर्तमान पादटिप्पणी नई में बदल दी। (iii) इसके टिप्पणी सहित खंड 4 और और क-1, 5 नई में बदल दिए गए।	1985-04-30
31	IS : 9428-1980 पूर्वनिर्मित कैल्शियम मिलिकेट विद्युत्-रोकेन (9500 से. तापमान तक) की विशिष्टि	एस.ओ. 5611 दि. 1985-09-24	संख्या 1 फरवरी 1985	खंड 1.8.2 (सी) और 2.8.2.1 संशोधित किए गए हैं।	1985-02-28
32	IS : 9875-1981 लिपिस्टिक की विशिष्टि	एस.ओ. 1013 दि. 1985-02-09	संख्या 1 फरवरी 1985	(पृष्ठ 6, खंड 4.2 और 4.3)-हटाये	1985-02-28
33	IS : 9999-1981 खानों में उपयोग के लिए बीजल रेसनाशी इंजनों की विशिष्टि	एस.ओ. 3998 दि. 1985-08-24	संख्या 1 जुलाई 1985	(i) सारणी 1 (पृष्ठ 1) और 2 (पृष्ठ 2) संशोधित किए गए हैं। (ii) खंड 7.5.1, 7.7.2 1, 7.7.5.1, 7.7.6.2, 7.10.4.1 और 7.11.2 नये खंडों से बदल दिए हैं। (iii) खंड 7.7.8.1 और 7.9 संशोधित किए गए हैं। (iv) नया खंड 7.7.11 के 7.7.10 के बाद जोड़ा गया है।	1985-07-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. IS : 10109-1981 तेल दाब स्टोक, एस.ओ. 2147 ऑफसेट बनेर वाले की विशिष्टि	दिनांक 1985-05-18	संख्या 1 फरवरी 1985	खंड 11.2 संशोधित किया गया है।		1985-02-28
35. IS : 10119-1982 स्टाट अनुप्रयोग के लिए उपयोग के लिए तैयार कीटनाशक की विशिष्टि	एस.ओ. 3998 दिनांक 1985-08-24	संख्या 1 जनवरी 1985	(i) खंड 3.1 और 4.1 हमकी टिप्पणी सहित नये में बदले गए हैं। (ii) (पृष्ठ 4)** अंकित वर्तमान पाद- टिप्पणी '*' और (पृष्ठ 5) + अंकित नई में बदल दी गई है। (iii) खंड 5.2 संशोधित किया गया है।		1985-01-31
36. IS : 10143-1982 वायवीय तरल- पावर मिलिटरों-एक राइ बियोज्य माउंटिंग 10 बार सीरीज और 32 मिमी से 320 मिमी के लिए माउंटिंग आयामों की विशिष्टि	एस.ओ. 3992 दिनांक 1985-08-24	संख्या 1 अप्रैल 1985	सारणी 1, 3 और 4 संशोधित किए गए हैं।		1985-04-30

इन भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग और क्षेत्रीय कार्यालयों: बम्बई, कलकत्ता, चेन्नै और मद्रास तथा
इसके जवाब कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में विक्री के लिए उपलब्ध है।

[सं. सी.एमडी./13:5]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 6th March, 1990

S.O.1088.—In pursuance of clause (b) of Sub Rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued.

SCHEDULE

Sl. No. and title of the No. Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the estab- lishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the amendment	Brief Particulars of the Amendment	Date from which the Amend- ment shall have effect
1	2	3	4	5
1. IS : 326—1968 Methods of sampling and test for natural and synthetic perfu- mery materials (first revision)	S.O. 2330 dated 1969-06-14	No. 3 Jan 1985	(i) Pages 9 to 17, clauses 3 to 3.6.2)—Delete. (ii) (Pages 41 to 42, clauses 16.2 to 16.2.2)—Delete	1985-01-3
2. IS : 326—1968 Methods of sampling and test for natural and synthetic perfu- mery materials (first revision)	-do-	No. 4 Feb. 1985	(i) (Pages 44, clauses 16.6 to 16.6.2)—Delete.	1985-02-28

1	2	3	4	5	6
3.	IS : 722 (Part 5)—1980 Specification for AC electricity meters; Part 5 Volt-ampere hour meters for restricted power factor range, class 3.5 (first revision)	S.O. 1294 dated 1985-03-30	No. 1 Jan 1985	New clause 9.16 has been added after clause 9.15	1985-01-31
4.	IS : 770—1977 Classification and condication of Indian coals and lignites (second revision)	S.O. 2001 dated 1981-07-25	No. 1 Jan. 1985	Clause 3.5.2 has been amended	1985-01-31
5.	IS : 1622—1981 Methods of sampling and microbiological examination of water (first revision)	S.O. 3994 dated 1985-08-24	No. 1 Jan 1985	Clause 3.2.4.3 has been amended and a new note has been added after this clause.	1985-01-31
6.	IS : 2474—1982 Specification for metal closures for drums (first revision)	—	No. 1 April 1985	Existing fig. 2 has been substituted by a new one	1985-04-30
7.	IS : 3716—1978 Application guide for insulation Co-ordina- tion (first revision)	—	No. 2 April 1985	(i) (Page 8, clause 1.2, line 1)—Delete the word 'only'. (ii) New clause 1.3 has been added after clause 1.2 and the subsequent clause renumbered (iii) Existing Appendix 'F' has been added after Appendix 'E'	1985-04-30
8.	IS : 4003 (Part II)— 1978 Specification for pipe wrenches Part II heavy duty	S.O. 2216 dated 1981-08-22	No. 1 April 1985	Existing figure (Page 1, clause 3) has been substituted by bu a new one	1985-04-30
9.	IS : 4217-1981 Specification for needle rollers (first revision)	S.O. 3992 dated 1985-08-24	No. 2 Feb. 1985	Table 3 has been amended	1985-02-28
10.	IS: 4561 (Part I)- 1968 Specification for oil cans; part 1 light duty oil cans.	S.O. 2766 dated 1968-08-10	No. 1 Jan 1985	(i) (Page 5, Fig. 2, Spout) Substitute '0.30' for '0.31'.	1985-01-31

1	2	3	4	5	6
11.	IS : 4800 (Part IX)-1971 Specification for enamelled round winding wires; part IX wires with temperature index 180	S.O. 3255 dated 1973-11-24	No. 2 April 1985	(i) Clause 5.5.1 has been substituted by a new one and subsequent clauses renumbered 5.5.2 and 3 '5.5.3.' as '5.5.3' and '5.5.4' respectively (ii) Existing Tables 1,2 and 3 (pages 6, 7, and 8. have been substituted by new ones. (iii) Existing clauses 5.6 and 5.7 have been substituted by new ones.	1985-04-30
12.	IS: 4800 (Part X)- 1977 Specification for enamelled round winding wires Part X self bonding wires	S.O. 2116 dated 1980-08-09	No. 2 May 1985	(i) Clause 5.5.1 has been substituted by a new one and subsequent clauses renumbered as clauses '5.5.2' and '5.5.3' as '5.5.3' and '5.5.4' respectively. (ii) Existing Tables 3 and 4 (page 9) have been substituted by new ones (iii) Existing clauses 5.7 has been substituted by a new one.	1985-05-31
13.	IS: 5154-1980 Specification for lead-acid traction batteries (first revision)	S.O. 4242 dated 1984-12-08	No. 2 Jan. 1985	Clause 5.2 has been amended	1985-01-31
14.	IS: 6313 (Part 2)-1981 Code of practice for antitermite measures in buildings; Part 2 Pre-constructional chemical treatment measures (first revision)	S.O. 2148 dated 1985-05-18	Not. 1 Jan. 1985	(i) (Page 12, clause 6.7 line 4) Delete the word 'Vertical'	1985-01-31
15.	IS: 6716-1981 Specification for benzoic acid, technical (first revision)	S.O. 2147 dated 1985-05-18	No. 1 Jan. 1985	Clause A-7.1 has been amended	1985-01-31
16.	IS: 6848-1979 Specification for lead-acid batteries for train lighting and air-conditioning services (first revision)	S.O. 3449 dated 1982-10-31	No. 1 April 1985	(i) (Page 5, Table 1, S.No. 7) Delete together with all entries against it. (ii) (Page 8, Fig. 2, Note 1) Substitute the '0.01 mm' for '0.025 mm'. (iii) Clauses 5.1.2 and 5.9.8 have been substituted by new ones.	1985-04-30

1	2	3	4	5	6
				(iv) New clause 5.1.3 has been added after clause 5.1.2	
				(v) Clause 5.2 has been amended	
				(vi) A Note has been added after sequence of type test in Appendix D	
				(Page 21)	
				(vii) New Appendix 'G' has been added after Appendix 'F'	
17. IS: 7513-1974 Graphical symbols for fluid power systems	S.O. 1092 dated 1977 04 09	No. 1 Jul. 1985		(i) Clauses 2.1.2.5, 4.2.2.7, 4.2.3.5 4.4.7, 6.2.4.1.c and 7.1.2.1 have been amended.	1985-07-31
				(ii) (Page 7, Clause 3.7, under column 'Symbol')- Delete the symbol for 'hydraulic to pneumatic.	
				(iii) (Page 15, clause 5.3.1.4) Delete along with all the entries against it.	
				(iv) Clause 8 has been amended.	
				(v) Explanatory Note has been added after clause 8.3.2	
18. IS: 7967-1976 Criteria for controlling pollution of marine coastal areas.	S.O. 1598 dated 1979-05-19	No. 1 Jan. 1985		Table 1 has been amended & a note has been added at the end of the Table.	1985-01-31
19. IS: 8122 (Part I)-1976 Test code for combine harvester-thresher Part I terminology	S.O. 3822 dated 1979-11-24	No.2 Feb. 1985		Clause 4.2.2.3 has been substituted by a new one	1985-02-28
20. IS: 8190 (Part II)-1980 Requirements for packing of pesticides Part II liquid pesticides (first revision)	S.O. 4242 dated 1984 12 08	No. 2 May 1985		Table 1 and 2 have been amended	1985-05-31
21. IS: 8190 (Part IV)-1979 Requirements for packing of pesticides Part IV fumigants	S.O. 2508 dated 1982 07 17	No. 1 Feb. 1985		Existing Table 1 has been substituted by a new one	1985-05-31
22. IS: 8261 (Part I)-1976 Specification for pins and wires, skeletal traction, Part I kirschner wires	S.O. 97 dated 1980 06 12	No. 1 April		Existing clauses 3 to 3.3.3 have been substituted by ones.	1985-04-30

1	2	3	4	5	6
23.	IS: 8261 (Part 2)—1976 Specification for pins and wires, Skeletal, traction; Part 2 guide wires	S.O. 97 dated 1980 06 12	No. 1 April 1985	(Page 1, clause 3)—Delete the existing clause 3 and its sub-clauses and substitute the following : '3. Material—Shall be in accordance with IS: 8261 (Part 4)—1985 Specification for pins and wires, skeletal, traction: Part 4 Materials and mechanical requirements'.	1985-04-30
24.	IS: 8261 (Part 3)- 1976 Specification for pins and wires, skeletal, traction Part 3 pins and wires, fixation and threaded	-do-	No. 1 April 1985	-do-	1985-04-30
25.	IS: 8615-1977 Specification for stub milling arbors with self- release 7/24 taper	S.O. 3171 dated 1980 11 15	No. 1 Aug. 1985	Details of detachable driving tenon has been added after clause 3	1985-08-31
26.	IS: 8693-1978 Specification for net pyrradiometer	S.O. 3408 dated 1980 12 13	No. 1 May 1985	Clauses 2.1, 6.1.5 and 8.1.2 (b) have been amended	1985-05-31
27.	IS: 8963-1978 Specification for chlorpyrifos, technical	S.O. 2274 dated 1981 08 29	No. 1 Feb. 1985	(i) (Page 4, Table 1, col 5, heading) Substitute IS : 6940-1982* for IS: 6940-1973*. (ii) Table 1 (at page 4), foot- note with '*' mark has been substituted by a new one (iii) Clauses 3.1 and 4.1 with note have been sub- stituted by a new ones (iv) Foot-note with '*' mark (at page 4) has been sub- stituted by a new one (v) Foot-note with '*' mark (Page 5) has been sub- stituted by a new one (vi) Clause A-3.4.1 has been amended.	1985-02-28

1	2	3	4	5	6
28.	IS: 9178 (Part 1)-1979 Criteria for design of steel bins for storage of bulk materials Part 1 General requirements and assessment of loads.	S.O. 358 dated 1983 01 15	No. 1 Feb. 1985	Existing formula of clause 6.2.1.2 has been substituted by a new one	1985-02-28
29.	IS: 9299 (Part III)/(Sec. 3)-1982 Specification for insulating materials based on built-up mica or treated mica paper; Part III Specification for individual materials Sec. 3 Flexible mica flake tape for insulation of electrical Machines.	S.O. 3103 dated 1986 09 13	No. 1 April 1985	Existing Table 5 (page 9) has been substituted by a new one.	1985 -04-30
30.	IS: 9353 -1983 Specification for alachlor, technical	S.O. 219 dated 1984 01 21	No. 1 April 1985	(i) (Page 4, Table 1) - Substitute 'IS: 6940-1982*' for 'IS: 6940-1973*'. (ii) Existing foot-note with '**' mark (page 4) has been substituted by a new one. (iii) Clause 4.1 with its note, and A-1.5 have been sub- stituted by new ones.	1985-04-30
31.	IS: 9428-1980 Specification for preformed calcium silicate insulation (for temperature up to 95° C)	S.O. 3611 dated 1983 09 24	No. 1 Feb. 1985	Clauses 3.8.2 (C) and 3.8.2.1 have been amended	1985-02-28
32.	IS: 9875-1981 Specification for lipstick	S.O. 1013 dated 1985 03 09	No. 1 Feb. 1985	(Page 6, clauses 4.2 and 4.3) Delete.	1985-02-28
33.	IS: 9999-1981 Specification for diesel locomotives for use in mines..	S.O. 3998 dated 1985 08 24	No. 1 Jul. 1985	(i) Table 1 (Page 1) and 2 (Page 2) have been amended. (ii) Clauses 7.5.1, 7.7.2.1., 7.7.5.1, 7.7.6.2, 7.10.4.1. and 7.11.2. have been substituted by new ones.	1985-07-31

1	2	3	4	5	6
				(iii) Clause 7.7.8.1. and 7.9 have been amended	
				(iv) New clause 7.7.11 has been added after clause 7.7.10	
34.	IS: 10109-1981 Specification for oil pressure stoves. offset burner type	S.O. 2147 dated 1985 05 18	No. 1 Feb. 1985	Clause 11.2 has been amended	1985-02-28
35.	IS: 10119-1982 Specification for ready-to-use insecticides for spot application	S.O. 3998 dated 1985 08 24	No. 1 Jan. 1985	(i) Clauses 3.1 and 4.1 with its Note has been substituted by new ones. (ii) Existing foot-notes with '***' Mark (page 4), with '**' and with '*' marks (page 5) have been substituted by new ones (iii) Clause 5.2 has been amended.	1985-01-31
36.	IS: 10143-1982 Mounting dimensions for pneumatic fluid power cylinders, single rod-detachable mounting 10 bar series bore 32 mm to 320 mm	S.O. 3992 dated 1985 08 24	No. 1 April 1985	Table 1, 3 and 4 have been amended.	1985-04-30

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, 9 Bahadur Shah Zafar Marg and Regional Offices Bombay, Calcutta, Chandigarh, and Madras and also from its Branch Offices—Ahmdabad, Bangalore, Bhopal, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivendrum.

[No. CMD/13 :5]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1990

का.अ. 1089.--भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एनई-द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों की मूल्यांकन फीस अधिमुक्ति करण है।

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	इकाई	प्रति इकाई नुह्रांकन फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एक्स्प्लेन्ड सीमेंट दाब पाइप	IS: 1592-1980	1 मीटर	1. रु. 2.00 प्रति इकाई पहला 3000 इकाइयों के लिए, और 2. रु. 1.00 प्रति इकाई 3001 वी और अधिक के लिए टिप्पणी: मूल्यांकन शुल्क की दर में निम्न परिवर्तन किया गया है : जो दिनांक 1989-02-01 से लागू होगा :	1983-05-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				1. रु. 4.00 प्रति इकाई पहली 3000 इकाइयों के लिए, और	
				2. रु. 2.00 प्रति इकाई 3001 और अधिक के लिए	
				(इकाई-1 मो.)-IS : 1592-1984	
2. हल्क जालित जंजीर चिरनी ब्लक	IS : 3832-1971	एक जंजीर चिरनी ब्लक		1. रु. 5.00 प्रति इकाई पहली 1000 इकाइयों के लिए, और	1984-02-01
				2. रु. 2.50 प्रति इकाई 1001 और अधिक के लिए।	
				टिप्पणी: मुहरांकन शुल्क की दर में निम्न परिवर्तन किया गया है, जो दिनांक 1989-07-01 से लागू होगा :	
				1. रु. 7.50 प्रति इकाई पहली 1000 इकाइयों के लिए, और	
				2. रु. 5.00 प्रति इकाई 1001 और अधिक के लिए	
				(इकाई-1 चिरनी ब्लक)--	
				IS : 3832-1986	
3. ब्राय ग्रेड, सोडियम का कार्बोसो मिथाइल सैल्फोनेट	IS : 5306-1978	एक कि.ग्रा.		20पैसे	1987-09-16
4. ब्राय ग्रेड, एस्कारिक अम्ल	IS : 5341-1969	~वही~		1. 30 पैसे प्रति इकाई पहली 100000 इकाइयों के लिए	1987-12-01
				2. 15 पैसे प्रति इकाई 100001 और अधिक के लिए	
				टिप्पणी: मुहरांकन शुल्क की दर में निम्न परिवर्तन किया गया है, जो दिनांक 1989-06-01 से लागू होगा :	
				30पैसे प्रति इकाई	
				(इकाई-एक कि.ग्रा.)	
5. ब्राय ग्रेड, सोडियम क्रोमेट	IS : 6507-1982	एक टन		1. रु. 10.00 प्रति इकाई पहली 500 इकाइयों के लिए और	1988-12-01
				रु. 7.50 प्रति इकाई 501 और अधिक के लिए	
				टिप्पणी: मुहरांकन शुल्क की दर में निम्न परिवर्तन किया गया है, जो दिनांक 1989-07-01 से लागू होगा :	
				रु. 10.00 प्रति इकाई	
				(इकाई-एक टन)	
6. ब्राय ग्रेड, फ्लूवोरिक अम्ल	IS : 6793-1972	एक कि.ग्रा.		1. 4 पैसे प्रति इकाई पहली 100000 इकाइयों के लिए और	1980-04-01
				2. 2 पैसे प्रति इकाई 100001 और अधिक के लिए।	
				टिप्पणी: मुहरांकन शुल्क की दर में निम्न परिवर्तन किया गया है, जो दिनांक 1989-06-01 से लागू होगा :	
				5 पैसे प्रति इकाई	
				(इकाई-एक कि.ग्रा.)	
7. एस्केटम सॉलेंट वायु पदार्थ (हल्की ब्लूटी)	IS : 9627-1980	एक टन		1. रु. 2.00 प्रति इकाई पहली 3000 इकाइयों के लिए, और	1983-07-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. रु. 1.00 प्रति इकाई 3001 और अधिक के लिए टिप्पणी :—मूहरणक शुल्क की दर में निम्न परिवर्तन किया गया है, जो दिनांक 1989-02-01 से लागू होगा : 1. रु. 4.00 प्रति इकाई पहली 3000 इकाइयों के लिए, और 2. रु. 2.00 प्रति इकाई 3001 और अधिक के लिए (इकाई—1 बी टन)	
8. बी और खाद्य तेलों के लिए डिब्बा 5 कि. ग्रा. के केवल गोल डिब्बे	IS : 10339-1982	एक डिब्बा		1. 1 पैसा प्रति इकाई पहली 1000000 इकाइयों के लिए, और 2. 1/2 पैसा प्रति इकाई 1000001 और अधिक के लिए टिप्पणी :—मूहरणक शुल्क की दर में निम्न 1 परिवर्तन किया गया है जो दिनांक अगस्त 1988 से लागू होगा : रु. 0.01 प्रति इकाई (इकाई : एक टन)	1988-04-01
9. मोटर वाहनों के लिए हुआ भरे टायर—या छोटे टायर विकल्प प्लाई	IS : 10914 (भाग 3)-1985	एक टायर	रु. 1.00		1989-01-16
10. 53 पेज साधारण पोर्टेलेण्ड सीमेंट	IS : 12269-1987	एक टन	40 पैसे		1989-01-01

[सं. सी.एम.जी/ 13:10]

New Delhi, the 13th March, 1990

S.O. 1089 :—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies the marking fee(s) for the products given in the schedule:

SCHEDULE

S. No.	Product/Class of product	No. and year of Indian Standard	Unit	Marking fee per unit	Date of Effect
1	2	3	4	5	6
1.	Asbestos cement pressure pipes	IS : 1592-1980	1 MT	(i) Rs. 2.00 per unit for the first 3000 units and (ii) Re. 1.00 per unit for the 3001 st unit and above Note: Rate of Marking Fee has since been revised as under with effect from 1989-02-01 : (1) Rs. 4.00 per unit for the first 3000 units and (2) Rs. 2.00 per unit for the 3001st unit and above. (Unit-1 MT)-IS: 1592-1984	1983-05-16

1	2	3	3	5	6
2. Hand-operated chain pulley blocks	IS: 3832-1971	One Chain-pulley block	(i) Rs. 5.00 per unit for the first 1000 units and (ii) Rs. 2.50 per unit for the 1001 st unit and above. Note: Rate of Marking Fee has since been revised as under with effect from 1989-07-01 : (i) Rs. 7.50 per unit for the first 1000 units and (ii) Rs. 5.00 per unit for the 1001st unit and above. (Unit-1 Pulley block)-IS : 3832-1986	1984-02-01	
3. Sodium carboxymethyl cellulose, food grade	IS : 5306-1978	One Kg	20 Paise	1987-09-16	
4. Ascorbic acid, food grade	IS: 5342-1969	One Kg	(i) 30 paise per unit for the first 100000 units and (ii) 15 paise per unit for the 100001st unit and above. Note: Rate of marking fee has since been revised as under with effect from 1989-06-01 : 30 paise per unit (unit-One Kg)	1987-12-01	
5. Sodium chromate, technical	IS : 6507-1982	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units and (ii) Rs. 7.50 per unit for the 501st unit and above. Note: Rate of marking fee has since been revised as under with effect from 1989-07-01 : Rs. 10.00 per unit (Unit-One Tonne)	1988-12-01	
6. Fumaric acid, food grade	IS : 6793-1972	One Kg	(i) 4 Paise per unit for the first 100000 units and (ii) 2 Paise per unit for the 100001st unit and above. Note: Rate of Marking fee has since been revised with effect from 1989-06-01 : 5 Paise per unit (Unit - One Kg)	1980-04-01	
7. Asbestos cement pressure pipe (light duty)	IS : 9627-1980	One Tonne	(i) Rs. 2.00 per unit for the first 3000 units and (ii) Rs. 1.00 per unit for the 3001st unit and above.	1983-07-1	

1	2	3	4	5	6
<p>Note: Rate of Marking fee has since been revised as under with effect from 1989-02-01 :</p> <p>(i) Rs. 4.00 per unit for the first 3000 units and</p> <p>(ii) Rs. 2.00 per unit for the 3001 st unit and above. (Unit-1 MT)</p>					
8. Ghee and edible oils tins, 5-kg round tin only	IS : 10339-1982	One Tin	(i) 1 Paisa per unit for the first 1000000 units and	1986-04-01	
			(ii) 1/2 Paisa per unit for the 100000 1st unit and above.		
9. Pneumatic tyres for automotive vehicles: Passenger car tyres-Diagonal ply	IS : 10914 (Part 3)-1985	One Tyre	Note: The rate of marking fee has since been revised as under with effect from 1 August 1988 : Rs. 0.01 per unit (Unit: One Tin)		
10. 53 grade ordinary portland cement.	IS : 12269-1987	One Tonne	40 Paise	1989-01-01	

[No. CMD/13 : 10]

क.प्र. 1090.-भारतीय मानक बोर्डो द्वारा अधिसूचित किया है कि निम्नलिखित उत्पादों के सम्बन्धित जो त्रुटिकर फंस अनुसूची के स्तम्भ (7) अथवा (8) में वर्गीकृत हैं, और जिन्हें पहले भारत के राजस्व भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) में अधिसूचित किया गया था, उनमें अनुसूची के स्तम्भ (4), (5) और (6) के अनुसार संशोधन किया गया है।

अनुसूची

क्र.सं. सं.	उत्पाद	भारतीय मानक की संख्या तथा वर्ष	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)
1. लवण से स्नेज बड़े स्टोन मेयर पाइप और फिटिंग		IS : 651-1980	एक टन
2. हाकी		IS : 829-1978	एक हाकी
3. गरबर विधि द्वारा शुद्ध बत्ता के निर्धारण हेतु उपकरण : खंड 2 लोक स्टापर		IS : 1223-1982	100 नम
4. अपकेन्द्रक खंड 6		-वही-	एक अपकेन्द्रक
5. कुक्कुट आहार		IS : 1374-1979	एक टन
6. बाँसों का गज		IS : 1397-1967	-वही-
7. जल, गैस और सीवेज हेतु डलवां लोहे के बाब पाइप		IS : 1537-1976	एक टन
8. ब्यूरेट		IS : 1997-1982	एक ब्यूरेट
9. स्विचरीकृत हाइड्रोजन-पर-आक्साइड		IS : 2080-1980	एक कि. ग्रा.
10. मिरोपरि बिजली की लाइनों के लिए नलिकाकार इस्पात के खम्भे		IS : 2713 (भाग 1 से 3)-1980	एक खंभा
11. फायरवोर्ड के बक्से		IS : 2771 (भाग 1)-1977	एक टन
12. मस्क एम्बेट		IS : 3131-1986	एक कि. ग्रा.
13. मस्क आइलाल		IS : 3145-1986	एक कि. ग्रा.

(1)	(2)	(3)	(4)
14. विशेष प्रयोजनों हेतु अधीन स्वकीय सिरिज		IS : 3237-1980	100 सिरिज
15. शक्तिज बेल्त-कार और शक्तिज प्रयत्नाकार लुंडी बाले निर्जर्मक (स्टेडिअर), दाया		IS : 3829 (भाग 1)-1978	एक स्टैण्डर्ड
16. शक्तिज बेल्त-कार और उच्च गति वाली बाले निर्जर्मक, दाया टाइप		IS : 3829 (भाग 2)-1988	एक निर्जर्मक
17. सौन्दर्य प्रसाधन उद्योग हेतु सारबिटाज (70 प्रतिमान)		IS : 3987-1983	एक टन
18. कृषि जुताई के चक्के, प्रयत्न टाइप		IS : 4366 (भाग 1)-1985	एक चक्का
19. अभियन्त हेतु यांत्रिक सामान उत्पन्न करने हेतु सामान सान्द्र (यांत्रिक), प्रोटोन भाग		IS : 4989 (भाग 1)-1985	एक सिटर
20. अभियन्त हेतु यांत्रिक सामान उत्पन्न करने हेतु सामान सान्द्र (यांत्रिक), जल-चक्रिय		IS : 4989 (भाग 2)-1984	एक सिटर
21. वनस्पति विस्थापन टाइप बायु संयोजकों और निष्कासकों की रीति संज्ञिका		IS : 5456-1985	एक संयोजक
22. हस्तचालित यूक्लेन गीयर रजित खिंचने और उठाने की मशीन		IS : 5604-1984	एक मशीन
23. फर्श की लेवी पालिश		IS : 8541-1977	10 कि. ग्रा.

सूचकांक फीस की दर		भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना का संवर्ध		भारत के राजपत्र के जारी होने की तारीख	नापूरी होने की तिथि
प्रति इकाई	इकाइयों के लिए	जिसमें प्राथमिक रूप से अधिष्ठापित किया गया था का. प्रा. सं. और दिनांक	जिसे प्राथमिक रूप से संशोधित किया गया था का. प्रा. सं. तथा दि. तथा दि.		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.00	सभी	--	1274 1984-04-12	1984-04-21	1989-08-01
0.10	सभी	--	2363 1983-04-28	1983-05-25	1990-01-01
0.20	सभी	--	1015 1988-01-20	1988-04-02	1989-08-01
0.75	सभी	--	-वही-	-वही-	-वही-
3.00 पहली	3000	--	2108	1983-05-14	1989-07-01
10.00	सभी	--	--	--	1989-08-02
4.00 पहली 1500		--	1482	1984-05-03	1989-07-01
2.00 शेष			1984-03-03		
1.50 शेष			1983-04-14		
2.00 शेष			1984-03-30		
0.25	सभी	--	--	--	-वही-
0.05	सभी	2587 1989-09-12	--	1989-10-14	-वही-
1.00	सभी	653 1977-02-01	--	1977-02-26	1989-10-01
5.00	सभी	1505 1977-04-28	--	1977-05-21	1989-07-01
0.40	सभी	--	220 1983-12-27	1984-01-21	1989-12-01
0.10	सभी	--	220 1983-12-27	1984-01-21	1989-12-01
3.00	सभी	--	4199 1983-10-26	1983-11-19	1990-01-01
50.00	सभी	--	1015 1988-01-26	1983-04-02	-वही-

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50.00	सर्वा	--	--	--	1990-01-01
25.00	सर्वा	--	3972	1979-12-08	1989-12-01
			1979-11-20		
0.30	सर्वा	--	2005	1974-08-10	1989-11-01
			1974-07-10		
0.06 पट्टी	100000	2545	--	1977-08-13	1989-10-01
0.04 शेव		1977-07-20			
0.12 पट्टी	100000	--	--	--	1989-10-01
0.08 शेव					
15.00 पट्टी	1000	--	1998	1984-06-23	1989-10-01
10.00 शेव			1984-05-10		
7.50 पट्टी	1000	--	1354	1972-06-24	1989-07-01
5.00 शेव			1972-04-21		
0.75	सर्वा	2587	--	1989-10-14	1989-07-01
		1989-09-12			

[स.सं.प.सं./13/10]

S.O. 1090.—The Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the marking fees as notified earlier in Part-II, Section-3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, shown in Col. 7 or 8 of the Schedule given her under, in respect of the various products shown under Col. 2 and 3 of the same Schedule have been revised as mentioned in Col. 4, 5 and thereof.

THE SCHEDULE

Product		IS : No. & Year	Unit	Marking Per Unit Rs. P.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Salt-glazed stoneware pipes and fittings	IS : 651—1980	One Tonne	2.00
2.	Hockey sticks	IS : 829—1978	One Stick	0.10
3.	Apparatus for determination of milk fat by gerber method ; Section 2 Lockstepper	IS : 1223—1982	100 Pieces	0.20
4.	Centrifuge Section 6	-do-	One Centrifuge	0.75
5.	Poultry feeds	IS : 1374—1979	One Tonne	3.00
				1.50
6.	Kraft paper	IS : 1397—1967	-do-	10.00
7.	Cast iron pressure pipes for water, gas and sewage	IS : 1537—1976	One Tonne	4.00
				2.00
8.	Burettes	IS : 1997—1982	One Burette	0.25
9.	Stabilized hydrogen peroxide	IS : 2080—1980	One Kg	0.05
10.	Tubular steel poles for overhead power lines	IS : 2713 (Parts I to III)—1980	One Pole	1.00
11.	Fibreboard boxes	IS : 2771 (Part I) 1977	One Tonne	5.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Musk ambrette		IS : 3131—1986	One Kg	0.40
13. Musk Xylol.		IS : 3145—1986	One Kg	0.10
14. Hypodermic syringes for special purposes		IS : 3237—1980	100 Syringes	3.00
15. Horizontal Cylindrical and horizontal rectangular steam sterilizers, pressure type		IS : 3829 (Part 1) — 1978	One Sterlizer	50.00
16. Horizontal cylindrical and high speed steam sterilizers pressure		IS : 3829 (Part 2) — 1978	One Sterlizer	50.00
17. Sorbitol (70%) solution for cosmetic industry		IS : 3987—1983	One Tonne	25.00
18. Agricultural trillage disc concave type		IS : 4366 (Part I)— 1985	One Disc	0.30
19. Foam concentrate (compound) for producing mechanical foam for fire fighting Protein Foam		IS : 4989 (Part 1)— 1985	One Litre	0.06 0.04
20. Foam concentrate (compound) for producing mechanical foam for fire fighting Aqueous film forming foam (AFFF)		IS : 4989 (Part 2)— 1984	One Litre	0.12 0.08
21. Code of practice for testing of positive displacement type air compressors and exhausters		IS : 5456—1985	One Compressor	15.00 10.00
22. Hand-operated universal gearless pulling and lifting machines		IS : 5604—1984	One Machine	7.50 5.00
23. Floor polish, paste		IS : 8541—1977	10 Kg	0.75

Fee Rate For Unit	Reference of Govt. of India, Gazette Notification Partially Superseded S.O. No. and Date	Reference of Govt. of India, Gazette Modified S.O. No. and Date	Date of Issue of Gazette of India	Date of Effect
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
All	—	1274 1984 04 12	1984 04 21	1989 08 01
All	—	2365 1983 04 28	1983 05 28	1990 01 01
All	—	1015 1988 01 20	1988 04 02	1989 08 01
All	—	-do-	-do-	-do-
First 3000	—	2108	1983 05 14	1989 08 01
Remaining	—	1983 04 14		
All	—	—	—	1989 07 01
First 15000	—	1482	1984 05 05	1989 07 01
Remaining	—	1984 03 30		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
All	—	—	—	-do-
All	2587 1989 09 12	—	1980 10 14	-do-
All	653 1977 02 01	—	1977 02 26	1989 10 01
All	1505 1977 04 28	—	1977 05 21	1989 07 01
All	—	220 1983 12 27	1984 01 21	1989 12 01
All	—	220 1983 12 27	1984 01 21	1989 12 01
All	—	4199 1983 10 26	1983 11 19	1990 01 01
All	—	1015 1988 01 20	1983 04 02	-do- 1988 01 20
All	—	—	—	—
All	—	3972 1979 11 20	1979 12 08	1989 12 01
All	—	2005 1974 07 10	1974 08 10	1989 11 01
First 100000	2545	—	1977 08 13	1989 10 01
Remaining	1977 07	—	—	1989 10 01
First 100000	—	—	—	1989 10 01
Remaining	—	—	—	1989 10 01
First 1000	—	1998	1984 06 23	1989 10 01
Remaining	—	1984 05 30	—	1989 10 01
First 1000	—	1554	1972 06 24	1989 07 01
Remaining	—	1972 04 21	—	1989 07 01
All	2587 1989 09 21	—	1989 10 14	1989 07 01

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1990

का.प्र. 1091--भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों की मुहुरांकन फॉर्म अधिसूचित करता है।

अनुसूची

क्र. सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	भारतीय मानक को संख्या और वर्ष	इकाई	प्रति इकाई मुहुरांकन फॉर्म	जामा होने की तिथि
1.	हैलिकॉप्टर संवीक्षण कमानो-अनूप कुंडलित कमानो	IS : 7906 (भाग 2)-1975	एक लिपि	1. 2 पैसे प्रति इकाई पत्रिका 100000 इकाइयों के लिए, और 2. 1 पैसे प्रति इकाई पत्रिका 100001 की और अधिक के लिए	1982-05-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				टिप्पणी : महरांकन शुल्क की दर में दिनांक 1988-07-01 से निम्न परिवर्तन किया गया है : 2 पैसे प्रति इकाई (इकाई-1 कमावी)	
2. खाद्य ग्रेड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड	IS : 8356-1977	एक कि.ग्रा.	25 पैसे		1981-03-16
3. प्लास्टिक के संकलित ग्रीफकेस	IS : 9848-1981	एक ग्रीफकेस	1. 20 पैसे प्रति इकाई, पहली 100000 इकाइयों के लिए, और 2. 10 पैसे प्रति इकाई 100001वीं और अधिक के लिए		1986-08-16
			टिप्पणी : महरांकन शुल्क की दर में दिनांक 1989-05-01 से निम्न परिवर्तन किया गया है :		
			1. 40 पैसे प्रति इकाई पहली 100000 इकाइयों के लिए, और 2. 20 पैसे प्रति इकाई 100001वीं और अधिक के लिए		
4. पटसन केमवस, भारीक	IS : 10036 (भाग 2)-1982	एक टन	रु. 7.00		1989-08-16
5. हरमेटिक संपीड़क, उच्च ताप उपयोग समूह	IS : 10617 (भाग 1)-1983	एक संपीड़क	1. रु. 1.00 प्रति इकाई पहली 20000 इकाइयों के लिए 2. 80 पैसे प्रति इकाई 20001वीं से 40000 इकाइयों के लिए और 3. 50 पैसे प्रति इकाई 40001वीं और अधिक के लिए ।		1984-09-16
			टिप्पणी : महरांकन शुल्क की दर में दिनांक 1989-07-01 से निम्न परिवर्तन किया गया है :		
			1. रु. 2.00 प्रति इकाई पहली 20000 इकाइयों के लिए, और 2. रु. 1.00 प्रति इकाई 20001वीं और अधिक के लिए (इकाई-एक संपीड़क)		
6. हरमेटिक संपीड़क, मध्यम ताप उपयोग समूह	IS : 10617 (भाग 2)-1983	एक पैसा	--यही--		1987-05-01
7. हरमेटिक संपीड़क, निम्न ताप उपयोग समूह	IS : 10617 (भाग 3)-1983	एक	1. रु. 1.00 प्रति इकाई पहली 20000 इकाइयों के लिए 2. 80 पैसे प्रति इकाई 20001वीं से 40000 इकाइयों के लिए, और 3. 50 पैसे प्रति इकाई 40001वीं और अधिक के लिए ।		1986-09-16
			टिप्पणी : महरांकन शुल्क की दर में दिनांक 1989-07-01 से निम्न परिवर्तन किया गया है :		
			1. रु. 2.00 प्रति इकाई पहली 20000 इकाइयों के लिए, और 2. रु. 1.00 प्रति इकाई 20001वीं और अधिक के लिए (इकाई-एक संपीड़क)		

New Delhi, the 21st March, 1990

S.O. 1091.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies the marking fee(s) for the products given in the schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and year of Indian Standard	Unit	Marking fee per unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Helical compression springs—Cold coiled springs	IS : 7906 (Part II)—1975	One spring	(i) 2 Paise per unit for the first 100000 units and (ii) 1 Paise per unit for the 100001st unit and above. Note : Rate of Marking fee has since been revised with effect from 1989-07-01 : 2 Paise per unit (Unit-1 Spring)	1982-05-16
2.	Titanium dioxide, food grade	IS : 8356—1977	One Kg	25 Paise	1981-03-16
3.	Brief cases, plastic moulded	IS : 9848—1981	One Briefcase	(i) 20 Paise per unit for the first 100000 units and (ii) 10 Paise per unit for the 100001st unit and above. Note : Rate of Marking fee has since been revised with effect from 1989-50-01 : (i) 40 Paise per unit for the first 100000 units and (ii) 20 Paise per unit for the 100001st unit and above.	1986-08-16
4.	Jute canvas, fine	IS : 10036 (Part II)—1982	One Tonne	Rs. 7.00	1980-08-16
5.	Hermetic compressors, High temperature application group	IS : 10617 (Part I)—1983	One Compressor	(i) Rs. 1.00 pe unit for the first 20000 units; (ii) 80 Paise per unit for the 20001st 40000 units and (iii) 50 Paise per unit for the 40001st unit and above. Note : Rate of Marking fee has since been revised as under with effect from 1989-07-01 : (i) Rs. 2.00 per unit for the first 20000 units and (ii) Rs. 1.00 per unit for the 20001st unit and above. (Unit-One Compressor)	1984-09-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Hermetic compressor, IS : 10617 (Part II)— Medium temperature 1983 application group	One Piece	-do-		1987-05-01
7.	Hermetic compressors, IS : 10617 (Part III)— Low temperature 1983 application group	One	-do-		1984-09-16

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1990

क्र. प्र. 1092:—भारतीय मानक ब्यूरो विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन विभिन्न उत्पादों का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है उनकी प्रति इकाई मूहर लगाने को फंस निर्धारित कर दी गई है और यह फंस उनके सामने दी गई तिथि से लागू होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	इकाई	प्रति इकाई मूहर लगाने की फंस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टागल स्विच टाइप 1 व 2	IS : 3452 (भाग 2)- 1970	एक पiece	एक पैसा	1989-08-01
2.	पूर्व प्रतिबलित कॉन्क्रीट हेतु अलेपित प्रतिलव मुक्त लड़	IS : 6006-1983	एक टन	रु. 3.00	1989-08-16
3.	प्रोपोक्सोर पाथसर्तीय सांद्र	IS : 9665-1981	1 लि.	25 पैसे	1988-12-16

[संख्या सी.एस.बी./13 : 10]

एस. सुब्राह्मन्यम, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 22nd March, 1990

S. O. 1092.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies the marking fee(s) for the products given in the schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and year of Indian Standard	Unit	Marking fee per unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Toggle switches, Type I & II	IS : 3452 (Part II)— 1970	One Piece	One Paise	1989-08-01
2.	Uncoated stress relieved strand for prestressed concrete	IS : 6006—1983	One Tonne	Rs. 3.00	1089-08-16
3.	Propoxur emulsifiable concentrates	IS : 9665—1981	11	25 Paise	1988-12-16

[No. CMD/13: 10]

S. SUBRAHMANYAN, Addl. Director General

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1990

क्र. आ. 1039—केंद्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii), तारीख 29 अक्टूबर, 1988 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना क्र. आ. सं. 3189, तारीख 30 सितम्बर, 1988 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 218.08 हेक्टर (लगभग) या 538.65 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वोक्त करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राय है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनसे संलग्न अनुसूची में वर्णित 216.91 हेक्टर (लगभग) या 535.98 एकड़ (लगभग) माप की भूमि या ऐसी भूमि में या उन पर के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देता है।

टिप्पण 1: स अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक नं. सी. 1 (ई.)/III/जेई जे. आर./433-0589, तारीख 2-5-1989 का विरोक्षण कलकत्ता यबतमाल (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय में या वेस्टन कोल-कॉरडम लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल एस्टेट्स सिविल लाइसेंस, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2: कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्तों का और ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध है।

"8. अर्जन के प्रति आक्षेप—(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अर्जी अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किसी अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संचायक करना चाहता है और ऐसी संचायक केंद्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन पर्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं मुने जाने का या विधि व्यवस्थाओं द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को मुने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो यह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हत का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण 3: केंद्रीय सरकार के कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रधान सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची "क"

कोलार डिप्टरी ग्लाक

बानी क्षेत्र

जिला यबतमाल (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पट्टाकारी सफिल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1. गोवारी		31	बानी	यबतमाल	105.33	भाग
2. कोल		31	बानी	यबतमाल	28.92	भाग
3. धगासी		32	बानी	यबतमाल	78.39	भाग
4. धिम्परी		32	बानी	यबतमाल	1.14	भाग
कुल क्षेत्र :				213.78 हेक्टर (लगभग)		
या				528.25 एकड़ (लगभग)		

गोवारी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याएँ

1 से 3, 6 (भाग), 7 (भाग), 8 (भाग), 9/1-9/2 (भाग), 10 (भाग), 11, 12/1-12/1क-12/2, 13, 14, 15 (भाग), 16 (भाग), 17 (भाग), 18 (भाग), 23 (भाग), 24 (भाग), 28 (भाग), 99 (भाग), 100 (भाग), 101 (भाग), 122 (भाग), 129 से 132, 138 से 144, 145 (भाग), 146 (भाग), 147 (भाग), 148 (भाग), 149 (भाग), 150 से 152 सहक भाग और आबादी भाग।

कोना ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

77 (भाग), 78 (भाग), 111 (भाग), 112 (भाग), 113 (भाग), 212 (भाग), 213 (भाग), 215 (भाग), 216 (भाग), 217 से 228, 230, 232 (भाग), 233 (भाग) ।

भगासी ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

1/3-1/4 क-1/4 ख-1/4 ग-1/4 घ-1/5, 2/1-2/2-2/3-2/4क, 3/1-3/2-3/3, 4/1-4/2-4/3-4/3क-4/4, 5/1-5/2, 6/1-6/1क-6/2-6/3-6/4, 7/1-7/1क-7/2-7/2क-7/2ख-7/2ग-7/2घ-7/2ङ-7/3-7/3क-7/4 (भाग), 8, 9, 10/1-10/1क-10/2-10/3-10/4-10/5, 11/1-11/2, 12/1-12/2, 12/2क-12/3-12/4-12/5, 13/1-13/2-13/3-13/3क-13/4, 14 आबदी नाला भाग ।

पिम्परी ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

3 (भाग), 5 (भाग) ।

सीमा वर्णन :

क-ख-ग रेखा बिन्दु "क" से प्रारम्भ होती है और पिम्परी ग्राम में प्लॉट सं. 3, 5 से होकर गुजरती है। तब वह भगासी ग्राम में नाला, प्लॉट सं. 7/1-7/1क-7/2-7/2क-7/2ख-7/2ग-7/2घ-7/2ङ-7/3-7/3क-8/4 से होकर गुजरती है और गोवरी ग्राम में प्लॉट सं. 18, 17, 16, 15, 23, 24, 28, 10, 9/1-9/2, 8, 7, 6, सड़क 149, 148, 147, 143, 146, 99, 100, 101 से होते हुए बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ-ङ रेखा गोवरी ग्राम में से प्लॉट सं. 101, 144, 138 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती हुई प्लॉट सं. 122 तक जाती है। तब सीमा ग्राम कोना में प्लॉट सं. 78, 77, 112, 111, 213, 212, 215 नाला, 216 में से जाती है और फिर प्लॉट सं. 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 230 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती हुई बिन्दु "ङ" से मिलती है।

ङ-घ-छ-ज रेखा ग्राम कोना में प्लॉट सं. 233, 232, 216 में से गुजरते हुए नाला, 215, सड़क, 213, 111, 112, 113, 77, 78, को पार करती है और ग्राम गोदावरी में प्लॉट सं. 122 से गुजरते हुए बिन्दु "ज" से मिलती है।

ज-झ-ञ-क रेखा ग्राम गोवरी में प्लॉट सं. 132, 131, 129, 141, 142, 151, 152, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9/1-9/2, 10, 11, 12/1-12/1क-12/2, 13 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती है, तब ग्राम भगासी में प्लॉट सं. 4/1-4/2, 4/3-4/3क-4/4, 3/1-3/2-3/3, 2/1-2/2-2/3-2/4क-1/3-1/4क-1/4ख-1/4ग-1/4घ-1/5, 14, आबदी 13/1-13/2-13/3-13/4, 11/1-11/2, 10/1-10/1क-10/2-10/3-10/4-10/5 की बाह्य सीमा तथा नाला के साथ-साथ चलती है और तब ग्राम पिम्परी में प्लॉट सं. 3 से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

अनुसूची "ख"

कोलार पिम्परी ब्लाक

बानी क्षेत्र

जिला वयतमाल (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पट्टेधारी सफिल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टरों में	टिप्पणियाँ
1.	कोना	31	बानी	वयतमाल	0.93	भाग
2.	सावरला	31	बानी	वयतमाल	2.20	भाग
			कुल क्षेत्र :	3.13 हेक्टर (लगभग)		
			या	7.73 एकड़ (लगभग)		

अनुसूची क+ख का

कुल क्षेत्र - 213.78 + 3.13 = 216.91 हेक्टर (लगभग)

या 528.25 + 7.73 = 535.98 एकड़ (लगभग)

ग्राम कोना में अजित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

231 (भाग), 262 (भाग), 264 (भाग), 265 (भाग),

ग्राम सावरला में अजित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

6 (भाग), 7 (भाग), 10 (भाग), 11 (भाग), 14 (भाग), 15 (भाग), 136 (भाग), 141 (भाग), 142 (भाग), 144 (भाग), 145 (भाग) सड़क भाग ।

सीमा वर्णन :

ट-ठ-ड रेखा बिन्दु "ट" से प्रारम्भ होती है और कोना ग्राम में प्लॉट सं. 262, 231, 264, 265 से होकर जाती है और तब सावरला ग्राम में प्लॉट सं. 136, 145, 144 में से होकर प्लॉट सं. 141, 142 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलकर प्लॉट सं. 6, 7, 10, 11, 14, 15 में से गुजरती है और बिन्दु "ड" से मिलती है।

ड-ढ-ट रेखा, सावरला ग्राम में से होकर प्लॉट सं. 15, 14, 11, 10, 7, 6 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती है और प्लॉट सं. 142, 141, 144, 145, 136 में से होकर जाती है और तब कोना ग्राम में प्लॉट सं. 265, 264, 262 में से होकर जाती है और बिन्दु "ट" पर मिलती है।

[सं. 43015/9/88 - एल. एस. डब्ल्यू.]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 2nd April, 1990

S.O. 1093.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal, S.O. No. 3189, dated the 30th September, 1988 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in the Gazette of India in Part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 29th October, 1988, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 218.08 hectares (approximately) or 538.65 acres (approximately) of the lands in locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in apart of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 216.91 hectares (approximately) or 535.98 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in the schedule appended hereto.

Note-1.—The plan bearing No. C-1(E)/III/JJR/433-0589, dated 2-5-1989, of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Yeotmal (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra).

Note-2.—Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition

and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows :—

8. Objections to acquisition—(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note-3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE 'A'

KOLAR PIMPRI BLOCK

WANI AREA

DISTRICT—YEOTMAL (MAHARSHTRA)

ALL RIGHTS

Serial No.	Name of Village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Gowari	31	Wani	Yeotmal	105.33	Part
2.	Kona	31	Wani	Yeotmal	28.92	Part
3.	Agasi	32	Wani	Yeotmal	78.39	Part
4.	Pimpri	32	Wani	Yeotmal	1.14	Part
Total Area = 213.78 Hectares						(approximately)
						or
						528.25 Acres
						(approximately)

Plot numbers to be acquired in village Gowari :

1 to 5, 6 (part), 7 (part), 8(part), 9/1-9/2 (part), 10(part), 11, 12/1-12/1A-12/2, 13, 14, 15 (part), 16 (part), 17(part), 18(part), 23(part), 24(part), 28(part), 99(part), 100(part), 101(part), 122(part), 129 to 132, 138 to 144, 145(part), 146(part), 147(part), 148(part), 149(part), 150 to 152, Road part and Abadi part.

Plot numbers to be Acquired in Village—Kona.

77(part), 78(part), 111(part), 112(part), 113(part), 212(part), 213(part), 215(part), 216(part), 217 to 228, 230, 232(part), 233(part).

Plot numbers to be Acquired in Village—Agasi.

1/3-1/4 A-1/4B-1/4C-1/4 D-1/5, 2/1-2/2-2/3-2/4A, 3/1-3/2-3/3, 4/1-4/2-4/3-4/3A-4/4, 5/1-5/2, 6/1-6/1A-6/2-6/3-6/4, 7/1-7/1A-7/2-7/2A-7/2B-7/2 C-7/2D-7/2E-7/3-7/3A-7/4(part), 8, 9, 10/1-10/1A-10/2-10/3-10/4-10/5, 11/1-11/2, 12/1-12/2-12/2A-12/3-12/4-12/5, 13/1-13/2-13/3-13/4, 14 Abadi, Nallah Part.

Plot numbers to be Acquired in Village—Pimpri.

3(Part), 5(Part).

Boundary Description :

- A-B-C** Line starts from point 'A' and passes through village Pimpri in plot numbers 3, 5 then proceeds through village Agasi in plot numbers, nallah, 7/1-7/1A-7/2-7/2A-7/2B-7/2C-7/2D-7/2E-7/3-7/3A-7/4 and proceeds through village Gowari in plot numbers 18, 17, 16, 15, 24, 28, 10, 9/1-9/2, 8, 7, 6 road, 149, 148, 147, 145, 146, 99, 100, 101 and meets at point 'C'.
- C-D-E** Line passes through village Gowari along the outer boundary of plot numbers 101, 144, 138 and in plot number 122 then proceeds through village Kona in plot numbers 78, 77, 112, 111, 213, 212, 215, nallah 216 and along the outer boundary of plot numbers 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 230 and meets at point 'E'.
- E-F-G-H** Line passes through village Kona in plot numbers 233, 232, 216 crosses nallah 215, road, 213, 111, 112, 113, 70, 78 then proceeds through village Gowari in plot number 122 and meets at point 'H'.
- H-I-J-A** Line passes through village Gowari along the outer boundary of plot numbers 132, 131, 129, 142, 141, 151, 152, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9/1-9/2, 10, 11, 12/1-12/1A-12/2, 13, then proceeds through village Agasi along the outer boundary of plot numbers 4/1-4/1 4/3-4/3A-4/4, 3/1-3/2-3/3, 2/1-2/2-2/3-2/4A, 1/3-1/4A-1/4B-1/4C-1/4D-1/5, 14 Abadi, 13/1-13/2-13/3-13/4, 11/1-11/2, 10/1-10/1A-10/2-10/3-10/4-10/5 nallah and then proceeds through village Pimpri in plot number 3 and meets at starting point 'A'.

SCHEDULE 'B'
KOLAR PIMPRI BLOCK
WANI AREA
DISTRICT—YEOTMAL (MAHARASHTRA)

ALL RIGHTS

Serial Number	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	KONA	31	Wani	Yeotmal	0.93	Part
2.	SAWARLA	31	Wani	Yeotmal	2.20	Part
(Total of Schedules A + B—						Total Area-3.13 Hectares (approximately)
						or 7.73 Acres (approximately)
						213.78 + 3.13-216.91 hectares (approximately)
						or 528.25 + 7.73 acres-535.98 Acres (approximate)

Plot Numbers to be Acquired in Village : Kona.

231 (part), 262 (part), 264 (part), 265 (part).

Plot Numbers to be Acquired in Village —Sarwarla.

6 (part), 7 (part), 10 (part), 11 (part), 14 (part), 15 (part), 136 (part), 141 (part), 142 (part), 144 (part), 145 (part), road part.

Boundary description :

- K-L-M Line starts from point 'K' through village Kona in plot numbers 262, 231, 264, 265, then proceeds through Sawarla village in plot numbers 136, 145, 144 along the outer boundary of plot numbers 141, 142 and in plot numbers 6, 7, 10, 11, 14, 15 and meets at point 'M'.
- M-N-K Line passes through village Swarla along the outer boundary of plot numbers 15, 14, 11, 10, 7, 6 and in plot numbers 142, 141, 144, 145, 136 then proceeds through Kona village in plot numbers 265, 264, 262 and meets at starting point 'K'.

[No. 43015/9/88-LSW]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1990

का. प्रा. 1094:—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपाखण्ड (ii) तारीख 20 अप्रैल, 1988 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) अधिसूचना सं. का. प्रा. 1348, तारीख 8 अप्रैल, 1988 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिच्छेद में 206.81 हेक्टर (लगभग) या 511.03 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सूत्राय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उस भूमि में कोयला अतिव्याप्त है ;

अतः, अब, सूत्राय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है :—

(क) इससे संलग्न अनुसूची "क" में वर्णित 95.20 हेक्टर (लगभग) या 235.15 एकड़ (लगभग) माप की भूमि ;

(ख) इससे संलग्न अनुसूची "ख" में वर्णित 25.81 हेक्टर (लगभग) या 63.72 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बो करने, उनका खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार ;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक 'सो-(ई)/III/जेजेआर/442-0889, तारीख 11 अगस्त 1989 का निरीक्षक कलक्टर चम्बरपुर (महाराष्ट्र) या कोयला नियंत्रक, 1 प्लाउमिन हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता या वेस्टर्न कोयला इम लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध है :—
अर्जन के प्रति आपत्ति :

"8. (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 17 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितवद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करनी चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसा सभी आपत्तियों की सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो यह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अधिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टों केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितवद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने या हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, कार्लसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

घनसूची "क"

बुगुस विद्युत परियोजना

घनी क्षेत्र

जिला - चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार (भाग-1)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सफिल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	उसगांव	2	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	26.57	भाग
					कुल क्षेत्र या	26.57 हैक्टर (लगभग) 65.62 एकड़ (लगभग)

ग्राम उसगांव में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

1क, 1ख भाग और 258 भाग।

सीमा वर्णन :

- छ - ज रेखा बिन्दु "छ" से प्रारंभ होती है और बुगुस तथा उसगांव ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलती हुई बिन्दु "ज" पर मिलती है।
- ज - झ रेखा प्लॉट संख्यांक 1/क, 1/ख की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती हुई ग्राम उस गांव से गुजरती है और प्लॉट सं. 258 से होकर गुजरती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।
- झ - ञ रेखा प्लॉट सं. 1/ख में ग्राम उसगांव से होकर गुजरती है और बिन्दु "ञ" से मिलती है।
- ञ - छ रेखा प्लॉट सं. 1/ख, 258 में ग्राम उसगांव से होकर जाती है और प्लॉट सं. 1 क की बाह्य सीमा से साथ-साथ चलकर बिन्दु "छ" से मिलती है।

घनसूची "क"

सभी अधिकार (भाग-2)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सफिल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	बुगुस	2	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	34.30	भाग
2.	नकोड़ा	2	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	34.33	भाग
					कुल क्षेत्र या	68.63 हैक्टर (लगभग) 169.51 एकड़ (लगभग)

घनसूची "क" भाग - 1 और भाग - 2 का कुल क्षेत्र 95.20 हैक्टर (लगभग)

या

235.13 एकड़ (लगभग)

ग्राम बुगुस में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

1989 भाग, 292, 448ख भाग और 448क भाग

ग्राम नकोड़ा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

4 भाग, 37 भाग, 38 से 40, 41/एपी भाग, 46 से 64, 65 भाग, 68 से 71, 73/1, 73/2, 74, 75/76 भाग, 77 से 84

सीमा वर्णन :

- क - ख रेखा बिन्दु "क" से प्रारंभ होती है और प्लॉट सं. 1989 292 की बाह्य सीमा के साथ-साथ ग्राम बुगुस से होकर गुजरती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।
- ख - ग रेखा बुगुस ग्राम में प्लॉट संख्यांक 198/क, 448/ख, 448/क से होकर जाती है, फिर नकोड़ा और उस गांव ग्रामों की सम्मिलित ग्राम्य सीमा के साथ-साथ चलकर बिन्दु "ग" पर मिलती है।
- ग - छ रेखा ग्राम नकोड़ा के प्लॉट सं. 4 से होकर गुजरती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

- ४-४-घ रेखा प्लॉट सं. 76 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती हुई ग्राम नकोड़ा से गुजरती है और प्लॉट सं. 76 में से और फिर वह प्लॉट सं. 84, 83 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती है। तत्पश्चात् प्लॉट सं. 37 में से होती हुई प्लॉट संख्यांक 38, 39, 40 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती है और फिर प्लॉट सं. 41 ए. पी. में से होती हुई प्लॉट सं. 62, 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 54 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलते हुए प्लॉट सं. 65 में से होकर बिन्दु "ब" से मिलती है।
- घ-ट रेखा प्लॉट सं. 69, 68 की बाह्य सीमा के साथ-साथ अन्नहर ग्राम नकोड़ा के प्लॉट सं. 4 से गुजरती हुई, घुगुस ग्राम के प्लॉट सं. 198४ में से होती हुई आरम्भिक बिन्दु "क" से मिलती है।

अनुसूची "ख"
घुगुस विधुल परियोजना
बनी क्षेत्र
जिला - चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

खनन अधिकार (भाग-1)

क्रम सं. ग्राम क. नाम	पट्टाकारी सफिल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1 नकोड़ा	2	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	24.88	भाग
				कुल क्षेत्र	24.88 हैक्टर (लगभग) 61.46 एकड़ (लगभग)

ग्राम नकोड़ा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

36, 76 भाग, 85, 86 भाग, 87, 88 89 भाग, 90 भाग, 93 भाग, 94, 95 भाग, 97, 103, 104, 113, 114/1, 115

सीमा वर्णन :

- ट-ठ रेखा बिन्दु "ट" से आरम्भ होती है और प्लॉट सं. 88 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती है और प्लॉट सं. 89, 90, 93, 95 में से गुजरती हुई ग्राम नकोड़ा के प्लॉट सं. 94, 97, 104, 114/1, 113, 115 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलकर बिन्दु "क" पर मिलती है।
- ठ-ड रेखा नकोड़ा ग्राम में से गुजरती हुई प्लॉट सं. 115, 114/1 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलकर बिन्दु "ड" पर मिलती है।
- ड-४ रेखा नकोड़ा ग्राम में से प्लॉट सं. 114/1, 103, 97 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती है और तब प्लॉट सं. 36 और 85 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलकर बिन्दु "क" से मिलती है।
- ड-घ-ट रेखा नकोड़ा ग्राम से गुजर कर प्लॉट सं. 85 की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलती है और तब प्लॉट सं. 76 में से गुजरती है और फिर बिन्दु "ट" से मिलती है।

अनुसूची "ख"

खनन अधिकार (भाग-2)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पट्टाकारी सफिल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्रों में	टिप्पणियां
1. नकोड़ा		2	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	0.93 (भाग)	
					कुल क्षेत्र	0.93 हैक्टर (लगभग) या 2.27 एकड़ (लगभग)

अनुसूची "ख" भाग - 1 और भाग - 2 का कुल क्षेत्र 25.81 हैक्टर (लगभग)
या
63.72 एकड़ (लगभग)

ग्राम नकोड़ा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं. 72क, 72ख

सीमा वर्णन :

- ड-ण रेखा नकोड़ा ग्राम में बिन्दु "क" से आरम्भ होती है, प्लॉट सं. 72क, 72ख के साथ-साथ चलकर बिन्दु "ण" पर मिलती है।
- ण-त-ड रेखा ग्राम नकोड़ा में प्लॉट सं. 72क, 72ख की बाह्य सीमा के साथ-साथ चलकर आरम्भिक बिन्दु "ड" पर मिलती है।

New Delhi, the 5th April, 1990

OBJECTION TO ACQUISITION :

S.O. 1094.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. SO. 1348 dated the 8th April, 1988, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated the 30th April, 1988, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 206.81 hectares (approximately) or 511.03 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire;

- (a) the lands measuring 95.20 hectares (approximately) or 235.13 acres (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto;
- (b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 25.81 hectares (approximately) or 63.72 acres (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto;

NOTE-1.—The plan bearing No. C-1(E)/III/JJR/442-0889 dated the 11th August, 1989 if the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller-1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-40001, Maharashtra.

NOTE-2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows :—

"8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations on the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of the Section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections together with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

NOTE-3.—The Coal Controller-1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE 'A'

GHUGUS OPENCAST PROJECT

WANI AREA

DISTRICT-CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

ALL RIGHTS (PART-I)

Serial Number	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	USGAON	2	Chandrapur	Chandra pur	26.57	Part
Total Area =					26.57	Hectares (approximately) or 65.62 Acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village-Usgaon.

1A, 1B part, and 258 Part.

Boundary description :

G-H Line starts from point 'G' and passes along the common village boundary of villages Ghugus and Usgaon and meets at point 'H'.

H-I	Line passes through village Usgaon along the outer boundary of plot numbers 1/A, 1/B and through plot number 258 and meets at point 'I'.
I-J	Line passes through village Usgaon in plot number 1/B and meets at point 'J'.
J-G	Line passes through village Usgaon in plot numbers 1/B, 258 and along the outer boundary of plot number 1/A and meets at starting point 'G'.

SCHEDULE 'A'

ALL RIGHTS (PART-II).

Serial Number	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Ghugus	2	Chandrapur	Chandrapur	34.30	Part
2.	Nakode	2	Chandrapur	Chandrapur	34.33	Part
Total Area =					68.63 Hectares (approximately) or 169.51 Acres (approximately)	
Total of Schedule 'A', Part-I and Part-II =						95.20 Hectares (approximately) or 235.13 Acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village—Ghugus.

198 E part, 292, 448B part and 448 E Part.

Plot numbers to be acquired in village—Nakoda.

4 part, 37 part, 38 to 40, 41/1AP Part, 46 to 64, 65 part, 68 to 71, 73/1, 73/2, 74, 75, 76 part, 77 to 84.

Boundary description :

A-B	Line starts from point 'A' and passes through village Ghugus along the outer boundary of plot numbers 198 E, 292 and meets at point 'B'.
B-C	Line passes in village Ghugus, through plot numbers 198/E, 448/B, 448/E then partly along the common village boundary of villages Nakoda and Usgaon and meets at point 'C'.
C-D	Line passes through plot number 4 of village Nakoda and meets at point 'D'.
D-E-F	Line passes through village Nakoda, along the outer boundary of plot number 76, then through plot number 76, proceeds along the outer boundary of plot numbers 84, 83, then through 37, along the outer boundary of plot numbers 38, 39, 40, through plot number 41. Along the outer boundary of plot numbers 62, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, then through plot number 65 and meets at point 'F'.
F-A	Line passes along the outer boundary of plot numbers 69, 68 then through plot number 4 of village Nakoda, through plot number 198E of village Ghugus and meets at Starting point 'A'.

SCHEDULE 'B'
GHUGUS OPENCAST PROJECT
WANI AREA

DISTRICT-CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

MINING RIGHTS (Part-I)

Serial Number	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	NAKODA	2	Chandrapur	Chandrapur	24.88	Part
					Total area—24.88 Hectares	(approximately)
						or
						61.45 Acres
						(approximately)

Plot numbers to be acquired in village-Nakoda.

36, 76 part, 85, 86 part, 87, 88, 89 part, 90 part, 93, part, 94, 95 part, 97, 103, 104, 113, 114/1, 115.

Boundary description :

K-L	Line starts from point 'K' and passes along the outer boundary of plot number 88 then passes through plot numbers 89, 90, 93, 95 then along the outer boundary of plot numbers 94, 97, 104, 114/1, 113, 115 of village-Nakoda and meets at point 'L'.
L-M	Line passes through village—Nakoda along the outer boundary of plot numbers 115, 114/1 and meets at point 'M'.
M-E	Line passes through village Nakoda along the outer boundary of plot numbers 114/1, 103, 97 then through plot number 86, along the outer boundary of plot numbers 36 and 85 and meets at point 'E'.
E-D-K	Line passes through village Nakoda and passes along the outer boundary of plot number 85 then through plot number 76 and meets at starting point 'K'.

SCHEDULE 'B'

MINING RIGHTS (PART-II)

Serial Number	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	NAKODA	2	Chandrapur	Chandrapur	0.93	Part
					Total area—	0.93 hectares (approximately) or 2.27 Acres (approximately)

Total of Schedule 'B', Part-I and Part-II —

25.81 Hectares
(approximately)
or
63.72 Acres
(approximately)

Plot number to be acquired in village—Nakoda.
72A, 72B.

Boundary description :

- N-O Line starts from point 'N' through village Nakoda along the outer boundary of plot numbers 72A, 72B and meets at point 'O'.
- O-P-N Line passes through village Nakoda along the outer boundary of plot numbers 72A, 72B and meets at starting point 'N'.

[No. 43015/2/88-LSW]
B.B. RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1990

का. धा. 1095.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्ध और विमान) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (i) के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 2 मई, 1987 में प्रकाशित द्वारा सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. धा. 1136, तारीख 16 अप्रैल, 1987 द्वारा उन अधिसूचना संख्यांक अधिसूचों में विनिर्दिष्ट परिणेत्र में 633.15 हेक्टर (लगभग) या 1563.88 एकड़ (लगभग) की भूमि में कोयले का पूर्वोक्त करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. धा. 909, तारीख 28 मार्च, 1989 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 की उपधारा (i) के अधीन 2 मई, 1989 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया या जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि का अथवा ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकार का अर्जन करने के योग्य को सूचना दे सकेगी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राय है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूचा में वर्णित 531.00 हेक्टर (लगभग) या 1312.25 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देता है।

टिप्पण 1— इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सी-I (ई)/III/जे. जे. आर./458-290, तारीख 7-2-1990 का निरीक्षण कलक्टर, चन्द्रपुर और यवतमान (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या बैस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व, अनुभाग), कोयला एन्डेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2— पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों को और ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं।

“8(1) अर्जन की बाबत आपत्तियाँ: कोई व्यक्ति जो कितनी भूमि में जिसको बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली हुई गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीन दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किसी अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

सम्यक्करण— इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (i) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा मुतबाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (i) के अधीन अधिसूचित भूमि या के ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को विनिर्धन्य के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में जिन का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।”

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची
जुनाडू ब्लॉक
बानी क्षेत्र

(जिला चंद्रपुर और यवतमाल (महाराष्ट्र))

सभी अधिकार

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ग्राम सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टरों में	टिप्पणियाँ
1.	अहेरी	12	बानी	यवतमाल	12.45	भाग
2.	बोरगांव	247	बानी	यवतमाल	200.83	भाग
3.	जुनाडू	122	बानी	यवतमाल	168.31	भाग
4.	पिपलगांव	218	बानी	यवतमाल	100.72	भाग
5.	उकणी	21	बानी	यवतमाल	31.29	भाग
6.	पिपरी	311	भद्रावनी	चंद्रपुर	17.50	भाग

कुल क्षेत्र 531.10 हेक्टर (लगभग)
या 1312.45 एकड़ (लगभग)

अहेरी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं. :

11 से 13, 16 से 22

बोरगांव ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं. :

1 से 77, 80 से 93, 95 से 100, 163 से 187, आशानी

जुनाडू ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं. :

1 से 34, 38, 51 से 54, 56 से 86, आबादी और सड़क

पिपलगांव ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं. :

1 से 2, 151 से 157, 159 से 168, 169/1-169/2, 203 से 305, नाका

उकणी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं. :

692 से 698, नदी (भाग)।

पिपरी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं. :

नदी (भाग)

सीमा वर्णन :

- क-ख रेखा, वर्धा नदी के दक्षिणी किनारे के साथ साथ अहेरी, बोरगांव ग्रामों से होकर बिन्दु "क" से प्रारंभ होती है और फिर वर्धा नदी के पश्चिमी किनारे के साथ साथ जुनाडू और पिपलगांव ग्राम से होकर जाती है, वर्धा नदी को पार करती है, उसके बाद वर्धा नदी के पूर्वी किनारे के साथ साथ पिपरीगांव से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।
- ख-ग रेखा, पिपरी ग्राम से होकर जाती है, वर्धा नदी को पार करती है, उसके बाद प्लॉट सं. 698, 697 को बाहरा मामा के साथ साथ उकणी ग्राम से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।
- ग-क रेखा, प्लॉट सं. 697, 696, 692 का बाहरी सीमा के साथ साथ उकणी ग्राम से होकर जाती है और उसके बाद प्लॉट सं. 192, 191, 203, 205, 179, 1, 2, 159, 157, 156, 155, 151 का बाहरी सीमा के साथ साथ पिपलगांव ग्राम से होकर जाता है उसके बाद जुनाडू और पिपलगांव ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है फिर प्लॉट सं. 34, सड़क, 38, 54, 53, 52, 51 को बाहरा मामा के साथ साथ जुनाडू ग्राम से होकर जाती है फिर प्लॉट सं. 77, 75, 80, 100, 99, 98, 96, 95, 87, 93, 92, 164, 163, 168, 169, का बाहरी सीमा के साथ साथ बोरगांव ग्राम से होकर जाती है फिर प्लॉट सं. 22, 16, 13, 11 का बाहरी सीमा के साथ साथ अहेरी ग्राम से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/20/86 - सं. ए./एन एम डब्ल्यू.]

डॉ. बी. राव, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 1990

S.O. 1095.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 1136 dated the 16th April, 1987 under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in the Gazette of India in Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 2nd May, 1987, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 633.15 hectares (approximately) or 1563.88 acres (approximately) of the lands in locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And, whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 909 dated the 28th March, 1989 under sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government specified a further period of one year commencing from the 2nd May, 1989 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 531.10 hectares (approximately) or 1312.35 acres (approximately) in All Rights as described in the schedule appended hereto.

Note 1.—The plan bearing No. C-1(E)/III/IJR/458-290 dated 7-2-1990 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collectors Chandrapur and Yavatmal (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the West-

ern Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra).

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the aforesaid Act, which provides as follows :—

Objections to Acquisition :

“8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this Section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act.

SCHEDULE JUNAD BLOCK WANI AREA

DISTRICT CHANDRAPUR AND YAVATMAL (MAHARASHTRA)

ALL RIGHTS

Serial number	Name of village	Village number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Aheri	12	Wani	Yavatmal	12.45	Part
2.	Borgaon	247	Wani	Yavatmal	200.83	Part
3.	Junad	122	Wani	Yavatmal	168.31	Part
4.	Pimpalgaon	218	Wani	Yavatmal	100.72	Part
5.	Ukani	21	Wani	Yavatmal	31.29	Part
6.	Pipri	311	Bhandravati	Chandrapur	10.50	Part

Total area : 531.10 hectares
(approximately)
or
1312.35 acres
(approximately)

Plot numbers to be acquired in village Aheri :
11 to 13, 16 to 22.

Plot numbers to be acquired in village Borgaon :

1 to 77, 80 to 93, 95 to 100, 163 to 187, Abadi.

Plot numbers to be acquired in village Junad :

1 to 34, 38, 51 to 54, 56 to 86, Abadi and Road.

Plot numbers to be acquired in village Pimpalgaon :

1 to 2, 151 to 157, 159 to 168, 169/1-169/2, 170 to 192, 203 to 205, nallah.

Plot numbers to be acquired in village Ukani :

692 to 698, River (Part).

Plot numbers to be acquired in village Pipri :

River (Part).

Boundary description :

- A-B Line starts from point 'A' along the southern bank of Wardha River through villages Aheri, Borgaon, then passes through villages Junad and Pimpalgaon along the western Bank of Wardha River, crosses Wardha River, then passes through village Pipri along the Eastern bank of Wardha River and meets at point 'B'.
- B-C Line passes through village Pipri, crosses Wardha River, then through village Ukani along the outer boundary of plot numbers 698, 697 and meets at point 'C'.
- C-A Line passes through village Ukani along the outer boundary of plot numbers 697, 696, 692 and then passes through village Pimpalgaon along the outer boundary of plot numbers 192, 191, 203, 205, 170, 1, 2, 159, 157, 156, 155, 151, then passes along the common boundary of villages Junad and Pimpalgaon then passes through village Junad along the outer boundary of plot numbers 34, road, 38, 54, 53, 52, 51 then passes through village Borgaon along the outer boundary of plot numbers 57, 75, 80, 100, 99, 98, 96, 95, 87, 93, 92, 164, 163, 168, 169, then passes through village Aheri along the outer boundary of plot numbers 22, 16, 13, 11 and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/20/86-CA/LSW]

B.B. RAO, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1990

का. आ. 1096-दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61वां) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) द्वारा पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्रालय की दिनांक 4 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना सं. के-11011/22/78-डी. डी. 1-ए/II-बी के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार नई दिल्ली नगरपालिका के प्रशासक श्री सुभाष शर्मा को दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है तथा भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 30 दिसम्बर, 1957 की अधिसूचना सं. 12-173/57-एल. एस. जी. में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः :-

उक्त अधिसूचना में मद सं. 10 में "श्री धर्म दत्त, प्रशासक नई दिल्ली नगरपालिका" की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित होगी :-

"श्री सुभाष शर्मा, प्रशासक, नई दिल्ली नगरपालिका"

[सं. के-11011/22/78-डी. डी. आई. (ए)/II-बी/खण्ड-II]

एस. पी. मिगल, निवेशक (डी. डी.)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 22nd March, 1990

S.O. 1096.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), and in supersession of the Ministry of Works and Housing Notification No. K-11011/22/78-DDI(A)/IIB dated the 4th September, 1985, the Central Government hereby nominates Shri Subhash Sharma, Administrator, New Delhi Municipal Committee as a member of the Delhi Development Authority and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 12-173/57-LSG dated the 30th December, 1957, namely :—

In the said notification, in item No. 10 for the entry "Shri Dharam Dutt, Administrator, New Delhi Municipal Committee" the following entry shall be substituted :—

"Shri Subhash Sharma, Administrator, New Delhi Municipal Committee".

[No. K-11011/22/78-DDI(A)/IIB/Vol.II]

S. P. SINGAL, Director (DD)

अम संज्ञालय

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1990

का. आ. 1097 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-3-90 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd March, 1990

S.O. 1097.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 16-3-90.

BEFORE SHRI ARJAN DEV. PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT, KANPUR.

Industrial Dispute No. 161 of 1987
In the matter of dispute between :

The General Secy.,
Central Bank Employees' Congress (UP),
Central Bank of India, Nayagani, Kanpur.

AND

The Chairman & Managing Director,
Central Bank of India, Chander Muni,
Nariman Point, Bombay-400021.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-1202/423/86-DII(A) dated 9-11-87 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :—

Whether the action of the management of Central Bank of India in not considering Shri S. K. Mehrotra Clerk as regular pass book writer from 16-9-69 and full time workman from 1-1-72 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled.

2. The Industrial dispute on behalf of Shri S. K. Mehrotra, the workman has been raised by the General Secretary, Central Bank Employees Congress (UP) (hereinafter referred to as Union). The case set up by the union is that the workman was initially appointed as parttime as Pass Book Writer on 16-9-69 and he had worked at Guntl No. 5 branch of the bank at Kanpur till 4-11-74 with intermittent breaks not exceeding 3 days at a time. Therefore, from 5-11-74, to 14-7-77 he had worked as part time pass book writer at Meston Road Branch of the Bank at Kanpur without any break. The workman represented to the management of the bank to treat him as permanent pass book writer in terms of Bank's circular based on an agreement dt 23-12-71 entered into between the management bank and the Majority Federation known as All India Central Bank Employees Federation, with regard to back date confirmation, but in vain. Subsequently, the management of the bank deputed Mr. Ayyer, a Sr. Suptd. to examine all cases of part time

pass book writers for being absorbed in permanent service of the bank. Mr. Ayyer then visited Kanpur and entered into an agreement with UPBEU in 1972 providing that such part time pass book writers as had worked full time for a minimum period of 75 days (450 hours) as part time pass book writers, they would be straight away absorbed in the full time service of the Bank. The Union further alleges that the workman was given probationary appointment in clerical cadre on 15-7-77 and posted at Allahabad Branch of the Bank. The Union has therefore, prayed that confirmation of the workman as permanent part time pass book writer should be ordered w.e.f. 16-9-69 with prorata increment deemed to have fallen due and ordered to be released so far as the workman is concerned and that his confirmation as full time clerk w.e.f. 1-1-72 with all consequential benefit should also be ordered.

3. The case is contested by the management. The management pleads that the workman had worked as part time pass book writer from 16-9-69 to 14-7-77 with breaks on purely temporary basis. He was appointed as clerk on probation in the bank on 15-7-77. The management further pleads that as per understanding arrived at on 12-1-72, between the bank and the Majority Union, it was agreed that part time pass book writers who were appointed prior to 1-1-71 and who had been performing the regular duties of clerk a part time from the duty of pass book writer would be appointed in the service of the bank from 1-1-71 (the date 1-1-71 should be considered for the purposes of seniority only). According to the management Shri Mehrotra had been performing the work of only temporary pass book writer and had not been performing regular duties of a clerk apart from the duty of pass book writers. As such his claim is not tenable.

4. The Union also filed a rejoinder but in it 'it' has pleaded no new fact.

5. In support of its case, the Union first filed the affidavit of the workman concerned with certain documents. However, after the close of the evidence of the parties the Union examined Shri Rameshwar Singh, a retired employee of the bank. On the other hand in support of their case management of the bank filed the affidavit of Shri Naresh Mohotra Regional Manager, of the Bank, Regional Office Kanpur.

6. It is a case in which neither side has filed, the circular of the bank alleged by the Union as based on agreement dt. 23-12-71 entered into between the management of the bank and All India Central Bank Employees Association and the agreement which is said to have been arrived at in 1972 between the management bank through Mr. Ayyer and UP Bank Employees Union. So the Tribunal will have to look into the terms of the agreement as referred to by the parties. In para (d) of the claim statement the relevant portion with regard to 1972 agreement reads as under :

Those part time pass book writers who had worked full time for a minimum period of 75 days (450 hours) as part time pass book writer were straight away to be absorbed on full time service.....

7. On the other hand, the terms of the aforesaid agreement have been stated by the management witness in para 5 of his affidavit in the following manner,—

The case of Shri Kishanil Rainai was discussed at length. The Union represented that Mr. Rainai has been performing the duties of regular clerk at frequent intervals apart from the duty of pass book writer. It was agreed that the case of Shri Rainai and similar other cases of Pass Book Writer if they have been performing regular duties of clerk apart from the duty of pass book writer will be verified from the incharge of those offices from their records and it is found that Mr. Rainai and similar other pass book writers have been frequently doing the actual work of a clerk other than the pass book writer duties, such persons will be appointed in the Bank's service from 1-1-71 but they will not be paid any difference of Salary, bonus etc and from

1-1-72 they will be given regular salary but this will be operative only if the facts are properly verified.

Now let us examine the evidence in the light of the above terms. Annexure 9 and 10 filed by the workman with his affidavit refer to the alleged clerical work done by him on different dates between 7-11-69 and 24-12-70 and 27-12-74 and 30-6-70 respectively. In view of the above terms the clerical work alleged to have been done during the latter period has no relevancy. Despite statement annexure IX with regard to the alleged clerical work done by him, the workman in his cross examination has deposed that he was never assigned the job of a clerk and that he had been performing the duties of a part time pass book writer from 16-9-69 to 14-7-77. This statement thus takes away from the very feet of the Union and workman the case set up in the claim statement that he had ever performed clerical duties apart from the duties of a part time pass book writer.

8. The other witness of the Union is Shri Rameshwar Singh. He has deposed that branch No. 5 branch of the bank opened in March 1963 and in the said branch he remained posted from the day it was opened till Nov. 70. He has further deposed that in the said branch Mr. Mehrotra workman remained posted as pass book writer (part time) during 1969 and 1970. His working hours had been from 5 p.m. to 7 p.m. According to him often some clerical work was left unfinished by the clerks and such unfinished work used to be done from the workman by the management.

9. From some of the statements further made by this witness it will become evident that his testimony is not reliable. He has deposed that the management never paid any wages to the workman for the extra work taken from him. And the management taken any extra clerical work from him, the management would have surely paid him extra wages. Then he has deposed that the management had never passed any orders directing the workman to do the work left unfinished by the regular staff. Another important statement made by him is that the workman never worked during normal working hours of the bank, i.e. from witness that he had ever stayed in the bank after normal working hours i.e. after 5 p.m.

10. On the other hand the management witness, who is Regional Manager of the Bank, in his deposition has denied that the workman had ever done the work as shown in Annexure IX of his affidavit. In fact, the workman's affidavit evidence prove nothing. It does not even corroborate the facts stated in the claim statement and the rejoinder. Para 2 of his affidavit is to the effect that he has filed written statement and rejoinder in reply to the written statement of the management and that to prove his case he is filing this affidavit alongwith documents. In para 3 he has stated that in view of the claim statement and rejoinder filed by him he is entitled to the relief claimed. There is nothing in his affidavit.

11. Even if it be believed that the workman had done work of clerical nature as given in annexure IX in view of the statement made by Shri Rameshwar Singh in his cross examination that the workman normally did those work also after office hours of the bank between 5 p.m. and 7 p.m. and some times even a little more, it cannot be held that he had performed the job of a clerk for full day on dates given. The extract of 1972 agreement to which I have referred to above means that only such part time pass book writers were to be given the benefits who had worked as full time clerks for 75 days during their engagement as part time pass book writers. As we have seen he was never appointed as a clerk nor he had done continuously clerical work of regular nature for 75 days.

12. In view of the above discussion of evidence and circumstances, I find that the workman concerned cannot claim benefit under the agreement as pleaded by the Union. This being so, he is not entitled to any relief.

13. The reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer
[No. L-12012/423/86-DII(A)]

का. आ. 1098 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, कन्द्राय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन के संबंध निवाजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदोष्ट औद्योगिक विवाद में कन्द्राय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो कन्द्राय सरकार का 16-3-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1098.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 16th March, 1990.

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 104 of 1988

In the matter of dispute between :

Smt. Sarojni Pamnani C/o Shri P. N. Tewari 165
Sobatoagh Allahabad.

AND

The Regional Manager, Punjab National Bank Regional
Office S-20, 56-D The Mall Varanasi Cantt.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/825/87-D.II (A) dated 21st July, 88 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Rajasthan Commercial Bank (now merged with Punjab National Bank) in terminating the services of Smt. Saroni Pamnani, clerk w.e.f. 25-5-86 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?

2. On 5-2-90, an application has been moved by Smt. Saroni Pamnani, the concerned workman, for giving no dispute award in the case for reasons stated in the application.

3. The contents of the application have been read over and explained to the workman in the presence of the authorised representative of the parties Shri P. N. Tewari, General Secretary, Punjab National Bank Staff Association U.P. representing the workman and Shri R. S. Srivastava, representing the management and duly verified before me.

4. In para 2 of the application it has been stated by the workman that on her approaching the management of the Punjab National Bank, the management have shown their intention to consider her case sympathetically on compassionate grounds. In para 3 she has stated that in view of it she is no more interested in prosecuting the present dispute referred to this Tribunal by the Central Government for adjudication.

5. Hence, a no dispute award is given in the present case.

6. Reference is decided accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer
[No. L-12012/825/87-D.II (A)]

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1990

का. आ. 1099—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार विजया बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 बम्बई के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, 10th April, 1990

S.O. 1099.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Vijaya Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

P. D. Deshpande, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-2/42 of 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of Vijaya Bank,
Bombay,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Bank—Shri R. K. Shetty, Advocate.

For the Workmen—Shri S. M. Dharap, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra
Bombay, the 15th March, 1990

AWARD

The Central Government by their order No. L-12011/16/86D.IV (A) dated 25-8-1987 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act :

“Whether the demand of the subordinate staff of the Vijaya Bank, Bombay (and all offices and branches in Bombay Zone) regarding providing them separate lockers to each with locking arrangement for keeping personal dress during office working hours and little secluded place for changing clothes within Bank premises just before and after office duty hours, is justified and reasonable? If so, to what relief the subordinate staff of all branches/office of Bombay Zone and entitled to?”

2. The case of the Vijaya Bank Employees Association as disclosed from the statement of claim (Ex. 2/W) filed by the General Secretary, in short, is thus :—

The service conditions of the workmen of Vijaya Bank are governed by various Awards and Bipartite Settlements. As per Clause 2 of the settlement dated 5-1-1987 all permanent full time members of the subordinate staff and the permanent part-time workmen in subordinate cadre working for not less than six hours per week, should be supplied with three sets of terry khadi uniforms once in two years and one set of woolen uniform once in three years. As per the provisions of Bipartite Settlement (Fourth) dated 17-9-1984, washing allowance is to be paid by the Bank to the subordinate staff entitled to uniforms at the rate of Rs. 15 per month at all centres with effect from 1-9-1984. Further, as per the provisions of the said settlement all members of staff who are supplied with uniforms are to wear them while on duty and in clean condition.

(ii) The employees serving in different branches of the Bank are staying not necessarily near the respective branches of the Bank. They have to come to the Branch travelling in the crowded trains and buses. This causes physical strain to them and also damages the dresses worn by them. Further, in case they wear the uniforms while reporting for duty, the same can no longer remain clean and well laundered. Therefore, the only course left to the workmen was to daily carry them with them or leave the uniforms in the Bank's premises, wear them while reporting for duty by chance the civil dress, and again leave them or carry after duty hours, are over. Faced with these difficulties the members of the subordinate staff had made a demand to the Bank that they be provided with lockers with locking arrangement to keep their uniform or the civil dress at a secluded place within the Bank premises. The Bank did not, however, concede to the request of the Association. Therefore, the workmen raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (C), Bombay. The conciliation proceedings ended in failure, and therefore the Central Government made the reference as above.

3. The Association further alleged thus :—

Due to staggering of duties of sub-staff on account of which few sub-staff have to report for duty even after commencement of the office hours and for want of secluded place, they find it difficult to change the dresses and wear uniforms supplied by the Bank. Further, at certain places the workman lost their valuables kept in their civil dress kept in the open place in the Bank premises for want of lockers. Even the uniforms kept in the open place at two branches namely Mahim and Exceisor have been found lost, and the Bank could not take proper steps to restore the things to the concerned sub-staff. The Supply of uniforms by the Bank to the workmen as a service condition also implies the condition of providing suitable space for changing the dress, and lockers or some other suitable device for safe-keeping of the uniform/dress by the Bank. No provision exists in any of the awards/settlements requiring the members of subordinate staff to wear the uniforms at the time they leave their residence for duty nor does the bank rightly require them to do so.

The Association, therefore, prayed that the demand of the members of subordinate staff working in the Bombay Zone of the Bank for providing secluded place for changing the dress and separate lockers etc. be held by this Tribunal as just and proper.

4. The additional Manager of the Vijaya Bank, by his written statement (Ex. 3/M) opposed the said claim of the Association, and in substance contended thus :—

The service conditions of the workmen are governed by Sastry and Desai Awards and four Bipartite Settlements entered into between the Indian Banks' Association and the Unions of workmen. As per the provisions of the Awards and settlements, the workmen are entitled to uniforms/liveries and washing allowance. Further, as per these provisions, the members of the staff who are supplied with uniforms are to wear them while on duty in clean condition, and not wearing of the uniform while on duty constitutes a minor misconduct. However, the said Awards and settlements do not stipulate for providing lockers to keep the personal dress of sub-staff members during working hours, or for a secluded place for changing the clothes within bank premises just before and after the office duty hours. As such the Bank is not obliged to provide the said facilities to the workmen. Further, none of the unions who are parties to the Bipartite Settlements including the National Organisation of Bank Workers to which the Association in question is affiliated had raised any demand for the said facilities. Therefore, the demand of the Association in question is not a necessary or essential conditions of the service of the workmen. The Bank has not extended the facilities of lockers and secluded places to the members of sub-staff in any of the branches of the Bank. None of the unions functioning in

Vijaya Bank had made such a demand. The facilities that have been demanded by the Association are only a concession, and the same cannot be claimed as a matter of right and cannot be legally enforced. The matter referred to this Tribunal does not constitute an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. As such this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the matter under reference. Further the reference is not maintainable as the issue referred is beyond the scope of the subject matter as enumerated in the second and third schedule of the said Act.

5. The Bank further contended thus :—

The said Association implicitly admitted in its reply to the statement of the Bank before the Assistant Labour Commission (C), Bombay, that the members of sub-staff can use the stationery room or lunch room for change of dress. Even at present the civil dresses of the members of the subordinate staff are kept in some safe place within the premises of the Bank without causing any inconvenience to them. Any direction to the Bank to provide individual lockers to each member of sub-staff and to provide a secluded place would result in wasteful expenditure of public funds. The wear and tear of the cloths is a natural process and is not a problem confined to the employees of the Bank at Bombay only. As the Bank is paying the washing allowance to the members of sub-staff, the Bank can expect them to wear uniform in clean and good condition during the working hours. The facilities demanded by the Association is neither a welfare activity nor an essential service condition. Out of 28 Public Sector Banks, only seven banks are reported to have extended the facilities now demanded by the Association. Out of 58 Banks who are parties to the Bipartite settlements, only seven Banks are reported to have provided the facility in question. The members of sub-staff are using the Stationery room or dining room or other rooms for changing their dresses, either during the office hours or beyond office hours or before office hours. The isolated incident of theft of clothes and valuables, cannot be as basis for demanding the facilities of lockers and secluded place. Even the clerical staff who are not provided with uniform, are not paid washing allowance and are required to attend the office with clean dress and any disregard of these instructions by the clerks constitutes a minor misconduct. The demand of the Association is not tenable in law and in facts.

The Bank, therefore, prayed for the dismissal of the claim of the Association.

5. The Issues framed at Ex. 5 are :—

- (1) Whether the Bank is not obliged to provide the lockers to the subordinate staff to keep the personal dress during the working hours, and to provide secluded space to change the clothes within the Bank premises, as the different Awards and the Bipartite Agreements between the parties do not stipulate any such condition therein ?
- (1A) Whether the existing facilities provided by the Bank, as described in para 2 and 18 of the Written Statement of the Bank, are not adequate ?
- (2) Whether there is no justification on the part of the Union in question in placing forth the demands in question ?
- (3) Whether the demands in question do not fall within the scope of an 'industrial dispute' as defined in Section 2(k) of the Industrial Disputes Act and as such, the reference in question is not tenable in law ?
- (4) Whether the demand of the subordinate staff of the Vijaya Bank, Bombay (and all offices and branches in Bombay Zone) regarding providing them separate locker to each with locking arrangement for keeping personal dress during office working hours and little secluded place for changing clothes within Bank premises just before and after office duty that there is no provision in any of the Awards

(5) If so, to what relief the subordinate staff of all branches/offices of Bombay Zone are entitled ?

(6) What Award ?

7. My findings on the said Issues are :—

- (1) The Bank is obliged to provide lockers, and secluded place.
- (1A) Existing facilities not adequate.
- (2) There is justification.
- (3) Industrial Dispute exists and the reference is maintainable.
- (4) Justified and reasonable.
- (5) As per the final order below.
- (6) As per the final order below.

3. Four witnesses have been examined on behalf of the Employees Association and four witnesses have been examined on behalf of the Vijaya Bank management. I, firstly, will deal with the oral evidence on record. The first witness of the Association is Shri Vijaykumar Bhagwat Narkhede (MW-1) who is serving as Staff Officer Grade 'A' in Management Section, Reserve Bank of India, Bombay. In substance he stated in his examination-in-chief thus :—

The Reserve Bank of India has provided lockers to all the Class IV employees (both full time and part-time) to enable them to keep their personal belongings and clothes. No separate accommodation for changing clothes has been provided. However, the lockers and cupboards are so arranged that some enclosed space is prepared which can be used by the Clause IV employees to change their clothes. This arrangement exists in all the offices/Departments of the Bank in Greater Bombay. The Locker arrangement is in existence in the Bank since the last 25 years in all branches. In his cross-examination he stated that there are 25 nationalised Banks in India, including the Vijaya Bank, and no provisions has been made in any of the Awards or settlements regarding providing of Lockers etc. to the employees.

(ii) The Second witness is Shri F. R. Pinto (WW-2) employed as Middle Management Scale II Officer of State Bank of India, Bombay. He also stated in his evidence that there are arrangements of Lockers practically in all branches of the State Bank of India in Bombay. The Lockers are provided for keeping the uniforms and belongings of the employees of the Bank. There is no separate accommodation for changing the clothes. However Lockers are placed in a secluded place so that the employees can change the dress there and the public has no excess to that place. There are ladies sub-staff members. Separate toilet is provided for ladies and it is used by them for changing the clothes etc. The Locker arrangements are in existence since the last without 25 years.

In his cross-examination he stated that the State Bank of India is the number one nationalised Bank in India. He further admitted in his cross-examination that in case the Bank employees put on the Uniforms at their residence and come to the Bank, and return back to their houses with the uniforms on their persons, it is not objected to by the Bank.

(iii) The third witness of the Association is Shri Madhav Prabhakar Nemjoshi (WW-3), an officer working in the Vigilance Section, Zonal office of the Central Bank of India since, the last ten years. He stated in his evidence thus :—

There is Lockers arrangements in the Central Bank of India at Bombay. The Lockers are belonging to the Bank. He particular Locker is provided to any particular member of the staff. The members of staff are using the Lockers since long and it is not objected by the Bank. The Bank is not charging any amount for the use of Lockers by the employees. At the Head Office of the Bank and at some of the branches, there are separate toilets for the ladies.

In his cross-examination the said witness admitted that there is no provision in any of the Awards or settlements between the Bank and the Unions regarding providing of Lockers to the Bank employees. It is seen from his cross-examination that there are about 2,000 Class IV employees in that Bank in Bombay, and out of them half of the

members of staff is getting the facilities of Lockers. This witness also admitted in his cross-examination that in case an employee intends to put on the uniform at his residence and then come to the Bank, it is left with his will, but normally the employees will not like to do so.

- (iv) The last witness is Shri Ignatius Paul Mondonca (WW-4), Chief Manager, Industrial Relations, Central Office, Bank of Baroda, Bombay. It is seen from his evidence also that Lockers have been provided to the employees of the Bank, and this arrangement is in existence since about 1970 or 1971. In some of the Branch offices of the Bank and big offices there are separate toilets for the ladies. This witness also admitted in his cross-examination that there is no provision in any of the Awards or the settlements for supply of Lockers to the Bank employees. From his cross-examination it is further seen thus :—

There have been demands for supply of Lockers, but not for providing secluded place from the workmen. The demand was regretted. However, Lockers which were already in existence for the use of the Bank employees were continued. The Lockers were last supplied about six or seven years back, and thereafter no new Lockers have been supplied. The Lockers have been provided to more than half the number of sub-staff in Bombay. In case the Bank employees put on the uniforms at their residence and then come to the Bank or return back with the uniform on their persons, it is not objected to by the Bank. Thus, it is seen from the evidence of these four witnesses that arrangements have been made for the use of Lockers by the sub-staff members for keeping their clothes in the Bank in different branches. Bombay in Reserve Bank of India, State Bank of India, Central Bank of India, and the Bank of Baroda, even though the different Awards and settlements did not provide for the granting of Lockers to the employees by the Banks.

9. According to Vijaya Bank management, the Lockers have not been provided by the other Bank and the four witnesses have deposed about it. The first witness for the Bank management is Raja Joseph Dominic (MW-1), serving as Personnel Officer in Corporation Bank at the Zonal Office, Bombay. In his evidence he stated thus :—

No facilities of Lockers have been provided in the said Bank, nor any secluded place for changing the clothes in the Bank premises has been provided. The Association of sub-staff had made a demand for providing for lockers and secluded place but that demand has not been agreed to by the management.

In his cross-examination he stated that out of the sub-staff members, a few persons come with uniforms on their persons and the rest put on the uniforms in the Bank premises. After putting on the uniforms in the Bank premises the employees concerned put their original clothes in their hand-bags.

- (ii) The other witness for the management is Shri Gulzar Suhai Dhaliwal (MW-2) working as Law Officer, in the Punjab and Sind Bank, Bombay. He stated in his examination in chief thus :—

That bank supplies uniforms to Class IV employees. However, the Bank does not provide any Lockers to any of the employees in any of the branches of the Bank. No demand has been made by any of the employees in that respect. That Bank has not provided any secluded place for changing clothes in any branch. The employees can come to the Bank with uniforms on their persons, and return home with the uniforms on their persons, as they are paid the necessary washing allowance.

In his cross-examination he stated thus :—

There are separate toilets for the lady employees in the branches of the Bank. Some of the employees come with uniforms on their person from their residence and some change the clothes and put on the uniforms in the Bank premises. The Members of the sub-staff go to the toilets and change their clothes.

- (iii) The third witness for the Bank management is Shri Amrose Joseph Moraes (MW-3), Personnel Officer in Andhra Bank, Bombay. He stated in his evidence thus :—

Andhra Bank has not supplied Lockers to the sub-staff in Bombay except in one branch i.e. Main Branch, Fort, Bombay. No Lockers have been provided in any of branches out of Bombay. There are about 170 sub-staff members in Bombay Zone. However, no demand has been made by the sub-staff members for the supply of Lockers or secluded place to them. The settlements between the Bank and the unions did not make any provision for the supply of Lockers and secluded places to the sub-staff. Some of the members of sub-staff who wear the uniforms in the Bank premises keep their personal dresses in the drawer or cup-boards of the Bank.

In his cross-examination he stated that about 10 to 12 Lockers have been provided for the use of sub-staff in the Main Branch of the Bank.

- (iv) The last management witness is Shri Heror Sakhar Das Shetty (MW-4), who is senior Manager of the Vijaya Bank, in Bombay. In substance he stated in his examination-in-chief thus :—

The relationship between the employer and the employees of the Bank are governed by the different Bipartite Settlements. The Bank has not supplied any Lockers to any of the members of sub-staff in any of the Branches of the Bank, for keeping their dresses. The Bank has not supplied or provided any separate or secluded place for the members of sub-staff in Bombay to change their dresses. They change their dresses in the record room, which is a secluded place. The employees after changing their clothes keep their original clothes in the racks in the R.O. rooms. About 70% of the sub-staff members come with uniforms on their persons from their houses, and return back with the uniforms on their persons. The Bank management has not objected to the members of sub-staff coming to the Bank with the uniforms on their persons from their houses, and return back with the Uniforms on their persons. The Bank pays washing allowance to them every month. The percentage of the members of the Union, which has raised the present dispute, is a small one. It is seen from his cross-examination that the members of sub-staff in each branch is five.

Thus, according to the Vijaya Bank management, the members of sub-staff are not entitled to Lockers for keeping their clothes, or a separate secluded place for changing their dresses.

10. Now, I will turn to the different Issues framed in this proceeding.

Point No. 1

11. According to the Bank management, the Bank is not obliged to provide the Lockers to the subordinate staff to keep the personal dress during the working hours, and to provide a secluded space to change the clothes within the Bank premises, as the different Awards and the Bipartite Settlements between the parties do not stipulated any such conditions therein. It is true that the different Bipartite settlements between the Unions and the Bank management have not made any provisions for the supply of Lockers to keep their clothes or providing secluded place to change their clothes there. Even then I find that the employees concerned are not debarred from making such a demand, as the demand in question is quite just and proper. The demand is incidental to the conditions of service of the employees, and as such the Bank is bound to satisfy with the needs of the employees. As per the provisions of the last Bipartite Settlement between the Unions and the Bank, the Bank is to supply uniforms to the members of sub-staff and the members of sub-staff are required to put on the Uniforms while on duty, and that too, in a clean and laundered condition. Many of the employees come to the Bank from long distance by travelling in crowded trains or buses, and as such in case they put on the uniforms on

their persons from their residence, their dresses are not likely to remain in a clean and laundered condition. Even though the Bank management does not object to the employees putting on their uniforms all their residence and coming to the Bank with the uniforms on their persons, still it is advisable that the employees come to the Bank with their private clothes on their persons and put on the uniforms after coming to the Bank. Therefore, the Bank is bound to provide the Lockers to the Sub-staff members to keep their personal clothes in the Bank premises, though the different Bipartite Settlements have made no provision about it. Issue No. 1 is found accordingly.

ISSUE No. 1-A

12. According to the Bank management, the existing facilities provided by the Bank as described in paras 2 and 18 of the written statement is adequate and the members of sub-staff are now using the stationery room or lunch room for changing their dresses, and keep their civil dresses in some safe place. According to the Employees Association, the place wherein they now change their dresses very dirty, and not a clean place. I find out that the present practice of keeping the clothes by the employees in some drawer etc. in the Bank premises is not adequate, and further, the secluded place where the employees change their dresses is not quite clean. As such the Bank must provide a clean secluded place for the use of the members of sub-staff. Issue No. 1-A is found accordingly.

ISSUE No. 2

13. According to the Bank management, there is no justification on the part of the Union in question in placing forth the demands in question. I find that it is not so. As noted above, the demand in question is quite just and proper. Therefore, Issue No. 2 is found accordingly.

ISSUE No. 3

14. According to the Bank management, the demands in question do not fall within the scope of an 'industrial dispute' as defined in Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, and as such, the reference in question is not tenable in law. Under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, an industrial dispute means any dispute or difference between employers and the workman, which is connected with the employment, or the terms of employment or with the conditions of labour, of any person. As per the provisions of the present Bipartite settlement between the parties, the members of sub-staff are required to put on uniforms in a clean and laundered condition and the management also is to pay the washing allowance to them. According to the employees, in case they come to the Bank with the uniforms on their persons by travelling in trains or buses, they cannot keep their uniforms in a clean and laundered condition. As such, they must be provided with Lockers and a secluded place to keep their personal clothes and to change their clothes. According to the Bank management no such facility is necessary. I find that an industrial dispute exists between the parties, as the terms of employment and conditions of labour of the said employees are involved. Therefore, the present reference is quite tenable in law.

ISSUE No. 4 and 5

15. According to the Bank management, providing of Lockers etc. is a matter only of concession and grace, and the employees cannot demand it as of right. As noted above, the demand of the workmen in question is quite just and reasonable, and as such, it cannot be said that the Bank used to make the necessary arrangement by way of only grace or concession and that the workmen are not entitled to it. According to the Bank management, the other four Banks mentioned above, in which the arrangements of Lockers have been made for the workmen are very big banks, and they cannot be compared with the Vijaya Bank. In my opinion, Vijaya Bank is also not a very small Bank. According to the Bank management, in case the Lockers are to be provided in all branches of the Bank throughout India, very huge amount will have to be spent and there will be unnecessary wastage of money. It is however, seen that the number of the members of sub-staff per branch is not much, and as such the expenses of providing the Lockers etc. per branch will not be a big one. Apart from that, as the demand in question is quite just and reasonable, the Bank must concede to it irrespective of the fact whether it is a small Bank or otherwise, and whether the expenses over the matter

would be a very large one or otherwise. As per the circular dated 7-3-1986 and 8-8-1988 (Exhibits 24/W and 31/W), the members of sub-staff have been directed by the Bank management to wear the uniforms while on duty and that the failure to put on the uniform would be viewed seriously. Therefore, in case the members of sub-staff have to put on clean uniforms in laundered condition while on duty, the Bank must also see that they get the proper and sufficient secluded place in the Bank premises to change their personal dresses and put on the uniforms, and also get sufficient space to keep their personal dresses in the Bank premises. According to the Bank management, the members of sub-staff are expected to come to the office 15 minutes earlier, and also to leave the Bank 15 minutes after the closure of the Bank and that they can change the dresses during the said period of 15 minutes in the Bank premises, and there will be no question of any secluded place during that period. It may be noted that anybody may come in at any time. As such it cannot be said that the place would be a secluded one even during the said period of 15 minutes. It is true that the Bank has no objection if the workmen come to the Bank with the uniforms on their persons and return back with the uniforms on their persons. Even then in order that the uniforms always remain clean and in a laundered condition, it is necessary that proper arrangements are made in the Bank premises to keep those dresses in a safe place. According to the workmen, the place where now they change their clothes in different branches of the Bank, are unclean and dirty. The Bank should, therefore, see that the secluded place where the workmen change their clothes in a clean place. As the said four Banks provide Lockers to the workmen in their Banks, Vijaya Bank can also be directed to provide the Lockers etc. to the workmen in their branches. Therefore, I find that the demands of the subordinate staff of the Vijaya Bank, Bombay (and all offices and branches in Bombay Zone) regarding providing them separate locker to each with locking arrangement for keeping personal dress during office working hours and little secluded place for changing clothes within Bank premises just before and after office duty hours, is just and reasonable. Issue No. 4 is found in the affirmative. As such they are entitled to the provision of Lockers and secluded place in the branches of the Bank. Issue No. 5 is found accordingly.

ISSUE No. 6

16. The following Award is, therefore, passed :—
AWARD

- (i) The demands of the subordinate staff of the Vijaya Bank, Bombay (and all offices and Branches in Bombay Zone) regarding providing them separate lockers to each with locking arrangement for keeping personal dress during office working hours and little secluded place for changing clothes within Bank premises just before and after office duty hours, is just and reasonable.
- (ii) The management of Vijaya Bank is hereby directed to provide Lockers to members of sub-staff individually or collectively in all branches and offices in Bombay Zone to keep their personal dresses therein, and also to make provision for a clean secluded scheduled place of sufficient dimension in the record room or the stationery room or in any other place in the Bank premises to enable the members of sub-staff to change their dresses.
- (iii) The necessary arrangements be made within three months.
- (iv) The parties to bear their own costs of this Reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer
[No. I-12011/16/86-D.IV (A)]

का. मा. 1100—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार यको बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्गत में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1100.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the UCO Bank and the their workmen, which was received by the Central Government on the 4-4-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 7 of 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Commercial Bank, Patna.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri (Dr.) Sadanand Jha, Advocate
For the Workmen—Shri Aftab Alam, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Banking.

Dated, the 10th March, 1990

AWARD

By Order No. L-12012/525/86-D.II(A), dated, the 11th August, 1987, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of UCO Bank, Patna, in terminating the services of Shri Shailendra Kumar Yadav, Water-Boy-Cum-Peon, Deoghar Branch, w.e.f. 3-9-85 without observing the provisions of Section 25F of the I.D. Act, and not providing him employment after 3-9-85 on regular basis is justified. If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the management of United Commercial Bank, Patna, as appearing from the written statement-cum-rejoinder submitted, details apart, is as follows :

The management of United Commercial Bank, Patna (hereinafter referred to as the Bank), before this present reference gave a detailed reply to the Asstt. Labour Commissioner (C), Patna, stating that the concerned person, Shailendra Kumar Yadav, was not a workman within the meaning of Industrial Disputes Act, and hence he was not entitled to any benefit under Sec. 25F of the said Act. Subsequently during conciliation the management informed the Asstt. Labour Commissioner (C), Patna, by letter dated 3-7-86 that Shailendra Kumar Yadav was not given any appointment by the Bank and as such, claim for continuance in service was pointless. It was also pointed out that he had not worked for 240 days in any period of 12 months in Deoghar Branch of the Bank. He was never appointed as Peon-cum-Waterboy by the Bank. He was, however, engaged by the Deoghar Branch of the Bank (although not at the instance of the competent authority). For doing certain odd job for a part period of working day and was paid remuneration as agreed upon. It was not a regular appointment in Bank's service and even if, such engagement is treated as regular appointment which, however, is strongly denied, the said appointment was not regular nor legal as the Branch Manager has no authority to appoint a person in Bank's regular employment without the sanction of the competent authority. It is well settled position of law that if a person is appointed irregularly, the termination of his service has the only effect of declaration that from the beginning there was no valid appointment. The Branch Manager had only taken some works from his and made payment to him not for the whole days of work, but

for the quantum of work done by him. As stated earlier he was not given any regular employment and for regular employment in any commercial Bank there are certain procedure which admittedly have not been followed in the case of Shailendra Kumar Yadav. The usual procedure is to assess the vacancy and to fill it up through Employment Exchange as per Government directive. Direct appointment of candidates is not made nor is it permitted. After selection of candidates letters offering employment detailing the terms and conditions are addressed to the candidates and after their acceptance of terms and conditions of employment unconditionally, the deal is clinched. Such candidates are allowed to join duties. Shailendra Kumar Yadav was never appointed by the Bank in its regular employment nor was any letter of appointment issued to him indicating the terms and conditions of his employment in the Bank nor was he required to sign the Attendance Register. Since he was not an employee of the Bank, the question of termination of his service did not arise. He appeared in a test for selection and failed and consequently he was not selected. This being the position, his claim either for continuity of service or regularisation of his service does not arise. Besides his case is covered by sub-clause (b) of clause (oo) of Section 2 of the Industrial Disputes Act as it amounts to non-renewal of contract of employment between the management and workman after expiry of stipulation of taking work from him.

3. The case of the concerned workmen as spelt out in the written statement submitted by him, briefly stated, is as follows:

Shailendra Kumar Yadav, the concerned workman, was employed as Water-boy-cum-Peon in the Deoghar Branch of the Bank on 24-4-78 on daily wage basis. He had been continuously working and was under the employment of the Bank in Deoghar Branch on 24-4-78. He was initially paid Rs. 5 per diem as wages which was increased to Rs. 8 per diem in April, 1980 and later it was further increased to Rs. 10 per diem on 4-2-85. He was working in the said Branch of the Bank from 10 A.M. to 6 P.M. The wages paid to him being less than the minimum wage fixed by the State Government, he requested the Branch Manager of Deoghar Branch for paying him minimum wages prescribed for the post. But his legitimate demand was taken as an affront by the Branch Manager, who acting in an autocratic way dismissed him from service with effect from 3-9-85. Prior to his dismissal he was not given any notice nor was he paid his legitimate dues to which he was entitled on account of his continued service in the Bank since 1975. The termination of his service was in breach in the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act and the position being so, the action of the management in terminating his service is wholly bad, illegal and unsustainable. The wages paid to him during the tenure of his service were credited in his account and entered in the Pass Book of the Bank opened in his name. During the period of one year immediately prior to his termination of service i.e. 4-9-84 to 3-9-85 he worked for 301 days and was paid wages for 298 days. He, by his letter dated 5-9-85 addressed to the Branch Manager of Deoghar Branch, protested against the illegal termination of his service. In that letter he stated that since 24-4-78 he had been working in the said Branch of the Bank as Peon-cum-Waterboy continuously on daily wages and everybody was satisfied with his work. He pointed out in that letter that he demanded minimum wages and was assured by the Branch Manager that minimum wages will be paid to him but that assurance was never kept. Ultimately, he was dismissed from service by the Branch Manager from 3-9-85 without any notice and without payment of any compensation to which he was entitled under the law. At the time of dismissal no letter was issued to him and the termination of service was effected orally by the Branch Manager. Being aggrieved by the illegal termination of service he raised an industrial dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Patna. The A.L.C.(C) initiated conciliation proceeding but that ended in a failure on account of recalcitrant attitude of the management. He is a workman within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act and the termination of his service is nothing but retrenchment within the meaning of Sec. 2(oo) of the Industrial Disputes Act. He was not given one month's notice in writing indicating the reason for retrenchment nor was he paid one month's wages in lieu of such notice. He has not even been offered any retrenchment compensation as required under

Sec. 25F of the Industrial Disputes Act. He was a full time employee of the Bank since his employment in 1978 and he had worked for more than 240 days in each year prior to his termination of service. The Branch Manager of Deoghar Branch of the Bank submitted a statement in response to a telegram received by him from Divisional Office of the Bank at Patna. In the said statement sent on 12-8-86 it was specifically mentioned that he had worked in the Bank since 24-4-78 for a total period of 7 years, 5 months almost continuously in the post of Waterboy-cum-Peon. Anyway, the action of the management in terminating his service is illegal, arbitrary and unjust. In the circumstances, he has prayed that the Tribunal be pleased to hold that the action of the management in terminating his service is illegal and unjust.

4. In rejoinder to the written statement of the concerned workman, the management has reiterated that the concerned workman was not a workman within the meaning of Sec. 2(s) of the Industrial Disputes Act and that he was never appointed by the Deoghar Branch of the Bank as Waterboy-cum-Peon. The Branch Manager has no authority to appoint a person in Bank's regular employment without the sanction of the competent authority. Since he was not an employee of the Bank the question of giving him notice or wages in lieu of notice and compensation as per provisions of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act does not arise. He has never worked for 301 days in a period of one year immediately preceding to 3-9-85. It is alleged that the statement of the Branch Manager is collusive document created by the Branch Manager in collusion with the concerned person. The management has totally denied that the concerned person ever worked for the Bank from 10 A.M. till 6 P.M.

5. In rejoinder to the written statement of the management, the concerned workman has stated that he is a workman within the meaning of Sec. 2(s) of the Industrial Disputes Act and that he worked for the Bank from 24-4-78 to 3-9-86 from 10 A.M. to 6 P.M. He has further asserted that the management illegally terminated his service without complying with the mandatory provision of retrenchment and notice as enshrined in Section 25F of the Industrial Disputes Act.

6. The management has examined only one witness, namely MW-1 Ram Adhar Singh who was posted as Branch Manager of Deoghar Branch of the Bank from 1976 to 1987 but laid no documentary evidence in support of its action. On the other hand, the concerned workman examined himself as WW-3 and two other witnesses, namely, WW-1 Bijoy Kumar Gupta who has been working in the Deoghar Branch of the Bank since 1971 and WW-2 Pishnu Pada Bhattacharjee, working in the Deoghar Branch of the Bank since 1981 and laid in evidence a mass of documents which have been marked Exts. W-1 to W-7/2.

7. It is its irrefragable position that the service condition of the employees of the Bank including the employees on subordinate cadre are governed by Sastry Award and Desai Award as modified from time to time by Bi-partite settlement arrived at between the employer and the employees. The Sastry Award comprehends classification of employees as mentioned herein below :

"508. Classification of employees—We direct that employees shall be classified as :—

- (a) Permanent employees;
- (b) Probationers;
- (c) Temporary employees; and
- (d) Part-time employees;

these expressions having the following meanings :

- (a) "permanent employee" means an employee who has been appointed as such by the Bank.
- (b) "probationer" means an employee who is provisionally employed to fill a permanent vacancy or post and has not been made permanent or confirmed in service;
- (c) "part-time" "employee" means an employee who does not or is not required to work for the full period for which an employee is ordinarily required to work and who is paid on the basis that he is or may be engaged in doing work elsewhere.

Neither the Desai Award nor any Bi-partite settlement has made any departure from this classification of employees as rendered in the Sastry Award. It is necessary to keep in view 1023 GI/90—7

this classification of employees of the Bank in order to consider and decide the present industrial dispute.

8. The case of the management of the Bank is that the concerned workman, Shailendra Kumar Yadav was never appointed by the Bank as Peon-cum-Waterboy, but that he was engaged by the Deoghar Branch of the Bank for certain odd jobs for a part period of working day and he was paid remuneration as agreed upon. It is the further case of the Bank that the concerned workman was not an employee employed by the Branch Manager as regular employee and that procedure for regular employment in commercial Bank admittedly has not been followed in the case of the concerned workman and that the usual procedure of the Bank is to assess the vacancy and fill it up through Employment Exchange as per Government directive and direct appointment of candidates is not made nor is it permitted.

The case of the concerned workman is that he was employed in the Deoghar Branch of the Bank on 24-4-89 as Waterboy-cum-Peon on daily wage basis and that he worked in that capacity from 24-4-78 to 2-9-85 and that he was dismissed from service by the Branch Manager with effect from 3-9-85. Now, the question that comes to the fore of my consideration is whether the concerned workman was appointed/engaged as Waterboy-cum-Peon in the Deoghar Branch of the Bank on 24-4-78 and who appointed or engaged him as Waterboy-cum-Peon or he was engaged for doing certain odd jobs for a part period of working day at remuneration agreed upon.

9. MW-1 Ram Adhar Singh is the sole witness for the Bank. His evidence discloses that he was posted as Branch Manager of Deoghar Branch of the Bank from 1976 to 87 and that during his tenure of service the concerned workman was engaged as Waterboy. Shri Singh has admitted that the concerned workman was engaged as Waterboy in 1978 and that no letter of appointment was issued to him. The concerned workman figuring as WW-3 has vouched for the fact that he was appointed in the post of Peon by Ram Adhar Singh, Branch Manager of Deoghar Branch of the Bank. It is established from evidence that the concerned workman was engaged as Waterboy or Peon in the Deoghar Branch of the Bank in 1978 by Ram Adhar Singh, the then Branch Manager of the Bank. Documentary evidence, such as, the certificate issued by the Asstt. Branch Manager of Deoghar Branch dated 6-1-85 (Ext. W-2) in favour of the concerned workman and the letter of the Branch Manager of Deoghar Branch to the Divisional Office (Ext. W-4) confirms this position. Thus, the conclusion is reached that the concerned workman was engaged/appointed by Sri Ram Adhar Singh, the then Branch Manager of Deoghar Branch of the Bank as Water-boy-cum-Peon in 1978.

10. Dr. Jha has submitted that since the concerned workman was not regularly appointed there exists no relationship of master and servant between the Bank and the concerned workman and so he cannot be considered to be workman within the meaning of Sec. 2(s) of the Industrial Disputes Act. Shri Jha has cited the decision reported in AIR 1957 Madras 688 in this context.

11. There can not be any dispute over the legal position as submitted by Dr. Jha. But the point is whether the Branch Manager had no authority to engage/appoint the concerned workman as Waterboy-cum-Peon.

MW-1 Ram Adhar Singh, the then Branch Manager has stated emphatically that he had no authority to give appointment to anybody and that recruitments were required to be done through Employment Exchange and that too by the higher authority. In cross-examination he has admitted that he got power of attorney from the higher authority and he was not empowered by the power of attorney to appoint any casual worker. He had denied the suggestion that he appointed the concerned workman on the basis of power of attorney. But this power of attorney has not been produced before this Tribunal to show that the Branch Manager had no authority to appoint any workman. In the circumstances, there is reason to believe that had the power of attorney been produced that would have not helped the case of the management. That apart, another intriguing question is left unanswered if the statement of Branch Manager is believed that he had no authority to appoint any workman. If he had no such authority then how could he engage or appoint the concerned workman as Waterboy-cum-Peon? The Branch

Manager has not offered or preferred any explanation for his action. There is no vestige of evidence on record that the higher authority came down upon the Branch Manager for his supposed indiscreet or unauthorised action. The anomaly of these circumstances, unmistakably indicate that the Branch Manager had authority for appointing the concerned workman as Waterboy-cum-Peon atleast on purely temporary basis. This being my conclusion, I am constrained to hold that the action of the Branch Manager in appointing the concerned workman as Waterboy-cum-Peon on purely temporary basis was neither illegal nor irregular. Hence, the contention of Dr. Jha that the concerned workman has no right to continue in service by reason of his allegedly appointed illegally and irregularly by the Branch Manager founders on the ground. Consequently it follows that there was relationship of master and servant between the management of the Bank and the concerned workman and so the concerned workman should be held to be a workman within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act. In this view of the matter the present industrial dispute is maintainable.

12. It is the emphatic case of the concerned workman that he was appointed/engaged as Waterboy-cum-Peon on 24-4-78 and worked in that capacity till 3-9-85. The fact relating to the length of service of the concerned workman has not been disputed by the management of the Bank specifically in its written statement MW-1 Ram Adhar Singh has not also disputed this fact in his testimony. WW-1 Bijoy Kumar Gupta is an employee of the Bank. He has stated in his testimony that he came on transfer to Deoghar Branch of the Bank in 1971 and that he know the concerned workman who was appointed in Deoghar Branch in 1978. WW-2 Bishnu Pada

“UCO BANK—DEOGHAR—0028.
statement of Person employed on daily wage basis during the last three years.

Name of Person.	Date since employed.	Total period during the person employed.	Whether they have rendered their service continuously with break	Capacity in which the person employed.	Appointing Authority.
1	2	3	4	5	6
Shailendra Kumar	24th April, 1978	7 years and 5 months	Almost continuously with two days break.	Waterboy-cum Peon	Manager

Sd/-
Manager,
Deoghar Branch”

The certificate of the Asstt. Branch Manager indicates that the concerned workman was employed in the Bank as temporary waterboy-cum-peon from 1978 to 1984 (Ext. W2). In consideration of all these evidence I have no hesitation to hold that the concerned workman worked as waterboy-cum-peon in the Deoghar Branch of the Bank from 24-4-78 till 3-9-85 when his service was terminated, admittedly, by the Branch Manager. Thus, it is evident that he was in service of the Bank for more than seven years.

13. It has been asserted by the Bank that the concerned workman never worked from 10 A.M. till 6 P.M. in the Bank while the concerned workman has asserted that he worked from 10 A.M. till 6 P.M. in the Bank and that he was initially paid Rs. 5 per diem which was increased to Rs. 8 per diem and later to Rs. 10 per diem. Ram Adhar Singh, the then Branch Manager has admitted that the concerned workman was paid at the rate of Rs. 5 per diem, later Rs. 8 per diem and subsequently Rs. 10 per diem. In cross-examination he has admitted that the concerned workman was required to report for duty with the opening of the Bank and that during the summer season he was required to stay put to his duty till the closing of the Bank at 5 P.M. and that in winter season he used to leave the Bank at 2 or 2.30 P.M. and that the concerned workman used to stay put to his duty till 6 P.M. during the first 3/4 days of the first week of every month. He has denied of course that the concerned workman was required to stay put to his duty till 6 P.M. throughout the month. The concerned workman has stated that he had to report for duty at 10 A.M. and he was required to stay put to his duty till 6 P.M. and that his duty was to open the almirahs and to bring ledgers and other documents and place

Bhattacharjee has stated that the service of the concerned workman was dispensed with from 3-9-85. He has further stated that in reply to the letter from Ranchi Divisional Office marked Ext. W-3, the Branch Manager sent reply to that letter to the Divisional Office which has been marked Ext. W-4. The text of this reply is gleaned hereinbelow.

“Engagement of Daily Wages/Temporary Workmen
With reference to your letter No. RAND/PER/BR CIR 1/88 dated 23-1-88 we give below the required statement for your information and doing the needful.

1. Name of the daily wages/Temporary workmen—Sri Sailendra Kumar.
2. Duration/Duration—Seven years.
3. Remuneration being paid—Rs. 10 per day.
4. Whether sponsored by Employment Exchange—No
5. Age—28 years.
6. Educational Qualification—Class VIII Pass.
7. Authority if sanctioned—Manager.
8. Court case if any filed by daily wages.—Yes. The case is now in Tribunal No. 1 Dhanbad.

Please acknowledge receipt.

Sd/- Manager”

WW-2 B. B. Bhattacharjee, in course of his testimony, has further proved the photo copy of the letter of the Branch Manager which has been marked Ext. W-5. The annexure which accompanied this letter has also been marked Ext. W 5 and the details mentioned therein are gleaned hereinbelow :

the same before the concerned persons. He has also stated that it was his duty to serve water to the employees and to do other sundry jobs and that in the afternoon after the business hours he used to put back the ledgers & other documents again inside the almirahs. WW-1 Bijoy Kumar Gupta has asserted that the concerned workman was required to report for duty with the opening of the Bank at 10 A.M. and to stay put to his duty till they left the Bank after working hours at 5 to 5.30 P.M. The letter of the Branch Manager (Ext. W-4) and his statement (Ext. W-5) do not indicate that the concerned workman was a part-time employee or that he had no fixed duty hours. Considering the entire evidence, I am constrained to hold that the concerned workman was required to perform his duty during the working hours of the Bank.

14. It is the case of the Bank that the usual procedure in the Bank is to assess the vacancy and fill it up through Employment Exchange as per Government directive and direct appointment of candidate is not made nor is it permitted. It is the further case of the Bank that the concerned workman appeared in the test for selection and failed and so he can not have any claim either for continuity or for regularisation in service.

The evidence on record does not disclose a white of evidence to sustain the contention of the management that the procedure of the Bank is to fill up the vacancy through Employment Exchange and direct recruitment is not made nor is it permitted. Admittedly, United Commercial Bank is a nationalised Bank, but then there is no evidence to establish the fact that it is obligatory on the part it is obligatory on the

part of the management of the Bank to fill up the vacancy through Employment Exchange in terms of Government directive.

Ram Adhar Singh (MW-1) has stated that the concerned workman once sat for the examination held for recruitment of subordinate staff and since he could not get through the examination, he could not be absorbed. In cross examination he has stated that he does not remember if any paper has been filed supportive of the fact that the concerned workman sat for examination held for the recruitment of subordinate staff. The concerned workman has firmly denied the fact that he sat for the examination for recruitment of workman on subordinate cadre of the Bank during the years 1978-1985. In the context of these evidence, I can not but hold that there is absolutely no cogent evidence on record to indicate that the concerned workman appeared in the examination for recruitment of subordinate staff of the Bank and failed.

15. In consideration of the evidence on record as pointed out earlier, I am constrained to hold that the concerned workman worked in the Bank for over seven years and that his service was terminated with effect from 3-9-85. Admittedly, he was not given any notice of termination of his employment or pay in lieu of notice and retrenchment compensation. That being so, the action of the management of the Bank in terminating the service of the concerned workman with effect from 3-9-85 without observing the provision of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act is not justified.

In the context of facts and circumstances of the case, the concerned workman is entitled to be regularised and reinstated in service with effect from 3-9-85 with 40% of back wages.

16. Hence, the following award is rendered—the action of the management of UCO Bank, Patna in terminating the services of Shailendra Kumar Yadav, Waterboy-cum-Peon, Deoghar Branch with effect from 3-9-85 without observing the provision of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act and not providing employment after 3-9-85 on regular basis is not justified. The management of the Bank is directed to reinstate him in service and regularise him as Waterboy-cum-Peon with effect from 3-9-85 with 40% of back wages.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

[No. L-12012/525/86-D.II(A)]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1990

का.आ. 1101 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th April, 1990

S.O. 1101.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th April, 1990.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

CASE NO. 59/87

Employers in relation to the management of Central Bank of India

AND

Their workman—Pala Ram.

For the workman : Shri R. K. Joshi.

For the management : Shri Yogesh Jain.

INDUSTRY : Banking

STATE : Chandigarh.

AWARD

Central Govt. vide gazette notification, No. L-12012/312/86-D. II(A), dated 7th August 1987 issued U/S 10(1) (d) of the I.D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri Pala Ram.

"Whether the action of the management of Central Bank of India Zonal Office, Sector 17, Chandigarh, in dismissing from service Shri Pala Ram, S. Sai Karanichari, w.e.f. 1-5-1983 for the charges framed under Section 381 and 411 I.P.C. for removing important documents in a gunny bag on 25-2-1983 without conducting a domestic enquiry is justified? If not to what relief the concerned workman entitled?"

2. The facts giving rise to the above reference need not be reproduced, because R. K. Joshi representing Pala Ram has made statement that he does not want to pursue this matter any more and a no dispute award may be sent. Mr. Yogesh Jain representing the management has also filed a certified copy of the judgement Ex. M1 indicating the conviction of Pala Ram workman U/S 380 IPC. In view of the circumstances since Pala Ram workman has been convicted and sentenced U/S 380 IPC and further since he does not want to pursue with the present reference, thus a No Dispute Award is returned.

Chandigarh

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

13-3-1990.

[No. L-12012/312/86-D.II(A)]

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1990

का.आ. 1102 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th April, 1990

S.O. 1102.—In pursuance of section 17 of the Industrial disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 4-4-90.

ANNEXURE

Before Shri Arvind Kumar, Presiding Officer, Central Govt., Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh.

Case No. 92/88

Employers in relation to the management of Union Bank of India.

AND

Their workman : R.K. Bhatia

For the workman.—Shri V.K. Gupta

For the management.—Shri S. K. Kapoor

AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-12011/47/88-D2(A) dated 15th November 1988 issued U/S 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri R.K. Bhatia.

“Whether the action of the management of Union Bank of India in relation to their Zonal Office (North), New Delhi in not considering the request transfer of S/Shri V.K. Setia and R.K. Bhatia, Head Cashier from extension Counter Sector 21, Chandigarh and Kulan branches to Sector 17, Chandigarh and Fatehabad respectively in terms of the Memorandum of Settlement dated 16-10-1984 arrived under Section 2(1) and Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of I.D. (Central) Rules, 1957 is justified. If not to what relief the workmen are entitled?”

2. The facts giving rise to the above reference need not be reproduced, because workman vide Statement dated 13-3-1990 made by his representative Shri V.K. Gupta agreed to withdraw the reference and also deposed that the workman does not want to persue with the matter and a no dispute award may be sent.

3. In view of this on the basis of the statement by Shri V.K. Gupta representative of the workman a no dispute Award is returned.

Chandigarh.
13-3-1990

ARVIND KUMAR, Presiding Officer
[No. L-12011/47/88-D.II(A)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1990

का. आ. 1103—अभ्रक खान श्रमिक कल्याणनिधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उन क्रियाकलापों, जिनके लिए 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि से पैसा दिया गया था, पर रिपोर्ट तथा उस वर्ष का लेखा विवरण और वर्ष 1989-90 के लिए उक्त निधि की प्राप्तियों तथा व्यय का एक प्राक्कलन प्रकाशित करती है।

भाग - I

1. सामान्य : अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि का गठन अधिनियम, 1946 (1946 का 22) के अधीन किया गया है ताकि अभ्रक खान उद्योग में उद्योग नियोजित श्रमिकों के कल्याण के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए पैसा दिया जा सके।

2. अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि निर्यात किए गये सभी अभ्रक पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर

सरकारी राजपत्र में प्रकाशित यथा मूल्य के अनुसार अधिकतम सीमा-शुल्क लगाने का अधिकार है लेकिन यह दर 6-1/4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरर दर 15 जुलाई, 1974 से 2-1/2% की पहली दर से बढ़ाकर यथा मूल्य 3-1/2% कर दी गई।

भाग - II

चिकित्सा :

अभ्रक खानों में खनन कार्यों में नियोजित श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए श्रम कल्याण संगठन द्वारा अनेक प्रकार की चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। चिकित्सा सुविधा प्रदान के लिए पांच अस्पतालों, आठ एलो-पैथिक औषधालयों, दो छोटे सामुदायिक औषधालय, दो लघु सामुदायिक केन्द्र औषधालय और ग्यारह आयुर्वेदिक औषधालयों की व्यवस्था की गई है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान (अर्थात् 1988-89) में सभी औषधालयों में कुल उपस्थिति 74271 थी जबकि अस्पतालों में औसत उपस्थिति 75742 थी। टी. बी. से पीड़ित अभ्रक खनिकों हेतु आवासीय उपचार योजना के अंतर्गत 167 रोगियों को राहत प्रदान की गई। घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत दस कर्मकारों को 4,775 रु. की राशि स्वीकृत की गई।

आवास :

टाइप-I आवास योजना के अन्तर्गत अभ्रक खान के प्रबन्धकों को, मकान निर्माण हेतु 10,000/- रु. (प्रति मकान) या कुल लागत का 75% जो भी कम हो, की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त खान प्रबन्धकों को साधारण क्षेत्रों में विकास की वास्तविक लागत का 50% अथवा 2000/- रु. इनमें से जो भी कम हो, और काली मिट्टी तथा उभरी मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकास की वास्तविक लागत का 75% अथवा 2000/- रु. इनमें से जो भी कम हो, प्रति मकान की दर से दिया जाता है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, 10 मकानों के लिए मंजूरी दी गई और इनके लिए 38,250/- रु. की राशि दी गई। अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अंतर्गत अभ्रक खानों में नियोजित पात्र कर्मकारों को मकान बनाने के लिए 1000/- रु. की आर्थिक सहायता और 4000/- रु. का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है जिसे श्रमिक को मासिक किस्तों के रूप में 9 वर्ष में लौटाना होता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण के रूप में 2000/- रु. की धनराशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत एक मकान निर्माण और 92 मकानों की मरम्मत के लिए 42,600/- रु. की धनराशि स्वीकृत की गयी।

शैक्षिक और मनोरंजन सुविधायें :

खानों में नियोजित कर्मकारों के उन बच्चों को, जो स्कूलों या कालिजों में अध्ययन कर रहे हैं, प्रतिमाह 15 रु. से 125 रु. तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष के दौरान 461 बच्चों को 1,53,312/- रु. की आर्थिक सहायता दी गई। अभ्रक खानों में नियोजित कर्मकारों के 385 बच्चों को पुस्तकों, स्लेटों आदि की खरीद के लिए 6,154/- रु. की धनराशि प्रदान की गयी। खान कर्मकारों के 395

बच्चों को स्कूल की बर्दी दी गई और इस उद्देश्य के लिए 19,750 रु. की राशि स्वीकृत की गई। 292 बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए 32,050/- रु. व्यय किया गया। माडल (राजस्थान) के छात्रावास में 20 विद्यार्थियों को निःशुल्क बोर्डिंग और लाजिंग सुविधाएं प्रदान की गयी।

चार खान प्रबंधकों को एक एक टेलीविजन सेट स्वीकृत किया गया जिसके लिए 40,000/- रु. रिलीज किए गये। अभ्रक खनिकों और उनके परिवारों के मनोरंजन के लिए फिल्म शो दिखाने में 63,120/- रु. व्यय किये गये। अभ्रक खनिकों के लिए एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिस पर 9000/- रु. खर्च किये गये।

पेय जल सुविधाएँ :

हालांकि खान कर्मकारों को जल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये योजना चल रही है लेकिन 1988-89 में किसी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।

भाग III

अभ्रक खान थ्रम कल्याण निधि को प्राप्तियां व्यय और शेष बची राशियां नीचे दी गई हैं :

	(रु. लाखों में)
1 अप्रैल 1988 को आदिशेष	187.46
प्राप्तियां	149.13
व्यय	162.14
31 मार्च, 1989 को अन्तशेष	174.45

भाग IV

वर्ष 1989-90 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय निम्न प्रकार हैं :—

	(रु. लाखों में)
अनुमानित प्राप्तियां	110.00
अनुमानित व्यय	201.50

[सं. जेड-16016/6/89-डब्ल्यू-II]

New Delhi, the 2nd April, 1990

S.O. 1103.—In pursuance of Sub-Section (4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946), the Central Government hereby publishes the following report on the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ending 31st March, 1989 together with a statement of accounts for the year and an estimate of receipts and expenditure of the said fund for the year 1989-90.

PART-I

1. General : The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund

PART-III

The receipts, expenditure and balances of the mica Mines Labour Welfare Fund are as under :

	(Rs. in lakhs)
Opening Balance as 1st April 1988	187.46
Receipts	149.13
Expenditure	162.14
Closing balance as on 31st March 1989	174.45

PART-IV

The estimated receipts and expenditure for the year 1989-90 are as follows :— (Rs. in lakhs)

Estimated Receipts	110.00
Estimated Expenditure	201.50

[No.Z-16016/6/89-W.II]

Act, 1946 (22 of 1946) for the financing of activities to promote the Welfare of labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of custom on all mica exported upto a maximum rate of exceeding 6-1/4 per cent ad valorem as may be fixed from time to time by the Central Government by publication in the Official Gazette. The rate of cess was enhanced to 3-1/2 per cent with effect from 15th July, 1974, from the previous rate of 2-1/2 per cent ad valorem.

PART-II

Medical : Various types of medical facilities for mica workers and their dependents are provided free of cost by the Labour Welfare Organisation. Five hospitals, eight allopathic dispensaries, two small community Centre dispensary and eleven ayurvedic dispensaries have been set up for providing medical care. During the year under report (i.e. 1988-89) the total attendance in all dispensaries was 74,271 while the aggregate attendance in hospitals was 75,742. Under the scheme for Domiciliary treatment of mica miners suffering from T. B. 167 patients were provided relief. Ten workers were sanctioned a sum of Rs. 4,775 under the Fatal and Serious Accident Benefit Scheme.

Housing : Under the Type-I Housing Scheme subsidy is payable to mica mine managements at the rate of Rs. 10,000 or 75 per cent of the actual cost of construction per tenement whichever is less. In addition development charges are also payable at the rate of 50 per cent of actual cost of development or Rs. 2,000 whichever is less, for ordinary soil areas and 75 per cent of actual cost of development or Rs. 2,000 whichever is less, for black cotton/swelly soil areas. During the year under report, ten houses were sanctioned and an amount of Rs. 38,8250 was released for this purpose.

Under the Build Your Own House Scheme financial assistance at the rate of Rs. 1,000 as subsidy and an interest free loan of Rs. 4,000, refundable in monthly instalments, spread over nine years is given to an eligible worker for construction of the house. A sum of Rs. 2,000 is given as Loan under the scheme. During the financial year 1988-89 a sum of Rs. 42,600 was sanctioned for construction of one house and repair of 92 houses.

Educational and Recreational facilities : Scholarships ranging from Rs. 15 to Rs. 125 per month are awarded to wards of miners studying in schools and colleges. During the year 461 children were awarded a sum of Rs. 1,53,312. An amount of Rs. 6,154 was provided to 385 children of mica miners for books, states etc. 395 children of mica miners were provided uniforms and for this purpose a sum of Rs. 19,750 was sanctioned. Expenditure of Rs. 32,050 was incurred in providing mid-day meals to 292 children. 20 students were provided free boarding and lodging facilities at the Hostel at Mandal (Rajasthan).

Four mine managements were sanctioned a T.V. set each for which Rs. 40,000 was released. Expenditure amounting to Rs. 63,120 was incurred in organising exhibition of film shows for recreation of mica miners and their families. A sports meet was organised for mica miners for which Rs. 9,000 was spent.

Drinking Water Facilities : Although scheme for providing water supply facilities for mine workers is operative no project was sanctioned in 1988-89.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1990

का.श्री. 1104:—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उन कार्य कलापों, जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन वित्त व्यवस्था की गई है, के बारे में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

सामान्य :

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी प्रतिष्ठानों में सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए उपायों की वित्त व्यवस्था के लिए गठित किया गया है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बनाए गए नियम 15 फरवरी, 1977 से लागू हुए और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बनाए गए नियम 7 अक्टूबर, 1978 से लागू हुए।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55) की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने बीड़ी बनाने से संबंधित किसी उद्देश्य के लिए गोदाम में से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू के प्रति किलोग्राम पर 20 पैसे की दर को उस दर के रूप में निर्धारित किया है जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना था और उपकर के रूप में एकत्र किया जाना था।

वित्त अधिनियम, 1976 के अधीन तम्बाकू को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी और गोदामों को लाइसेंस देना समाप्त कर दिया था। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन एकत्र किया जा रहा उपकर भी पहली मार्च, 1979 से रोक दिया गया था। इस निधि के अधीन कार्यकलापों की वित्त व्यवस्था के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संगोष्ठन) अधिनियम, 1981 बनाया गया था और पहली जनवरी, 1982 से प्रति हजार निमित्त बीड़ियों पर 10 पैसे की दर से उपकर लगाया गया था। इस उपकर को पहली मार्च, 1987 से प्रति हजार तैयार की गई बीड़ियों पर 10 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे कर दिया गया है।

प्रशासनिक सुविधा के लिए, देश में राज्यों के 9 क्षेत्रों में गुप बना दिए गए हैं और विभिन्न कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र एक कल्याण आयुक्त के अधीन है। कल्याण आयुक्तों के सहायक निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, भुवनेश्वर।	उड़ीसा
3.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, कलकत्ता।	पश्चिमी बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम।
3.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, इलाहाबाद।	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़।
4.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, भीलवाड़ा।	राजस्थान, हरियाणा और गुजरात।
5.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, जयपुर।	मध्य प्रदेश।
6.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, हैदराबाद।	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पांडिचेरी और अन्धमान एवं निकोबार द्वीप समूह
7.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नागपुर।	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली।
9.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, करमा।	बिहार।

चिकित्सीय देखरेख :

चिकित्सीय देखरेख देने के लिए आधारभूत ढांचा बनाने को सबसे अधिक वरीयता दी गई है। श्रम कल्याण संगठन द्वारा बीड़ी कर्मकारों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध की जा रही हैं। इनमें अस्पतालों, औषधालयों में चिकित्सा सुविधाओं और टी.बी. के इलाज की सुविधाएं आदि शामिल हैं।

वर्ष 1988-89 के दौरान, 154 औषधालय, दो अस्पताल, मैसूर (कर्नाटक) और करमा (बिहार) में एक एक और निमीतिता (पश्चिम बंगाल) में एक चैम्प क्लिनिक कार्य कर रहे थे। विद्यमान चिकित्सा संस्थानों के अलावा, मुंबई (तमिलनाडु) में एक अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमति दी गई है। औषधालयों में कुल उपस्थिति 23, 28, 650 बी.बी.बी. 66,786 व्यक्तियों

का (बी.पी.डी. में 54, 597 और अंतरंग में 11829 व्यक्ति) अस्पताल में इलाज किया गया। औपचारिक और अस्पतालों में रोगियों के बीच वितरण के लिए, दवाइयों की खरीद हेतु 45,62,274 रु. की राशि खर्च की गई थी। कल्याण आयुक्त उन बीड़ी कर्मकारों के, जो टी.बी. में पीड़ित हैं, इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। टी.बी. रोगियों के इलाज के लिए 72 पलंग आरक्षित किए गए, जी 6716 दिनों तक भरे रहे। टी.बी. अस्पतालों में पलंगों के आग्रहण की योजना के अंतर्गत टी.बी. रोगियों के आश्रितों को जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में 24,475/- रु. की राशि दी गई थी। टी.बी. रोगियों के लिए गृह उपचार की योजना के अंतर्गत 144 बीड़ी कर्मकारों को राहत प्रदान की गई। चिकित्सा प्रभार के रूप में 14,320 रु. की राशि वितरित की गई थी तथा उनके आश्रितों को 1,15,545/- रु. की राशि जीवन-निर्वाह भत्ते के रूप में दी गई थी।

चर्मों की खरीद की योजना के अंतर्गत 952 कर्मकारों को 37,376/- रु. की वित्तीय सहायता दी गई।

कैंसर से पीड़ित 4 बीड़ी कर्मकारों के इलाज की बाबत 4,147/- रु. की राशि व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई।

वर्ष 1988-89 के दौरान, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अधीन तीन नई योजनाएं शुरू की गई थीं। वे निम्न हैं :—

(क) महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविध योजना, जिसके अंतर्गत बीड़ी कर्मकार को अपने जीवन में दो बार प्रति प्रसव 250/- रु. की एकमुश्त अनुदान राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2744 महिला कर्मकारों ने लाभ उठाया और रिपोर्टेड वर्ष के दौरान उन्हें 6,86,000/- रु. की राशि दी गई थी।

(ख) बीड़ी कर्मकारों को बंधीकरण के लिए अतिरिक्त वित्तीय मुआवजे की अदायगों की योजना के अंतर्गत, उस कर्मकार को 20/- रु. की राशि दी जाती है जो बंधीकरण आपरेशन करवाता है। यह उस किसी अन्य लाभ के अलावा है जो उसे अन्यथा मिलता है। रिपोर्टेड वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत चार कर्मकारों को प्रोत्साहन दिया गया।

(ग) सहकारी समितियों के माध्यम से बीड़ी कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना, जिसके अंतर्गत पात्र सदस्य की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा निगम द्वारा सहकारी समिति को 5000/- रु. की राशि दी जाती है। प्रीमियम प्रति सदस्य 45/- रु. प्रति वर्ष की दर से बसूल किया जाता है। कल्याण आयुक्तों द्वारा 50% तक की इमवाद दी जाती है। रिपोर्टेड वर्ष के दौरान, इस योजना के अधीन किसी की सहकारी समिति ने लाभ नहीं उठाया।

गिराव :

छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, बीड़ी कर्मकारों के 34,424 बालकों को 114,61,787/- रु. की राशि वितरित की गई। स्कूल ड्रैम की खरीद के लिए 11,123 बालकों को वित्तीय सहायता दी गई। इस प्रयोजन हेतु 5,56,050 रु० की राशि मंजूर की गई थी।

आवास :

इस समय, बीड़ी कर्मकारों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए तीन योजनाएं चल रही हैं :—

- (i) बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मकारों के लिए आवास योजना ;
- (ii) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना; और
- (iii) बर्कशेडों/गोंदामों का निर्माण।

(i) बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मकारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 5000/- रु. प्रति मकान की दर से इमवाद दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, विकास की वास्तविक लागत का 50% की दर से विकास प्रभार भी देय है बशर्ते कि यह साधारण और ब्लैंक काटन/उभरी हुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए समशः 800/- रु. और 100/- रु. अधिकतम हो। इसके बजाय, राज्य सरकारें मकानों का निर्माण करनी है और बीड़ी कर्मकारों को आवंटित करती है। इस वर्ष के दौरान, बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मकारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत, नीचे दिए गए प्रस्तावों के संबंध में मकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन जारी किए गए :—

राज्य	मकानों की सं.	स्थान	प्रायोजित करने वाला प्राधिकरण
1. गुजरात	110	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (अ. श. वि. प्र.)
2. आन्ध्रप्रदेश	300	निजामाबाद	आन्ध्र प्रदेश सरकार
	100	कमलापुरम	
3. महाराष्ट्र	4000	शोलापुर	महाराष्ट्र सरकार
	210	नान्डेड	
	353	जालना	
	229	पुणे	

वर्ष 1988-89 के दौरान मंजूर की गई 15 लाख रुपये की राशि में से, मकानों के निर्माण हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को 13,68,500/- रु. की राशि दी गई थी। महाराष्ट्र राज्य सरकार को शोलापुर में 2680 मकानों के निर्माण के लिए 1.34 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

(2) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अंतर्गत पात्र कर्मकार को हमदाद के रूप में 1000/- रु. की दर से वित्तीय सहायता तथा इसके अतिरिक्त 6000/- रु. का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाता है जो 9 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में लौटाना होता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 172 मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी जारी की गई। 50 मकानों की मरम्मत के लिए भी मंजूरी जारी की गई। वर्ष 1988-89 में इस योजना के अंतर्गत 5.17 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए ऋण के रूप में पहले दी गई राशि में से 8,28,504/- रु. की राशि वसूल की गई है। बीड़ी कर्मकारों से 3,23,828/- रु. की और राशि अभी वसूल की जानी है।

(3) गोदामों और वर्कशेडों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकार सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना भी लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, समितियों को प्रत्येक के निर्माण की वास्तविक लागत के 75 प्रतिशत प्रोक या 75,000/- रु. इनमें से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्कशेड/गोदाम के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी संबंधित कल्याण आयुक्त द्वारा जारी की जाती है। सहकारी समितियों द्वारा 8 वर्कशेडों और गोदामों के निर्माण के लिए 95,746/- रु. की राशि मंजूर की गई है।

मनोरंजन :

बीड़ी कर्मकारों के मनोरंजन के लिए, वर्ष 1988-89 के दौरान निम्नलिखित व्यय किया गया :—

- (1) टी.वी. सैटों की खरीद के लिए 6 समितियों को 46,576/- रु. की राशि मंजूर की गई।
- (3) खेल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजित करने के लिए 41,757/- रु. की राशि मंजूर की गई।
- (3) दृश्य श्रव्य सैटों/सिनेमा बैन आदि की स्थापना के लिए इस योजना के अंतर्गत किराया प्रभार/प्रतिपूति प्रभार की बाबत 15,895/- रु. की राशि मंजूर की गई।
- (4) हाली-डे होम योजना के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु 11,312/- रु. खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त, होली-डे-होम योजना के अंतर्गत 30 कर्मकारों को याता भत्ता दिया गया।

भाग-2

वर्ष 1988-89 के लिए लेखा विवरण :

1. पहली अप्रैल, 1988 को अधिशेष	15,37,54,234 रु.
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	11,98,89,457 रु.
3. वर्ष 1988-89 के दौरान व्यय	6,59,85,688 रु.
4. 31-3-89 को अंत शेष	20,76,58,003 रु.

भाग-3

वर्ष 1989-90 के लिए अनुमानित आय और व्यय

1. अनुमानित व्यय	15,11,00,000 रु.
2. अनुमानित आय	11,50,00,000 रु.

[सं. जैड.16016/3/89-डब्ल्यू-2]
बी.डी. नागर, अव्वर नचिव

New Delhi, the 6th April, 1990

S.O. 1104.—In pursuance of Section 10 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976), the Central Government hereby publishes the following report on the activities financed under the said Act, during the year ending March, 1989 :—

GENERAL :

The Beedi Workers Welfare Fund has been constituted under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, and the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976, for financing of the measures to promote the welfare of persons engaged in beedi establishment directly or through any agency.

The Rules framed under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, came into force with effect from 15th February, 1977, and the Rules under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 from 7th October, 1978.

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 7 of the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (55 of 1976) the Central Government had fixed the rate of 20 paise per kilogram of tobacco issued from a warehouse for any purpose in connection with the manufacture of beedis, as the rate at which the duty of excise was to be levied and collected by way of cess.

Under the Finance Act, 1976, tobacco was exempted from the levy of excise duty and licensing of warehouses was discontinued. The cess which was being collected under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, was also stopped with effect from 1st March, 1979. For financing of the activities under the Fund, the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Act, 1981, was enacted and the cess was levied at the rate of 10 paise per thousand manufactured beedis with effect from 1st January, 1982. The rate of cess has been enhanced from 10 paise to 30 paise per thousand manufactured beedis with effect from 1st March, 1987.

For administrative convenience, the States in the country, have been grouped into 9 regions and each region is under the charge of a Welfare Commissioner for implementing the various welfare schemes. The jurisdiction of the Welfare Commissioners is as under :—

Sl. No.	Name of the Region	Name of States/Union Territories
1.	Welfare Commissioner, Government of India, Ministry of Labour, Bhubaneswar.	Orissa
2.	Welfare Commissioner, Government of India, Ministry of Labour, Calcutta.	West Bengal, Assam, Manipur, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Sikkim.
3.	Welfare Commissioner, Government of India, Ministry of Labour, Allahabad.	Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh.
4.	Welfare Commissioner, Government of India, Ministry of Labour, Bhiwara.	Rajasthan, Haryana and Gujarat.

5. Welfare Commissioner, Madhya Pradesh
Government of India,
Ministry of Labour,
Jabalpur.
6. Welfare Commissioner, Tamilnadu, Andhra Pradesh,
Government of India, Pondicherry and Andaman and
Ministry of Labour, Nicobar Islands,
Hyderabad.
7. Welfare Commissioner, Karnataka, Kerala and
Government of India, Lakshadweep,
Ministry of Labour,
Bangalore.
8. Welfare Commissioner, Maharashtra, Goa, Daman
Government of India, and Diu Dadra and Nagar
Ministry of Labour, Haveli,
Nagpur.
9. Welfare Commissioner, Bihar.
Government of India,
Ministry of Labour,
Karma.

During 1988-89 three new schemes were launched under the Beedi Workers Welfare Fund. They are :

- (a) Maternity Benefit Scheme for female beedi workers under which a lump sum grant of Rs. 250 is payable per delivery upto twice in the lifetime of the beedi workers. 2744 workers benefited under this Scheme and a sum of Rs. 6,86,000 was paid to them during the year under report.
- (b) Under the scheme for payment of extra monetary compensation for sterilisation to beedi workers an amount of Rs. 20 is paid to the worker who undergoes sterilization. This is in addition to any other benefit he received otherwise. During the year under report four workers were paid incentive under the scheme.
- (c) Group Insurance Scheme for Beedi Workers through Cooperative societies under which an amount of Rs. 5,000 is paid by the Life Insurance Corporation to the cooperative Society on death by whatsoever cause of an eligible member. The premium is charged at rate of Rs. 45 per annum per member. It is subsidised to the extent of 50% by the Welfare Commissioners. During the year under report none of the cooperative societies availed the benefits under this scheme.

MEDICAL CARE

The Organisation of infrastructure for rendering medical care has been given top priority. Various types of medical facilities for beedi workers and their dependants are being provided free of cost by the Labour Welfare Organisation. These include medical facilities at hospitals, dispensaries and facilities for treatment of TB etc.

During the year 1988-89, 154 dispensaries, two hospitals, one each at Mysore (Karnataka) and Karma (Bihar) and one chest clinic at Nimitita (West Bengal) were functioning. In addition to the existing medical institutions administrative Mukkudal (Tamilnadu). The total attendance at all dispensaries was 23,28,650 while 66,786 persons (54,597 in OPD and Hospitals. The Welfare Commissions have been ended-11,829 in Indoor) were given treatment in Hospitals. A sum of Rs. 45,62,274 was spent towards purchase of medicines, for distribution among patients at all the dispensaries and Hospitals. The Welfare Commissioners have been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of beedi workers suffering from T.B. 72 beds were reserved for providing treatment to TB patients which remained occupied for 6716 days. A sum of Rs. 24,475 was paid as subsistence allowance to dependents of TB patients under the Scheme for reservation of beds in TB. Hospitals, 144 beedi workers were provided relief under the Scheme for Demicellary treatment for T.B. patients. A sum of Rs. 1,44,320 was reimbursed as medical charges to the patients and Rs. 1,15,545 was to their dependents as subsistence allowance.

952 workers were given financial assistance of Rs. 37,376/- under the scheme for the purchase of spectacles.

A sum of Rs. 4,117/- was paid for reimbursement of charges towards treatment of 4 beedi workers suffering from cancer.

EDUCATION

A sum of Rs. 114,61,787/- was disbursed as scholarships to 34,424 children of beedi workers under the Scheme for award of scholarships. 11,123 children of beedi workers were paid financial assistance for purchase of school dress. A sum of Rs. 5,56,050 was sanctioned for this purpose.

HOUSING

At present, the following schemes are in vogue to provide housing facilities to beedi workers :

- (i) Housing Scheme for Economically Weaker Section of workers engaged in Beedi Industry;
- (ii) Build Your Own House Scheme; and
- (iii) Construction of Worksheds/godowns.

(i) Under the Housing Scheme for Economically Weaker Section of workers engaged in beedi industry, State Government are being given subsidy at the rate of Rs. 5000/- per house. In addition to this, development charges at the rate of 50% of the actual cost of development subject to a maximum of Rs. 800/- or Rs. 1000/- per house for ordinary and black cotton/swelly soil areas respectively is also payable. In turn the State Governments construct and allot houses to the beedi workers. During the year Administrative Approval for construction of houses under the Housing Scheme for Economically Weaker Sections of Workers engaged in Beedi Industry were issued in connection with proposals indicated below :

State	No. of Houses	Venue	Sponsoring Authority
1. Gujarat	110	Ahmedabad	Ahmedabad Urban Development, Authority (AUDA).
2. Andhra Pradesh	300	Nizamabad	Government of Andhra Pradesh
3. Maharashtra	100	Kamapuram	Government of Maharashtra.
	4000	Solapur	
	210	Nanded	
	353	Jajna	
	229	Pune	

During 1988-89 out of Rs. 15 lakhs sanctioned, a sum of Rs. 13,68,500 was paid to the State Government of Andhra Pradesh for construction of houses. Another sum of Rs. 1.34 crores was released to the State Government of Maharashtra for construction of 2680 houses at Sholapur.

(ii) Under the Build Your Own House Scheme financial assistance is given to an eligible worker at the rate of Rs. 1000 as subsidy besides interest free loan of Rs. 6000/- refundable in monthly instalments spread over a period of 1023 GI/90-8

9 years. During the period under report sanctions for construction of 172 houses were issued. Sanctions for repair of 50 houses were also issued. A sum of Rs. 5.17 lakhs has been disbursed under this Scheme in 1988-89. A sum of Rs. 1,29,504 which was paid as loan earlier for construction of houses has been recovered from the beedi workers under the Build Your Own House Scheme. Another sum of Rs. 8,28,828/- is to be recovered from the beedi workers.

(iii) A Scheme for grant of financial assistance to beedi workers cooperative societies for constructions of Godowns

and worksheds is also being implemented. Under the Scheme, Societies are given financial assistance upto 75% of the actual cost of construction of worksheds/godowns on both or, Rs. 75,000 for each whichever is less. Under the Scheme, administrative approval for the construction of workshed/godown is issued by the respective Welfare Commissioner. A sum of Rs. 95,746/- has been sanctioned for the construction of 8 workshed and godowns by Cooperative Societies.

RECREATION

For the recreation of the Beedi Workers following expenditure was incurred during 1988-89 :—

- (1) A sum of Rs. 46,576 has been sanctioned to 6 Societies for the purchase of TV Sets.
- (2) A sum of Rs. 41,757 was sanctioned for organising games, social and cultural activities.
- (3) A sum of Rs. 15,895 has been sanctioned towards hiring charges/reimbursement charges under the Scheme for establishment of Audio-visual sets (Cinema Van etc).
- (4) Rs. 11,312 was spent for providing benefits to beedi workers under Holiday Home Scheme. In addition 30 workers were paid Travelling Allowance under the Holiday Home Scheme.

PART II

Statement of Accounts for the year 1988-89

1. Opening balance as on 1st April, 1988 Rs. 15,37,54,234
2. Receipt during the year Rs. 11,98,89,457
3. Expenditure during the year 1988-89 Rs. 06,59,85,688
4. Closing balance as on 31 March, 1989 Rs. 20,76,58,003

PART III

Estimated Receipts and Expenditure for the year 1989-90

1. Estimated Expenditure Rs. 15,11,00,000
2. Estimated Receipt Rs. 11,50,00,000

[No. Z-16016/3/89-W.II]

V. D. NAGAR, Under Secy.

नई दिल्ली 5 अप्रैल, 1990

का. आ. 1105:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, न. 2 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 अप्रैल 1990 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 5th April, 1990

S.O. 1105.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby published the following award of the Central Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 153/89

Employers in relation to the management of State Bank of Patiala.

AND

Their Workman, Ashwani Kumar Sharma.

For the Workman—Workman in person.

For the management—Shri P. P. Tandon.

INDUSTRY : Banking

STATE : Himachal Pradesh.

AWARD

Central Government vide gazette notification No. L-12012/158/89-R(B-3) dated 29th September, 1989 issued under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri A. K. Sharma.

"Whether the action of the State Bank of Patiala, Region III, Chandigarh in denying special allowance/difference of wages to Shri A. K. Sharma, Head Clerk at Solan Branch (H.P.) with effect from 15-10-1985 is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled and from what date?"

2. During the pendency of the proceedings the parties have amicably settled the dispute and today the applicant has informed the Tribunal accordingly. To this effect A. K. Sharma workman had made the statement that in view of the revocation of the suspension order with retrospective effect I have been paid all the arrears of salary and allowance and does not want to pursue this case and the same may be filed as withdrawn.

3. The statement has been approved by Mr. P. P. Tandon representing the State Bank of Patiala. As a result of this since parties have amicably settled the dispute thus a No Dispute Award is returned.

Chandigarh,
13-3-1990.

[No. L-12012/158/89-IR(B-III)]

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

का. आ. 1106:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार युनाईटेड वेस्टर्न बैंक लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 अप्रैल 1990 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1106.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of United Western Bank Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT 239 of 1988

PARTIES.

Employers in relation to the management of United Western Bank Ltd.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For the Employers—1. Shri G. K. David, 2. Shri M. K. Khasbardar, Officers.

For the workmen—1. Shri S. G. Marathe, 2. Shri S. G. Bobde, Representatives.

INDUSTRY : Banking

STATE : Maharashtra

Bombay, the 26th March, 1990

AWARD

The Central Government by their order No. L-12012/40/88-D.(IV)(A) dated 3-10-1988 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under

Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act :—

"Whether the action or the management of United Western Bank Limited, Satara, in relation to its Satara City Branch to conduct a departmental enquiry in 1988 for alleged misconduct committed on 7-2-1983 by Shri V. M. Chavan, Clerk, working now in Satara City Branch while he was at Goregaon Branch is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the workman Shri V. M. Chavan as disclosed from the statement of claim (Ex. 2) filed by the Organising Secretary, United Western Bank Karmachari Sangh, in short, is thus :—

The workman Shri Chavan was working in Goregaon Branch of the Bank in February, 1983. On 7-2-1983, it was alleged against him thus :—

He was not performing his duties but was reading a magazine on 7-2-1983. The Acting Manager Shri K. B. Inamdar asked the workman Shri Chavan to perform his duties and not to read the magazine. However, the workman continued reading the magazine, and after repeated instructions from the said Officer, the workman kept aside the Magazine and started working at the counter allotted to him. After closure of the Bank on that day, the workman Shri Chavan beat the said officer Shri Inamdar at the front gate of the Bank.

These were the allegations made by the Bank management. Thereafter, the Bank issued a charge-sheet dated 4-10-1983 against the workman alleging that he indulged in certain acts which amounted to gross-misconduct under para. 19 of the bipartite Settlement. The workman was asked to submit his explanation, and accordingly the workman submitted his reply dated 28-10-1983, stating that the charge-sheet issued against him was vague and did not contain the necessary particulars, due to which he was unable to put forth any explanation for the said charge. After the workman submitted his reply, he did not receive any communication from the Branch Manager or from the Disciplinary authority, and as such, the workman presumed that his reply was accepted by the Bank management, and that he was exonerated from the charges levelled against him. No departmental enquiry was thereafter started against him in the year 1983.

(ii) Thereafter, on the request of the workman, he was transferred from Goregaon to Satara in May, 1984. Thereafter, in March, 1987 the workman was surprised to receive a letter dated 17-3-1987 from the Enquiry Officer informing him that the enquiry against him would be continued, and it will be held on 6-4-1987. However, no enquiry was held on that day, but by letter dated 22-6-1987 he was again informed that the enquiry would be held on 11-7-1987. Being aggrieved with the said decision of the Bank to start enquiry in 1987 in respect of certain allegations of the year 1983, the General Secretary of the said Sangh raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (C), Pune. As the conciliation proceedings ended in failure, the Central Government made the reference, as above.

3. The said Sangh alleged thus:—Initiation of enquiry in 1987 after a lapse of four years in respect of certain alleged misconduct of the year 1983 is by itself mala fide, void, and bad in law. There is no reason for the Bank to start the enquiry after the lapse of four years. The said act of the Bank is against the principles of natural justice and is mala fide, void and bad in law. After the lapse of four years, the workman would not be able to defend his case effectively.

The Union (Sangh) therefore, prayed that this Tribunal should hold the initiation of Departmental enquiry in 1987 in respect of certain alleged misconduct of February, 1983 as null and void, and should quash and set aside the orders of the Enquiry Officer dated 17-3-1987 and 22-6-1987 starting the enquiry against the said workman.

4. The United Western Bank Ltd. filed their written statement (Ex. 3), contesting the claim of the said Sangh, and in substance contended thus :—

It is an established principle of industrial jurisprudence that an issue to become an industrial issue must have been espoused by the concerned Union or by an appreciable number of workmen. The issue in question is not an industrial issue as it has not been espoused by the Union i.e. the United Western Bank Karmachari Sangh or even by any number of workmen. It is a dispute, which has been raised by a single office bearer without any knowledge and sanction of the Union or the workmen as per his sweet will. Therefore, no industrial dispute existed or exists between the Bank management and the Union, as contemplated under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. No resolution was passed either by the Executive Committee of the Union or by the general body of the Union to raise the industrial dispute in question before the authority concerned. It is only an individual dispute, and not an industrial dispute. Further conducting a departmental enquiry against an employee is purely an administrative or managerial function of the management or the employer. This administrative function does not in any way affect the term employment or the conditions of labour of the employee, no punishment or adverse action has been imposed upon the employee.

(ii) As regards the facts of the case, the Bank management contended thus:—

The employee Shri V. M. Chavan was posted at Goregaon Branch of the Bank from February, 1981 to May, 1984. On 17-2-1983 in the evening session of the day, Shri Chavan was reading a magazine at the counter of the Bank, instead of performing the duties allotted to him. Therefore, the then acting Manager Shri Inamdar instructed the employee Shri Chavan not to read the magazine during the working hours of the Bank and to perform the duties allotted to him. However, the employee Shri Chavan did not pay any attention to the instructions of the Branch Manager and continued reading the magazine. After repeated instructions from Shri Inamdar, the employee Shri Chavan stopped reading the magazine and started his work, but with a very slow speed. After the working hours of the Bank were over, at about 7.30 p.m. while the Branch Manager Shri Inamdar was leaving the premises of the Bank, the employee Shri Chavan who was standing nearby, assaulted Shri Inamdar and beat him in front of the main door of the branch. Shri Inamdar reported the matter to the higher authorities. The Divisional Manager asked for the explanation of Shri Chavan for his reported misbehaviour. Shri Chavan submitted his reply denying all the allegations made against him. As the said reply was not acceptable to the Bank, the Bank management issued a chargesheet to him and initiated a departmental enquiry against him in October, 1983. Shri M. V. Oak was appointed as an Enquiry Officer in the matter by letter dated 4-10-1983. However, later on this Enquiry Officer was changed and Shri S. V. Kanitkar was appointed as the Enquiry Officer by letter dated 22-6-1986. This Enquiry Officer was also changed and Shri V. S. Agnihotri was appointed as an Enquiry Officer by letter dated 24-6-1986. This Enquiry Officer was also changed and Shri J. H. Joshi was appointed as an Enquiry Officer by letter dated 25-7-1987.

(iii) The Bank management further contended thus :—

There were changes in the posting of presenting officers also. Shri A. S. Pingale was appointed as the presenting officer in the domestic enquiry against the said employee. However, he was changed and Shri S. S. Nene was appointed as the presenting officer by letter dated 24-11-1986. Shri Nene was also changed, and Shri S. D. Nerkar was appointed as

the presenting officer by letter dated 20-5-1987. The officers of the Bank are required to go on transfer, and hence the said changes were required to be made. Therefore, at no point of time the Bank was inclined to condone the misconduct committed by the workman. The Bipartite Settlement between the Bank and the Karmachari Sangh does not put a bar for conducting the enquiry after a lapse of a particular period. The Bank management, therefore, prayed for the dismissal of the prayer of the Organising Secretary and to hold the action of the management in continuing with the Enquiry against the said employees as just and proper.

5. Issues framed at Ex. 4 are :—

- (1) Whether the Organising Secretary of the United Western Bank Karmachari Sangh has espoused the present cause on behalf of the workman Shri Chavan with the permission of the substantial number of the members of that Sangh, and with the permission and knowledge of the said workman
- (2) Whether no industrial dispute existed or exists between the said Sangh and the management of the United Western Bank?
- (3) Whether the action of the Bank management in continuing the inquiry against the said workman in 1987, originally started in 1983, is just, proper and good in law?

(4) What Award?

6. Issues Nos. 1 and 2 are tried as preliminary Issues. My finds on these Issues are :—

- (1) No.
- (2) Did not exist.

REASONS

7. According to the Bank management, no industrial dispute as contemplated under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, exists or existed between the Bank management and the United Western Bank Karmachari Sangh, and at the most there was an individual dispute between the Bank management and the Organising Secretary of that Sangh. According to the Bank management, in order that a valid industrial dispute should exist, the issue must have been raised by the Union or a substantial number of the workmen of the Bank, and that in the present case, no dispute of this character has been raised. It is seen from the statement of claim that it has been signed by the Organising Secretary of the United Western Bank Karmachari Sangh. My attention was drawn on behalf of the Bank management to the case reported in 16 FJR 25 wherein it has been observed thus:—

"An industrial dispute between an employer and a workman which is not taken up by the other workmen in the industry or by a trade union of such workman is not an 'industrial dispute' which can be referred to or dealt with by an Industrial Tribunal. The fact that the Secretary or other office bearer of a trade union represented the case of the workman does not mean that the trade union has taken up the cause of the workman where such office bearer has not authorised by the trade union."

It has been held in the case reported in AIR 1963 Supreme Court 318 that "in each case in ascertaining whether an individual dispute has acquired the character of an industrial dispute, the test is whether at the date of the reference the dispute was taken up or supported by the Union of the workmen of the employer against whom the dispute is raised by an individual workman or by an appreciable number of workmen. In case the dispute espoused was an individual dispute at the time of the reference was made by the Government, it cannot be converted into an industrial dispute even though thereafter taken up by appreciable number of workmen or the Union."

8. As noted above, the Bank management raised the contention in the written statement filed on 27-1-1989, i.e. more than a year back that the Organising Secretary of the United Western Bank Karmachari Sangh has not been authorised by

the Union or by appreciable number of the workmen to espouse the case in the matter. Thereafter the necessary issues as above were framed. Thereafter the case was adjourned from time to time for leading the necessary evidence by the Organising Secretary of the said Sangh. As the Bank management has specifically raised a contention in their written statement that the said Organising Secretary of the Karmachari Sangh has not been authorised by the Union or by appreciable number of workmen of that Sangh, and that the Organising Secretary raised a dispute even without the consent or permission of the Sangh or the employees concerned, the Organising Secretary should have produced the necessary documentary evidence to show that in fact the Executive Committee of that Sangh had passed a resolution authorising him to raise the industrial dispute in question. No oral evidence also on that point has been led by the said Organising Secretary of the Sangh. It is, therefore, quite clear from the record of this case that the dispute raised by the Organising Secretary of the Sangh is an individual dispute and not an industrial dispute as contemplated under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. At least the employee concerned should have been examined in this case to show that the present dispute was raised by the Organising Secretary with the knowledge of the Sangh. However he has not been examined in this proceeding. Therefore, Issue No. 1 will have to be found and is found in the negative. Issue No. 2 is also found accordingly.

9. Therefore as no industrial dispute existed between the United Western Bank Karmachari Sangh and the said Bank management, Issue No. 3 does not survive. As such the present reference will have to be disposed of accordingly. Therefore, as Issues Nos. 1 and 2 have been found in the negative, the present reference stands disposed of accordingly.

The parties to bear their own costs of this reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer
[No. L-12012/40/88-DJV(A)]

का. आ. 1107 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 अप्रैल, 1990 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1107.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Central Industrial Tribunal JAIPUR as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-1990.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर. एच. जे. एस. केस नं. सी. आई. टी. 34/88।

मध्य

सैक्रेटरी, एस. बी. आई. स्टाफ एसोसियेशन माफत एस. बी. आई. मुख्य शाखा, अजमेर।

बनाम

क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्र-11, पी. आर. रोड, जयपुर।

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 10 (1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।

उपस्थिति

प्रार्थी श्रमिक की ओर से : श्री सूर्य प्रकाश सिंह
 प्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री एस. के. जैन
 दिनांक अवार्ड 6-2-90

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनकी आज्ञा क्रमांक [एल-12012/671/87-डी-II (ए)] दिनांक 3-5-88 के द्वारा निम्न विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (घ), जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जायेगा, के अंतर्गत इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णयार्थ भेजा है:

क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्ध तंत्र की टेलर श्री एस. एन. भार्गव को उप मुख्य कैशियर के रूप में 9-2-72 से स्थानापन्न रूप काम करने की अनुमति न देने और अन्त में उसे अजमेर मुख्य शाखा में तैनात करके उप मुख्य कैशियर के रूप में प्रोन्नत करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुसोप का हकदार है?"

2. बाद प्राप्त निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया। उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। श्रमिक प्रतिनिधि श्री पी. डी. अग्रवाल ने स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश किया जिसकी प्रति विपक्षी बैंक को नोटिस के साथ भेजी गई। दिनांक 12-7-88 को बैंक विपक्षी के खिलाफ जवाब का अवसर बन्द किया गया और मिसल वास्ते पेश होने शहायत मय दस्तावेजाता श्रमिक पक्ष 27-7-88 तारीख दी गई। उक्त तारीख पर श्रमिक प्रतिनिधि ने श्रमिक शम्भूनाथ भार्गव का शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेज पेश किये और मिसल वास्ते एकतरफा बहस श्रमिक पक्ष के लिए रखी गई। इतना हो चुकने के उपरांत दिनांक 20-8-88 को विपक्षी बैंक की ओर श्री ए. के. जैन अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 14-9-88 को बैंक ने एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र 2-9-88 को पेश किया जिसकी नकल श्रमिक प्रतिनिधि श्री पी. डी. अग्रवाल को दी गई। तथा मिसल वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र जवाब हेतु दिनांक 28-9-88 तारीख पर रखी गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद विपक्षी बैंक को हर्ज पर वास्ते पेश करने जवाब अवसर दिया गया और विपक्षी के विरुद्ध पारित एक तरफा आदेश निरस्त किया गया। विपक्षी को 12 अवसर दिये जाने जवाब तारीखें निश्चित की गई लेकिन विपक्षी बैंक ने जवाब पेश न कर दिनांक 6-2-90 को विपक्षी बैंक के अधिवक्ता श्री एस. के. जैन एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कहा गया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है और अब कोई विवाद बाकी नहीं रहा, अतः नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जावे। श्रमिक प्रतिनिधि ने जाहिर किया कि मुझे इस प्रार्थना पत्र पर कोई एतराज नहीं है और प्रार्थना पत्र को तस्वीक कर स्वीकार करता हूं। मेरे समक्ष दोनों पक्षों

ने उक्त विवाद में नो डिस्पूट अवार्ड पारित करने के लिए निवेदन किया, उक्त दोनों पक्षों के निवेदन की स्वीकार कर एवं प्रार्थना पत्र में कहे कथनों के आधार पर उक्त विवाद में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है। अवार्ड वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को अंतर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जाये।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश
 [नं. एल-12012/671/87-डीII ए]

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1990

का. आ. 1108.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 अप्रैल, 1990 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th April, 1990

S.O. 1108.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Central Industrial Tribunal Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-1990.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
 उपस्थिति :—माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव,
 (आर. एन जे एम.)

मी. आई. टी. केम. नं. :—2/86

राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन परवाना भवन,
 माधोबाग, जोधपुर।

एवम्

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, हैड आफिस

निलक मार्ग जयपुर।

रेफरेंस :—अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947,

उपस्थिति :—1. श्री जयन्ती लाल शाह अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक उपस्थित।

2. श्री टी. एन. टन्डन अधिवक्ता, प्रार्थी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर।

3. दिनांक अवार्ड :—6-11-89

अवार्ड

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के डेस्क अधिकारी ने, यह रेफरेंस जरिये आज्ञा संख्या नं. एल-12012/130/83-डी-II ए दिनांक 6 जनवरी, 1986, अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिया जायेगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को भेजा :—

“Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur in relation to their Taranagar Branch in terminating the services of Shri Mohan Singh Jat, watchman cum-Poon in July, 1974 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?”

बाद प्राप्ति निर्देश इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया और उभय का नोटिस जारी किये गये।

राजस्थान बैंक एम्प्लॉईज यूनियन, जिसे तत्पश्चात् यूनियन लिखा जायेगा कि जनरल सेक्रेटरी ने प्रार्थी श्रमिक मोहन सिंह जाट चौकीदार-कम-पियोन के सम्बन्ध में निम्न-लिखित स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत किया जो अंग्रेजी भाषा में पेश किया गया परन्तु अनुवाद के पश्चात् निम्न प्रकार से वर्णित किया गया जाता है।

यह कि श्री मोहन सिंह जाट को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के तारानगर ब्रांच में जुलाई 1973 में नियोजित किया गया था जो वहां जुलाई 1973 तक चलता रहा। जिसकी सेवाएं स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तारानगर शाखा, जिसे संक्षिप्त में बैंक लिखा जायेगा, ने मनपसन्द तरीके से बिना कारण समाप्त कर दिये और समाप्ती पर श्रमिक को छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया। इस सम्बन्ध में आगे यह व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक मोहन सिंह ने एक क्लैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया। बैंक के लिए छंटनी करने समय छंटनी का मुआवजा दिया जाना अनिवार्य था। मगर बैंक ने ऐसा न कर धारा 25(एफ) अधिनियम का उल्लंघन किया।

आगे यह व्यक्त किया कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, और छः बैंक में स्टेट सेक्टर के बैंक कर्मचारियों की एसोसियेशन के साथ सुन्दर मर्गो का केस जो 6-1-76 को फैसला हुआ उनके मध्य एक मुद्दावाहुआ कि जिन कर्मचारियों ने एक क्लैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य कर लिया था उनको बैंक वैसेज सहित पुनः सेवा में बहाल कर दिया जायेगा।

औद्योगिक विवाद संख्या 8/78 में एक शपथ-पत्र बैंक की ओर से प्रस्तुत किया गया। और उस शपथ पत्र के आधार पर नोटिफ़िकेशन अर्वाइड पारित किया गया। प्रार्थी श्रमिक मोहन सिंह जाट का केस भी बैंक और एसोसियेशन के उपरोक्त मुद्दायदे कवर होता है। परन्तु मोहन सिंह को बैंक की ओर से पुनः सेवा में बहाल नहीं किया गया। और बैंक ने इस प्रकार मुद्दायदे का भी उल्लंघन किया है। बैंक के लिए यह अनिवार्य था कि उपरोक्त मुद्दायदे की पाबन्दी कर श्री मोहन सिंह जाट के पिछे हटाने की निधि से वेतन सहित बहाल किया जाना था। बैंक ने इस प्रकार धारा 25(बी) व 25(एच) का उल्लंघन किया इसके अनिर्वित धारा 25(एफ) अधिनियम का उल्लंघन किया जाना व्यक्त किया।

यह कि बैंक ने अर्वाइड के प्रावधान बाई पार्ट टाइट का भी इस प्रकार उल्लंघन किया है जिनको बैंक द्वारा पाबन्द किये जाने की पूरी पाबन्दी थी। दिनांक 5-2-87 को श्री पी.के.

लाहोरी प्रबन्धक, इन्डस्ट्रियल रिलेशन अप्रार्थी बैंक ने स्टेट-मेन्ट आफ क्लेम का उत्तर निम्न प्रकार से पेश किया।

यह कि प्रार्थी श्रमिक का स्टेटमेंट आफ क्लेम भ्रामिक है। यह भी एतराज दिया कि प्रार्थी श्रमिक इस न्यायाधिकरण की अधिकारिता का उपयोग नहीं सकता था।

यह कि निर्देशन राज्य सरकार के आदेश के परे नहीं रखा जा सकता मौजूदा औद्योगिक विवाद भेजे गये रेफरेंस की परिधि में नहीं आता है इसलिए निरस्त किया जाये।

आगे यह भी एतराज लिया कि किसी कर्मचारी को अधिनियम की धारा 2(00) के तहत एक विशेष अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो उस अवधि तक के समय तक कार्य करने के उपरान्त वह विवाद नहीं उठा सकता है। यह भी एतराज लिया कि क्लेम को राजस्थान बैंक एम्प्लॉईज यूनियन के महासचिव के द्वारा, फाईल किया गया है और उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित व प्रभावित किया गया है। और यह क्लेम मोहन सिंह जाट की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने ऐसा किया गया है जो चलने के काबिल नहीं है। प्रार्थी श्रमिक की सेवा सेवा समाप्ति का क्लेम प्रार्थी स्वयं के द्वारा पेश किया जाना चाहिये।

उपरोक्त प्रारंभिक एतराज के अनिर्वित यह भी आगे एतराज लिये गये हैं कि श्री मोहन सिंह जाट ने एक क्लैण्डर वर्ष में लगातार औद्योगिक कर्मकार के रूप में कार्य नहीं किया था इसलिए वह कोई अनुतोष औद्योगिक न्यायाधिकरण से पाने का अधिकारी नहीं है। यह प्रार्थी श्रमिक पर भी भार है कि एक क्लैण्डर वर्ष में 240 दिन से कार्य करना प्रमाणित कराये। यद्यपि श्रमिक की ओर से यह कहा गया है कि प्रार्थी श्रमिक ने जुलाई 1973 से ल. ल. जुलाई 1974, तक कार्य किया परन्तु ऐसा कोई प्रलेख पेश नहीं किया वास्तव में एक क्लैण्डर वर्ष में 240 दिन तक निरंतर कार्य किया।

अप्रार्थी बैंक की ओर से यह भी एतराज किया गया है कि प्रार्थी ने क्लेम बहुत देरी से पेश किया है और भारत सरकार श्रम एवं पुनर्वासि मंत्रालय ने उनके पत्र संख्या नं.-एल 12012/130/63-डी iii (ए) दिनांक 16-9-83, में यह निर्णय ले लिया था कि इस निर्देश का विवाद बहुत लंबे समय के बाद उठाया गया है इसलिए इस विवाद को रेफर न किया जाये। और इसी विचार को दिनांक 28-3-84 के पत्र में समर्थन कर दिया था इस को देखते हुए, इस देरी से पेश किये गये क्लेम एक्जुलिवेन ना किया जाये, इस तथ्य को भी नकारा प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं बिना कारण मनमाने ढंग से समाप्त की गई हो इस संबंध में यह भी कहा कि प्रार्थी श्रमिक को बिल्कुल अस्थायी तौर पर एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किया गया था।

स्टेटमेंट आफ क्लेम के पैरा सं 2 का उत्तर देते हुए, बैंक ने कहा कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्त करते समय उसे छंटनी का मुआवजा दिये जाने के बारे में कोई प्रश्न पैदा नहीं है क्योंकि धारा 25(एफ) के प्रावधान अप्रार्थी कोई फायदा नहीं उठा सकता है।

आगे व्यक्त किया कि यदि प्रार्थी थनिक एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य कर लेता तो बैंक उसे अवश्य ही पुनः नौकरी में बहाल कर देता मगर जब उसने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया तो वह न छुटनी कामुआ-बजा पाने का अधिकारी था। आगे व्यक्त किया कि श्री मोहन सिंह जाट का केस स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एंड स्टेट सेक्टर बैंक एम्प्लोईज एमोसिपेशन के बीच हुए मुनाफों से कवर नहीं होता है इसलिए वह इस मुहायदे से कोई लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए बैंक के द्वारा धारा 25(जी) व 25(एफ) का उल्लंघन नहीं किया गया है। बैंक बाई पार्ट टाईट का उल्लंघन नहीं किया है।

आगे मजिद तिथि में यह कहा गया है कि छुटनी की परिभाषा अधिनियम 49 के द्वारा पबदली गयी और रिट्रैच-मेंट की परिभाषा में 2(10) के साथ 2 बी बी सेवा की (जोड़ दिया गया है। किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ती उसकी सेवा संविधा एक निश्चित अवधि के लिए हो उसकी समाप्ती पर की जाती है और वो छुटनी की परिभाषा में नहीं आयेगा। और एक प्रकार का संशोधन भूतलक्षी परिवर्तन होता है जो पीछे से लागू समझा जाना चाहिये। इसके अनतिरिक्त यह भी एनराज लिया गया है कि प्रार्थी श्रमिक पूरे वेतन सहित बहाल किये जाने का अधिकारी इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसने उसका गेमपुल नियोजित रहने का तथ्य छुपाया है।

अतः प्रार्थना की कि प्रार्थी श्रमिक के क्लेम को खारिज किया जाये। प्रार्थी यूनियन के क्लेम को समपुष्टी में भी मोहन सिंह ने स्वयं क शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे इस न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया है।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक ने श्रमिक मोहन सिंह से जिरह की।

प्रार्थी यूनियन की ओर से साक्ष्य समाप्त की। प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रलेख एक्जीविट डब्यू-1 डब्यू-5 साक्ष्य में ग्राह्य कराये गये। बैंक की ओर से एक्जीविट एम-1 लागूयत इ. एक्स. एम.-3 साक्ष्य में ग्राह्य हुए।

मैंने बहस योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष का रान सूनी है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि आया प्रार्थी श्रमिक मोहन सिंह पुत्र आशा राम ने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन निरन्तर कार्य कर धारा 25 (बी) प्रमाणित होने पाये जाते हैं या नहीं।

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम श्री मोहन सिंह प्रार्थी श्रमिक का बयान काबिल गौर है श्री मोहन सिंह श्रमिक ने उसके शपथ-पत्र में यह व्यक्त किया कि उसकी नियुक्ति स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, तारा नगर शाखा में 14 जुलाई 1973 को वाचमैन कम पियोन के पक्ष पर हुई थी। आगे व्यक्त किया कि उसे माह जोलाई 1974 में मौखिक आदेश द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया। इस नियुक्ति एवम् सेवा समाप्ति के मध्यों पर इस गवाह के मध्य मुकाबिल श्री इ० मुन्नहाण्यम बैंक के गवाह का बयान काबिल गौर है। जिन्होंने उनके बयान यानि शपथ-पत्र के पैरा चार में यह व्यक्त किया है "श्री मोहन सिंह जाट ने औद्योगिक विवाद

अधिनियम 1947, की धारा 23(बी) के अनुसार 12 माह में 240 दिन निरन्तर सेवा पूरी नहीं की थी। इस प्रकार उपरोक्त दोनों माध्य को जुवानी साक्ष्य में एक दूसरे के विरुद्ध जनरल बे में साक्ष्य दी है जो जुवानी साक्ष्य इस विवादित बिन्दु को तय करने में पर्याप्त नहीं है मगर जुबानी साक्ष्य के अतिरिक्त प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रलेख इ. एक्स. डब्यू-2 प्रस्तुत प्रमाणित करवाया गया है एवम् प्रार्थी बैंक की ओर से पेश किया गया पत्र इ. एक्स. डब्यू. 3 काबिल गौर है। इम. एक्स. एम.-3 काबिल गौर है इ. एक्स. एम.-3 बांच मैनेजर की ओर से लिखा गया पत्र है जिसमें जुलाई 1973 से जुलाई 1974 तक प्रार्थी श्रमिक के द्वारा 236 दिन बतौर बदली वाचमैन के कार्य करना माना गया। और कार्य करना दिखाया गया है इसके अतिरिक्त इ. एक्स-डब्यू-2 वह पत्र है जो स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मैनेजर श्री डी. एन. बसु की ओर से सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय अजमेर को निर्देशित किया गया है। जिसके पैरा 1 के सब पैरा 2 में यह व्यक्त किया गया है कि ऐसा पोइण्ट ग्राउंट किया गया। दिसम्बर मन् 1973, में श्री मोहन सिंह ने 21 दिन कार्य किया। परन्तु उसे 20 दिन का वेतन दिया गया और इसके अतिरिक्त विपक्षी ने यह बताया कि संबंधित कर्मचारी ने 12-12-73 से 31-12-73 तक पूरे तीन सप्ताह काम किया परन्तु उसे 3 दिन का वेतन विकली होलीडेज का नहीं दिया गया और इससे ऐसा चाहा गया है कि प्रार्थी श्रमिक की कार्य दिवसों में तीन ओर जोड़े जाएं। इस प्रकार के कथन से श्री डी. एन. बसु यूनियन के उक्त विचारसहमति प्रकट करते हुए। इ. एक्स. डब्यू.-2 के पैरा संख्या-2 में यह स्वीकार कर लिया है कि प्रार्थी श्रमिक के कार्य दिवसों में 4 दिन ओर जोड़े जावें और इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक की अस्थाई नियोजन की अवधि 240 दिन कर ली जावे। इ. एक्स. डब्यू-2 में यह निबन्धेय प्रभावित हो जाता है प्रार्थी श्रमिक मोहन सिंह जाट ने उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन निरन्तर कार्य कर लिया था और वह इस प्रकार 240 दिन निरन्तर करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था। धारा 25(बी) के प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावित होने पावे जाते हैं।

अप्रार्थी नियोजक बैंक की यह पिलि की प्रार्थी श्रमिक ने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन निरन्तर कार्य नहीं किया। और धारा 25(एफ) कोई उल्लंघन नहीं होता है न ही प्रार्थी श्रमिक की छुटनी किया जाना पाया जाता है यह पिलि भी फेल होती है। दूसरी मुख्यता पिलि यह ली गई है। प्रार्थी श्रमिक को एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया गया था और उस अवधि की समाप्ती पर आगे सेवा अवधि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस सम्बन्ध में नियोजक बैंक की ओर से अधिनियम 49 और 1984 का हवाला दिया गया है। जिससे कि छुटनी की परिभाषा में 2900 (बीबी) ओडा गया है जिसमें कर्मकार की सेवा समाप्ती नियोजन की संविदा रनिबल न किये जाने पूर्व यानि नियोजन की अवधि समाप्त होने पर समाप्त समझी जाने का प्रावधान और जोड़ने से यह बहस की है कि इस प्रकार जबकि प्रार्थी श्रमिक

सेवा यानि निशेजन एक निश्चित अवधि के लिए था जो उस अवधि की समाप्ति पर रिनिवेल न किये जाने की सूचना में छंटनी की परिभाषा में नहीं रहता है।

मैं योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की इस बहस से सहमत नहीं हूँ कि यह संशोधन 18-8-84 को लागू किया गया है। जबकि प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं जुलाई 1973 से समाप्त कर दी गई थीं। यह संशोधित भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है और ऐसी सूचना में नियोजक की यह विलि उसे फायदा नहीं पहुंचाती है। प्रार्थी की सेवाएं जुलाई 1973 में समाप्त की गई हैं। वह छंटनी की परिभाषा में आती है। एल.एल.जे. का बाल्यम एक 1977 परिशिष्ट (1) में यह विनिश्चित किया गया है कि:

In the facts and circumstances of the case, giving the full effect to the words "for any reason whatsoever" would be consistent with scope and purpose of S. 25F and not contrary to the scheme of the Act.

इसके अनतिरिक्त 1985 लेब. आई. सी. पेज 1773 में श्री उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि नियोजक द्वारा श्रमिक का नाम काट देना सेवा समाप्ति की परिभाषा में आता है और ऐसी सेवा समाप्ति छंटनी है। धारा 2(00) अधिनियम की ओर से यदि ऐसा धारा 25 (एफ) के आजापक प्रावधान के उल्लंघन में की गई है तो वह छंटनी अवैध होगी।

यह तय किया जा चुका है कि प्रार्थी श्रमिक मोहन सिंह जाट ने उसकी सेवा समाप्ति में 240 दिन एक कलैण्डर वर्ष में कार्य कर लिया था। उसको सेवा समाप्ति का एक माह का नोटिस नहीं दिया गया था नोटिस पे दिया ना ही छंटनी का मुआवजा दिया जो धारा (25) अधिनियम के तहत दिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक की कि छंटनी धारा (25) एफ अधिनियम के तहत अवैध है। इसके अनतिरिक्त योग्य अधिवक्ता बैंक ने एक यह ऐतराज श्री बहस के दौरान लिया है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रार्थी श्रमिक के केस को खूद ही प्रारम्भ में अधिकरण को न्याय निर्णय के लिए न भेजने का निर्णय लिया था क्योंकि यह विवाद बहुत देरी में उठाया गया है। इस सम्बन्ध में ड. एक्स. एम-1 को निर्देशित किया गया था। इसके अनतिरिक्त यह भी बहस की ड. एक्स. एम-2 की रेशनी में भारत सरकार ने पूर्व के निर्णय संख्या एल-12012/130/83-डी II (ए) दिनांक 16-9-83 को बदलने का कोई औचित्य नहीं समझा और इस. एक्स. एम-2 के द्वारा प्रार्थी युनियन के सचिव को सूचना भी दी थी। इस प्रकार सरकार स्वयं ने देरी के कारण प्रार्थी का विवाद न्यायाधिकरण को निर्देशित नहीं किया। अब जो बनावट कारण बताये रेफरेंस भेजा है उसमें यह स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रमिक का बलेम और भी बेलेटिड यानि देरी से किया गया है। जिस प्रार्थी के बलेम को खारिज किया जावे।

इस सम्बन्ध में यह लिखना पर्याप्त होगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अपना विवाद प्रस्तुत

करने के लिए कोई निमित्तेशन यानि मियाद अधिनियम में नहीं रखी गयी है। जहां तक है। इस प्रकार अवैध छंटनी पाई जाती है। इस अवैध छंटनी के कारण प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति से पूर्वत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है। अतः प्रार्थी श्रमिक के पक्ष में निम्न एवार्ड पारित किया जाता है।

यह कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, के तारानगर शाखा, के प्रबन्धतंत्र द्वारा भी मोहन सिंह जाट चौकीदार-कम पियोन की सेवा जुलाई 1974 से समाप्त करना उचित एवं न्याय संगत नहीं थी। प्रार्थी की सेवा धारा 23 (एफ) के आवश्यक प्रावधान उल्लंघन में की गई जो सेवा समाप्ति का आदेश अवैध होने के कारण प्रार्थी श्रमिक को उसकी सेवा समाप्ति से पूर्वत पद व वेतन पर बहाल किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति की तिथि में बहाल किये जाने की तिथि के मध्य का ब्रेक वेजेज प्राप्त करेगा और उसकी सेवा में निरन्तरता मानी जायेगी। इस अवधि के दौरान यदि अन्य कोई लाभ अर्जित हुए हों तो भी वह प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीन

[संख्या एल-12012-130/83-डी II (II)]

सुभाष चन्द्र शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1990

का. आ. 1109—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोक लि. की कतराम चौतुडीह कोलपरी के प्रबन्धतंत्र के सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनवाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-3-1990 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th April, 1990

S.O. 1109.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Katras Choitudih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited their workmen, which was received by the Central Government on 29-3-1990.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 337 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Katras Choitudih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri J. P. Singh, Advocate.

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 22nd March, 1990

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/169/86 D.III (A) dated, the 16th October, 1986.

SCHEDULE

"Whether the demand of Dalit Mazdoor Sangh that the management of Katras Choitudih Colliery of Bharat Coking Coal Limited should give employment to a dependent of their workman, Shri Bhadi Bhuia, Wagon Loader who was found by Medical Board on 29-10-81 to be physically unfit to continue work due to disease, is justified under para 10.4.3 of the National Coal Wage Agreement-II? If so, to what relief is he entitled?"

The case of the workmen is that Bhadi Bhuia was appointed as a wagon loader on 7-1-73 in Katras Choitudih colliery of BCCL. He was a permanent wagon loader of the said colliery. The management of Katras Choitudih colliery sent Bhadi Bhuia for his examination by the medical board at Koyala Bhawan headquarters of BCCL. The medical board declared that Shri Bhadi Bhuia was suffering from Leprosy and thereafter sent the report of the medical board to the G.M. Katras Area vide letter dated 29-10-81. The Personnel Manager, Katras Area by letter dated 11-11-81 sent an order to the Supdt. of Katras Choitudih colliery to stop the work of Bhadi Bhuia wagon loader. Thereafter Supdt. of Katras Choitudih colliery stopped the work of Bhadi Bhuia. The head office of the Koyala Bhawan sent an order to the Personnel Manager, Katras Area that full details of the son of Bhadi Bhatia be furnished. The Personnel Manager of Katras Area wrote a letter dated 11-11-81 to the Dy. C.M.E. Katras Choitudih colliery asking for the details of the dependent of Bhadi Bhuia for giving employment but the management of Katras Choitudih colliery did not comply with the said order. Thereafter the Dalit Mazdoor Sangh raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad vide letter dated 23/24-4-81. The Personnel Manager (IR) of the headquarters Shri B. N. Jha wrote in his files that the dependent of Bhadi Bhuia be provided with employment. The G.M. (Personnel) of Karmik Bhawan of BCCL sent an order to all the G.M. of the Area and all the colliery Managers that if the services of any workmen is terminated due to disease like cancer, leprosy, madness or T.B. then his dependent should be provided with employment. Shri B. N. Jha G. M. personnel of BCCL Karmik Bhawan by letter dated 4/14-3-85 sent an order to all the Area G.M. and head of the department stating that all the workmen who retire after 1-11-79 on the ground of some disease, his dependent should be provided with employment. Para 10.4.3 of NCWA-II provides that workmen who are permanently disabled will be provided with employment of one of his dependent on a certificate being granted by the management declaring permanent disablement of the workmen and that the services of the workmen has been terminated by the management on that account. The management is knowingly vexing the Harijan workman. On the above facts it is proved that a dependent of Bhadi Bhuia should be provided with employment.

The case of the management is that the workmen have not disclosed the name of the dependent of Bhadi Bhuia whose employment is sought in place of Bhadi Bhuia. Shri Bhadi Bhuia was employed in Katras Choitudih colliery as a casual wagon loader. He was not a regular wagon loader. Casual wagon loaders are employed in the different collieries according to the well recognised and time honoured practice and they are provided employment only when additional workmen over and above the regular wagon loaders are required on in particular day. There is no guarantee of employment to them or contract of service that they will be given the job every day. Casual wagon loaders are employed day to day subject to availability of work and there is no provision or guarantee of long term employment. When a casual wagon loader himself is not entitled to his employment on all working day it is neither logical nor does it stand to reason that the so-called dependent of casual workers should be provided regular employment when the casual workers become

unfit for work for any reason whatsoever. According to the management information Shri Bhadi Bhuia does not have any dependent. He had never produced any such dependent nor gave any particulars of his dependent to the management at any time. The sponsoring union is trying to induct an impersonator in the garb of dependent of Shri Bhadi Bhuia in the employment of the management. The reference order seeks to enforce the provision of NCWA-III through the process of adjudication. The enforcement of settlement/agreement cannot form the subject matter of an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the I. D. Act. Para 10.4.3 of NCWA-II is not applicable to casual workers. The dependent of the deceased casual workers have not been provided employment in any of the subsidiary company of Coal India Ltd. under para 10.4.3 of NCWA-II or para 9.4.2 of NCWA-III. The so-called dependent of Shri Bhadi Bhuia a casual wagon loader is not entitled to claim employment under para 10.4.3 of NCWA-III. On the above facts the management prays to hold that the reference order is not maintainable and that the Tribunal may hold and decide the reference in favour of the management that the so-called dependent of Shri Bhadi Bhuia is not entitled to any relief.

The points for determination in this case are :-

1. Whether the dependent of Bhadi Bhuia is entitled for employment under para 10.4.3 of NCWA-II and
2. Whether Nageswar Bhuia being Nati (daughter's son) of Bhadi Bhuia is a dependent of Bhadi Bhuia.

The workmen examined 4 witnesses before me to establish the case of the workmen. The management did not examine any witness. The documents of the workmen are marked Ext. W-1 to W-13. No document has been exhibited on behalf of the management.

Point No. 1

Provision of employment to dependents is made in para 10.4.1 to para 10.4.4 of NCWA-III. Para 10.4.1 of NCWA-III provides that employment will be provided to one dependent of workers (1) disabled permanently and those (2) who meet with death while in service. The provisions for implementation of the same is provided in the subsequent para 10 of NCWA-III. Para 10.4.2 provides for employment of one dependent of the worker who dies while in service. It provides that the dependent for this purpose means, the wife/husband as the case may be, unmarried daughter, son and legally adopted son and if no such direct dependent is available for employment then younger brother/widowed daughter/widowed daughter-in-law or son-in-law residing with the deceased and almost wholly dependent on the earning of the deceased may be considered the dependent of the deceased.

Para 10.4.3 of NCWA-III provides for employment to one dependent of a worker who is permanently disabled in his place and that the disablement of the worker concerned should arise from injury or disease be it of a permanent nature resulting into loss of employment and it should be certified by the Coal company concerned. Although para 10.4.2 of NCWA-III is in respect of giving employment of one dependent of the worker who dies while in service but it defines the dependent for the purpose of giving employment to the dependent of an employee who dies while in service. In para 10.4.3 of NCWA-III dependent for the purpose of 10.4.1 has not again been stated as it has already been stated in 10.4.2 of NCWA-III. Thus on disablement of the worker concerned resulting into loss of employment is also entitled for the employment one of his dependent as enumerated in para 10.4.2 of NCWA-III. We cannot have a different meaning of a dependent for the purpose of para 10.4.3 from the persons enumerated as dependents in para 10.4.2. Thus an employment to the dependent of the disabled workmen can be provided with employment if he comes in the category of dependent as enumerated in para 10.4.2 of NCWA-III.

So far the question of disablement of Bhadi Bhuia because of his disease of Leprosy is concerned the same is almost admitted resulting into loss of his employment. No separate certificate by the Coal company concerned to Bhadi Bhuia has been issued but there is material to show that Bhadi Bhuia lost his employment due to Leprosy to which he was suffering. Bhadi Bhuia has examined himself as WW-1 and has stated that the management declared him unfit and stop

ped him from work with effect from 29-10-81 as he was declared unfit after medical board examined in Koyala Bhawan. He has stated that he was stopped from work declaring him to be suffering from Leprosy. He has also stated that he was made permanent and that he has no son or daughter. It will appear from his evidence that his daughter and son-in-law died long ago and their son Nageswar Bhuia was brought up by Bhadi Bhuia and his wife. WW-2 the wife of Bhadi Bhuia has corroborated her husband. She has stated that they have no paper to show that Bhadi Bhuia or she herself had applied for employment of Nageswar Bhuia in place of Bhadi Bhuia. WW-3 Nageswar Bhuia whose employment is sought by Bhadi Bhuia as his dependent daughter's son. WW-4 is Shri Karu Ram, General Secretary of Dalit Mazdoor Sangh, Exts. W-1 in item No. 4, Ext. W-2 in item No. 4, Ext. W-3 in item No. 25, Ext. W-4 in item No. 18, Ext. W-6 in item No. 9 of the recorded note of discussion between the management and Shri Karu Ram, General Secretary of Dalit Mazdoor Sangh shows that the union had demanded for giving employment to the dependent of Bhadi Bhuia and in Ext. W-1 and W-2 it was decided that the attendance of Shri Bhadi Bhuia be verified. In Ext. W-3 item No. 25 it was decided that Area will examine the case of Bhadi Bhuia and send recommendation at the earliest. Ext. W-4 in item No. 18 shows that if the claim is covered by the scheme it shall be examined and expedited on its merit. In Ext. W-6 item No. 9 it was decided that Attendance of Bhadi Bhuia casual wagon loader is to be checked if he had put in minimum 240 days attendance during the year in 1981 or 1982 i.e. before he was declared medically unfit by the Medical Board. This item shows that Bhadi Bhuia was declared medically unfit by the medical board and according to the evidence of the workmen the services of Bhadi Bhuia was terminated with effect from 29-10-81. In spite of the said decision by the management and the union it appears that the management took no step in the direction of the decisions made by the management. However, it is clear that Bhadi Bhuia was stopped his work after being declared medically unfit by the Medical Board on the ground that he was suffering from Leprosy.

As Bhadi Bhuia lost his employment being declared medically unfit by the medical board and the said fact finds support from the decision made in item No 9 of Ext. W-6 and therefore even if no certificate has been provided to Bhadi Bhuia in accordance with the terms of para 10.4.3 (I) of NCWA-III. Bhadi Bhuia is entitled that one of his dependant should be given employment under the provision of para 10.4.3 of NCWA-III provided that the dependent claiming employment in place of Bhadi Bhuia is a dependent as enumerated in para 10.4.3 of NCWA-III. This point is accordingly decided in favour of the workmen.

Point No. 2

It will appear from the evidence of WW-1 Bhadi Bhuia his wife WW-2, Shri Karu Ram, WW-4 and WW-3 Nageswar Bhuia that Nageswar Bhuia is the daughter's son of Bhadi Bhuia. Although the management has disputed the fact that Nageswar Bhuia is the daughter's son of Bhadi Bhuia no serious attempt has been made on behalf of the management to show that Nageswar Bhuia is not his Nati (daughter's son) of Bhadi Bhuia. In the above view of the matter I hold that Nageswar Bhuia is the daughter's son (nati) of Bhadi Bhuia.

It has been seriously contended on behalf of the management that the name of the dependent for whom employment was being sought for as dependent of Bhadi Bhuia was neither disclosed in the different minutes of discussion Ext. W-1 to W-6 nor the name of Nageswar Bhuia was disclosed as daughter's son of Bhadi Bhuia in the W.S. of the workmen. It was for the first time in the evidence of the parties that the workmen came out with a case that Nageswar Bhuia is the daughter's son of Bhadi Bhuia. The fact that neither Bhadi Bhuia nor his union had ever expressed the name of the dependent Nageswar Bhuia as Nati of Bhadi Bhuia shows some doubt as to why the name of the dependent of Bhadi Bhuia was not disclosed earlier so that the management could ascertain if Nageswar Bhuia was the daughter's son of Bhadi Bhuia. Be that as it may, I have already come to a finding that Nageswar Bhuia is the daughter's son of Bhadi Bhuia and we shall proceed on the said finding whether Nageswar

Bhuia is entitled to get employment as dependant daughter's son of Bhadi Bhuia

I have already discussed above that para 10.4.2 of NCWA-II which is equivalent to para 10.4.2 of NCWA-III deals with employment of a dependent and enumerates persons who are to be reckoned as dependent of the employee who has lost his employment either due to his death while in service or who is permanently disabled. The category of dependents is confined to the relationship of (1) wife/husband as the case may be (2) unmarried daughter (3) son/legally adopted son. In case of failure of the dependents stated above employment may be given to a dependent of the employee who is his (1) younger brother/widowed daughter/widowed daughter-in-law or son-in-law residing with the deceased and almost wholly dependent on the earning of the deceased/permanently disabled workmen. Thus the daughter's son is not enumerated as one of the dependents who can be provided with employment in place of the workmen who has been permanently disabled. We cannot impart and include other relations of disabled workmen for giving employment and if the so-called dependent is not stated in the provision of para-10 of NCWAs, he cannot be stated to be the dependent under NCWA-III or II on the basis of which the claim is being made. We cannot bring all the heirs of any person as dependent for the purpose of para-10 of NCWA-II or para-9 of NCWA-III and we have to confine meaning of dependent as enumerated in para 10.4.2 of NCWA-III or para 10.4.2 of NCWA-III. On perusal of para 10.4.1 it will be clear that para 10.4.2/para 10.4.3 of NCWA-III/para 10.4.2/para 10.4.3 of NCWA-III are applicable in the case of giving employment to one dependent of worker disabled permanently and those who meet with the death while in service and as such the definition of dependent has to be read for para 10.4.2 and 10.4.3 as is stated in para 10.4.2 of NCWA-II or para 10.4.2 of NCWA-III. The case of Nageswar Bhuia claiming to be the daughter's son of Bhadi Bhuia is not covered as dependant in 10.4.2/9.4.2 of NCWA-III. I hold that Bhadi Bhuia cannot claim employment for Nageswar Bhuia as his dependants.

In the result, I hold that the demand of Dalit Mazdoor Sangh that the management of Katras Choitudih colliery of M/s. BCCL should give employment to Nageswar Bhuia, a daughter's son as dependent of Bhadi Bhuia wagon loader, who was found by the medical board on 29-10-81 to be physically unfit to continue work due to disease is not justified under para 10.4.3 of NCWA-II. Accordingly he is entitled to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012(169)/86-D.III(A)/IR(C.D)]

का. धा. 1110—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. का भोवरा एरिया संख्या 11 की जीलगोरा कोलिअरी के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है।

SO. 1110.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Bhowra Area No. XI of M/s. B.C.C. Ltd and their workmen.

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 224 of 1987

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES:

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Bhowra Area No. XI of B.C.C. Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri R. N. Mandal, Branch Secretary, RCMS Union.

On behalf of the employers : Shri S. A. R. Rizvi, Dy. P.M.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dated, the 13th March, 1990

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(199)/86-D.IV(B), dated, the 3rd August, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of Bhowra Area No. XI of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., (Distt. Dhanbad) in not regularising Smt. Rudni Kamin and seven others P. R. workmen at Annexure-A on their respective time-rated jobs is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

1. Smt. Rudni Kamin, 99824.
2. Smt. Karmi Kamin, 99826.
3. Smt. Upasi Kamin, 99815
4. Smt. Ani Kamin, 99809.
5. Smt. Sukhmati Kamin, 99809.
6. Smt. Janakwa Kamin, 99810.
7. Smt. Sino Kamin, 99804.
8. Smt. Samuntala Kamin, 99793."

In this case both the parties appeared before me and filed their respective W.S. Subsequently when the case was fixed for filing documents by both the parties, they appeared before me and filed a Petition of compromise. I heard them on the said petition of compromise and do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the petition of compromise which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-24012(199)/86-D.IV(B)/IR(Coal-I)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT
DHANBAD

Reference No. 224/87

Employers in relation to the Management of Jealgora Colliery.

AND

Their Workmen.

Petition of Compromise

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully sheweth :—

1. That the above dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :—

Terms of Settlement

- (a) That out of eight concerned workmen namely S/Smt. Rudni Kamin, Karmi Kamin, Upasi Kamin and Ani Kamin; Sukhmati Kamin Janakwa Kamin, Sino Kamin and Sakuntala Kamin two of them namely Smt. Rudni Kamin (Sl. No. 1) and Smt. Upasi Kamin (Sl. No 3) have already resigned under V.R.S. and their cases have been finalised under the said Scheme. Therefore the union drops the dispute in respect of the above two workmen namely S/Smt. Rudni Kamin (Sl. No. 1, and Upasi Kamin (Sl. No. 3).
- (b) That the management agrees to regularise the concerned ladies who are on the roll of the company as General Mazdoors in Category-I with effect from 1-1-1988. They will be fixed in the time rate scale of 1-1-1988 at the appropriate stage taking

into consideration the initial basic wages of group-III and the piece rated allowance payable to them on 31-12-1987.

(c) That the concerned ladies as well as the union will not claim for any other relief arising out of and connected with the present dispute. The dispute stands finally resolved.

(d) That in view of the above settlement there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the Settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the workmen :

Sd/-

(R. N. Mandal)

RCMS Union,

Branch Bhulanbararee

Sd/-

For the Employer :

General Manager Area-I

Personnel Manager Area-XI

नई दिल्ली 9, अप्रैल, 1990

का. आ. 1111—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 27 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट विशाखापटनम के प्रबन्धन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 9th April, 1990

S.O. 1111.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-1990.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri D. Ramalinga Swamy, B.Com., B.L., Industrial Tribunal

Dated, 12th March, 1990

Industrial Dispute No. 44 of 1987

BETWEEN

Workmen of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

AND

Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

APPEARANCES :

Sarvasri G. Bikshapathi, G. Vidya Sagar, V. Vishwanatham and N. Vinesh Rai, Advocate—for the Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Miss G. Sedha and Miss V. Usha Rani, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-34612/2/87-D.IV (A) dated 8-9-1987 referred the following dispute under Section 10(1)(d) and (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Visakhapatnam Port Trust for imposing penalty of reduction of pay by 5 stages for a period of 2 years without cumulative effect upon Sri S. S. N. Rao, Operator Grade-II, Ore Handling Complex for utter carelessness and gross negligence while performing his legitimate duties during the first shift on 9-3-1985 is justified? If not, to

what relief is the workman concerned is entitled to?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 44 of 1987 and notices were issued to the parties.

2. The chief facts relating to this dispute are as follows: S. S. N. Rao is working as an Operator Grade II under the employment of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam. On 9-3-1985, he was on duty in the first shift from 6.00 A.M. to 2.00 P.M. working as Operator Grade II at the Shipping Conveyor No. 14 tail-end in the Ore Handling Complex. He was placed under suspension on an allegation, that he was guilty of dereliction of duty at that time, and Ex. M-1 charge sheet dated 21-3-1985 was issued to him. The allegation in the charge sheet are: that while S-4 conveyor was running some unusual sounds were heard by one Satnarayana, that when he stopped S-4 conveyor, he found an M.S. angle of the length of 3½ feet in between the belt and the sixth drive pulley of S-4 conveyor in H-5-A Drive house, that it is an act of sabotage; that, but for the prompt and timely action of Satnarayana in stopping S-4 conveyor, the conveyor belt would have been completely damaged; and that the placing of the angle is evidently an act of sabotage performed either by this workman who is an Operator incharge or some other person through his active connivance. However, this workman was not directly charged for committing or for abetting any act of sabotage, but as per the wording of the charge sheet, he was alleged to be guilty of not exhibiting carelessness and guilty of gross negligence etc. The workman filed his explanation Ex. M-2 dated 1-4-1985 pleading, that he is not connected with the incident, that the person who was incharge of the drive house H-5-A is responsible for the act. An Enquiry Officer conducted an enquiry, and Ex. M-4 are the enquiry proceedings. The Enquiry Officer also made a local inspection of the place where the exact incident took place, and ultimately he submitted his report Ex. M-7 findings, that the workman is guilty of the charges. The Management issued an order imposing a punishment by reducing his pay by 5 stages for a period of two years without cumulative effect, and hence this dispute and the reference about the justifiability of that order.

3. On a Memo filed by the Management in M.P. No. 86 of 1988, this Tribunal conducted a preliminary enquiry regarding the validity of the domestic enquiry by an order dated 21-7-1988. MW-1 is the Enquiry Officer, and the Management marked Exs. M-1 to M-7. The workman did not adduce any oral evidence but marked only Ex. W-1. After recording the evidence with regard to the preliminary point, the matter was coming on for arguments. At that stage, the workman filed a memo on 13-6-1989 conceding, that the Tribunal may hold that the enquiry conducted by the Management is proper. As per the docket order made by this Tribunal on 14-6-1989, the Advocate for the Management represented to the Tribunal, that it has no objection to post the matter for adjudication on merits. Therefore, by virtue of the memo filed by the workman on 13-6-1989 and the consequent order of this Tribunal dated 14-6-1989 it must be deemed, that the workman admitted the fact that the domestic enquiry conducted is just, valid and proper and is in conformity with the principles of natural justice.

4. Therefore the following points will arise for consideration in this reference:

- (1) Whether the workman is guilty of any dereliction of duty as alleged?
- (2) Whether the action of the Visakhapatnam Port Trust imposing penalty of reduction of pay by 5 stages for a period of two years without cumulative effect upon S. S. N. Rao, Operator Grade II, Ore Handling Complex for utter carelessness and gross negligence while performing his legitimate duties during the first shift on 9-3-1985, is justified?
- (3) If not to what relief is the workman is entitled?

5. Point (1).—The workman is not challenging the truth, the M.S. angle was found in between the conveyor belt and 6th drive pulley as alleged nor he is admitting it. The charge is not, that this workman himself committed an act of sabotage by introducing the M.S. angle. The charge is, dereliction of duty for not being careful and vigilant in seeing that no such foreign body is introduced. The main plea of the workman is: that he is not responsible even if there is any negligence of duty on the part of any one. The admitted and undisputable facts are: the M.S. angle was found inside H-5-A drive house, in between the belt and 6th drive pulley of S-4 Conveyor. For a proper appreciation of the

evidence, the plans filed by Satnarayana who was examined as first witness for the Management before the Enquiry Officer, can be perused and they are Exs. M-5 and M-6. As per the evidence and plan, the S-4 conveyor belt consists of two portions namely, head-end and tail-end. The tail-end portion of S-4 conveyor was shown in this plan. A portion of the tail-end is outside H-5-A drive house, and the remaining portion of the tail-end of S-4 conveyor is located inside H-5-A drive house where in there are also six pulleys. The 'B' mark pulley shown in Ex. M-6 is the 6th drive pulley whereat, the M.S. angle was found inserted in between the pulley and the belt. Therefore, the foreign body, namely the M.S. angle was found inside the H-5-A drive house, and the tail-end portion of S-4 conveyor is partly inside H-5-A house, and partly outside the House. Evidently, no one saw as to who introduced this M.S. angle. As per the evidence of the witnesses of the Management, it could be only an act of sabotage, since there is no possibility for getting this angle in that position by way of any accident. The direction of the running belt is also shown in Ex. M-6 plan which shows, that the belt runs from the bottom side into H-5-A house and enters at the pulley 'C', and travels upward through the 6th drive pulley, take up pulley and again emerges and comes out of the H-5-A drive house, above the level of the entry belt. Therefore, there is no possibility of the angle being placed at any other position except inside H-5-A drive house near the 6th drive pulley. If the angle is placed at the position earlier than the 6th drive pulley, as the belt passes throughout three pulleys including the 5th drive pulley, it could have been detected long before it reaches the 6th drive pulley. Therefore, the main point is, as to who can be made responsible for not being vigilant in order to prevent the introduction of any such foreign body at that point? The Management examined three witnesses. G. Satnarayana is the Assistant Foreman, P. V. Murali Rao is an Executive Engineer and N. Sriramanurthy is Foreman who were examined before the Enquiry Officer, and who were referred to as S.Ws.-1 to 3 by the Enquiry Officer in his report Ex. M-7, and I shall also refer to them accordingly in this Award. The Enquiry Officer recorded the statement of these witnesses in the question and answer forms. As per the answers of questions Nos. 5 and 6 given by S.W-1, and the answers for questions Nos. 30, 31 and 39 given by S.W-2, and the answers of question Nos. 51 and 52 given by S.W-3; the workman was the Operator posted on duty for S-4 tail-end, and he was on duty on the first shift on that day, and the angle was recovered from the 6th drive pulley of S-4 tail-end conveyor. I have already stated, that S-4 tail end portion is partly in H-5-A drive house and partly outside the drive house. There is also an entrance to enter into H-5-A drive house as can be seen from Ex. M-5 and M-6. S.W-1 deposed in his answer to question No. 9, that the head-end and tail end cannot be reached by any body because, there is a partition provided. None of the witnesses stated that it is the duty of the operator on duty incharge of S-4 tail end, to watch the conveyor tail-end which is also inside the H-5-A drive house. A specific plea taken by the workman in his brief explanation Ex. M-2 dated 1-4-1985 is: that the person who is incharge of the Drive House H-5-A alone is liable for disciplinary action. The workman was examined by the Enquiry Officer, and he categorically deposed in answer to question No. 69, that ever since he was allotted to S-4 conveyor, he did not enter into H-5-A. He also stated for question No. 73, that he never entered into H-5-A House at any time. The Enquiry Officer himself made a local inspection of this S-4 tail-end conveyor, and he stated in his report at page 3: "During my site-inspection on 13-9-1985, I met Sri E. Mumford, duty Grade II Operator, S-4 Conveyor (tail-end) who also stated, that he never entered into H-5-A to check the conveyor passing through a set of pulleys. This is highly irregular. It is recommended to issue orders in written form to all concerned." Thus, even after this workman was suspended, his successor Sri E. Mumford also never entered into H-5-A house for checking the tail-end portion which is lying inside the H-5-A Drive house. There is no evidence of any departmental instructions to show, that the duty operator of S-4 conveyor tail-end, is also expected to enter into H-5-A house and to check and watch whether there is any foreign body inside the conveyor system. In the absence of any such evidence to show, that entering into H-5-A house falls part of his duty either by practice or by any departmental instructions either oral or in writing, a workman who never entered into H-5-A drive house, can be responsible for the location of a foreign body inside H-5-A drive house.

2 This case was posted to to-day for recording settlement. The Memorandum of settlement filed by both parties on 16-2-90 and a petition seeking disposal of the reference on

Ex. M-6—Diagram indicates the position of the pulleys
The direction of the running belt and the location

settlement are put-up. The second party-workman and the representative of the First Party-Management submitted that they have settled the dispute out of court in the interest of industrial peace and harmony and prayed to pass an Award in terms of the settlement. The settlement is readover and explained to the representative of both parties and they admit the contents thereof to be true and correct. The settlement appears to be fair. In the circumstance, the same is recorded and the reference is disposed of in terms of the settlement. Hence, I pass this Award in terms of the settlement. The memorandum of settlement do form part of the Award.

Dated & corrected by me.

S. K. MISRA, Presiding Officer

[No. L-26012/8/89-IR(Misc.)]

MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 12-1-90
BETWEEN SAIL, ROURKELA STEEL PLANT AND
AND UNITED MINES MAZDOOR UNION (CITU),
REPRESENTING SRI A. K. NAYAK, PL. NO. 35592,

EX-KHALASI OF BIM.

REPRESENTING MANAGEMENT :

1. Sri D. Patnaik,
Dy. CPM (M&P)
2. Sri B. K. Mohapatra,
Manager (PL) IR.

REPRESENTING WORKMEN :

1. Sri S. N. Mudali,
General Secretary, United Mines
Mazdoor Union (CITU), Tenda,
Dist. Sundergarh.
2. Ajoya Kumar Nayak,
Ex-Khalasi, BIM.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Sri A. K. Nayak was granted E.L. w.e.f. 5-7-83 to 8-7-83. After expiry of his leave, he did not report for duty on 9-7-83 and remained on unauthorised absence thereafter without any intimation to the authorities concerned. Since his unauthorised absence exceeded a period of more than 15 days, his name was struck off from the rolls of the Company w.e.f. 11-8-83 under Order No. 16(X) of the Standing Orders of BIM. The Secretary, UMMU, Tensa raised an Industrial Dispute which was conciliated upon and the dispute ended in failure. The dispute has been referred for adjudication before the Hon'ble Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar, which has been registered as I.D. Case No. 25/89(C). During pendency of the dispute, attempt was made for an amicable setting of the dispute. After protracted discussions the parties have agreed to settle the dispute out of court on the following terms :

TERMS OF SETTLEMENT

It is agreed that :

1. Sri A. K. Nayak will be appointed afresh as Semi-skilled worker in L-1 scale with the minimum Pay of L-1 and he will be posted at Rourkela.
2. In full and final settlement of his claims related to the dispute, a lumpsum amount of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only) will be paid to Sri Nayak.
3. The workman and the union agree not to raise any dispute financial or otherwise in future towards the past services of Sri A. K. Nayak or for any matter connected with the dispute.
4. This settlement fully and finally settles the dispute in I.D. Case No. 25/89(C) pending before the Hon'ble Tribunal.
5. The parties will file a joint petition before the Hon'ble Tribunal praying for passing an award in terms of this settlement.
6. The terms of settlement will be implemented within a period of 30 days from the date of receipt of the award passed by the Hon'ble Tribunal in ID Case No. 25/89(C).

SIGNATURE OF THE PARTIES

REPRESENTING MANAGEMENT :

1. Sri B. Patnaik.

2. Sri B. K. Mohapatra

REPRESENTING WORKMEN :

1. Sri S. N. Mudali
2. Sri Ajoya Kumar Nayak

WITNESS :

1. Sri N. C. Ghosh,
Manager (PL) OMIQ, RSP.
2. Sri P. N. Mohanty,
Asst. Manager (PL) IR, RSP.

का. आ. 1113—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार डायमण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट एन. एम. डी. सी. पन्ना (म. प्र.) के प्रबन्धन के सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1113.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Diamond Mining Project, NMDC, Panna (M.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on 5-4-90.

ANNEXURE

Before Shri V. N. Shukla, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Jabalpur (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(140)/1987.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Diamond Mining Project, Panna and their workman Shri Anandilal Sahu, represented through the M.P. Rashtriya Hira Khani Mazdoor Sangh, Panna (M.P.)

APPEANCES :

For Workman/Union.—Shri N. P. Mehta.
For Management.—Shri A.K. Shasi, Advocate.

INDUSTRY—Diamond Mining.

DISTRICT.—Panna (M.P.)

AWARD

Dated, March 22, 1990.

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide Notification No L-43012/28/85-D. III(B) dated 11th August, 1987, for adjudication of the following disputes :—

“Whether the action of the management of Diamond Mining Project, of NMDC, Panna in not acceding to the demand of the M.P. Rashtriya Hira Khani Mazdoor Sangh, Panna to enter correct date of joining service w.e.f. 9-8-64 in the seniority list prepared by the management in respect of Shri Anandilal Sahu is justified? If not, to what relief that workman

concerned is entitled?"

2. In this case parties have contested the dispute and filed their respective statement of claim. Documents on behalf of the management have also been filed.

3. During the pendency of the proceedings the representative of the Union, Shri N.P. Mehta, made a statement on 13-2-1990 that "Workman/Union does not want to pursue the reference. Hence order of no award be passed". Counsel for the management had no objection in this respect. In the circumstances of the case, I have no alternative but to make a no claim award and I accordingly do so. No order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer
[No. L-34012/28/85-D.II(B)]

का. आ. 1114:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार डायमण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट एन. एम. डी. सी. पन्ना (म.प्र.) के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1114.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Diamond Mining Project, NMDC, Panna (M.P.) and their workmen which was received by the Central Government on 5-4-90.

ANNEXURE

Before Shri V.N. Shukla, Presiding Officer Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Jabalpur (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(135)/1987.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Diamond Mining Project, Panna and their workman Smt. Babni Ganpat, represented through the M.P. Rashtriya Hira Khani Mazdoor Sangh, Panna (M.P.)

APPEARANCES :

For Workman.—Shri N.P. Mehta.
For Management.—Shri A.K. Shasi. Advocate.

INDUSTRY:—Diamond Mining
DISTRICT.—Panna (M.P.)

AWARD

Dated : March, 22, 1990.

This is a reference made by Central Government, Ministry of Labour, vide Notification No. L-43012/25/85-D. III(B) Dated 7th August, 1987, for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the management of Diamond Mining Project of National Minerals Development Corporation, Panna (M.P.) in not acceding to the demand of the M.P. Rashtriya Hira Khani Mazdoor Sangh, Panna to enter the correct date of joining of service i.e. 16-7-69 in the seniority list prepared by the management in respect of Smt. Babni Ganpat is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. In this case statement of claim on behalf of the workman/union has been filed. Management has filed its statement of claim and rejoinder. The case was at the stage of filing documents. But on 13-2-1990 the representative of the Union, Shri N.P. Mehta, stated before the Court that "The Union does not want to pursue the reference. Hence of no award be passed." Counsel for the management, Shri A.K. Shasi, raised no objection.

3. In the circumstances of the case, I have no alternative but to pass a no dispute award. Award is given accordingly. No order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer
[No. L-43012/25/85-D.III(B)]

का.आ. 1115:—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्थान स्टील कंस्ट्रक्शन लि. भावनाथपुर के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1115.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hindustan Steel Construction Ltd., Bhawanathpur and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 87 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Hindustan Construction Ltd., Bhawanathpur (Palamou).

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri P. R. Rakhit, Advocate.
For the Workmen : Shri J. P. Singh, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 22nd March, 1990

AWARD

By Order No. 1-26012/18/87-D-II(B), dated, the 7th June/19th July, 1988, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

"Whether the action of the management of Hindustan Steel Construction Ltd., Bhawanathpur, in stopping Shri Bhagwan Das, Driver, from work with effect from 1-7-1987 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case of the management of Hindustan Steel Works Construction Limited, Bhawanathpur, as spelt out in the written statement submitted, details apart, is as follows:

The present reference is not maintainable on the grounds that (i) it is beyond the ambit and jurisdiction of the Central Government for making such a reference under section 2(A) of the Industrial Disputes Act, 1947 inasmuch as the case of the concerned workman Bhagwan Das pertains to voluntary retirement from service on his own option, (ii) neither any union nor representative mass of workmen has sponsored the present dispute and (iii) no demand whatsoever was made on the management and (iv) appropriate Government is not the Central Government and that this Tribunal has got no jurisdiction to adjudicate upon the industrial dispute as the concerned workman, being a driver, was never a worker of the mine nor does he come under the mischief of the Mines Act. As a matter of fact the concerned workman was never stopped from work with effect from 1-7-87 because he voluntarily retired from service. He was employed by the management as driver on 29-10-73 and was posted at Bhawanathpur Works. He declared his age as 30 years at the time of joining service. The company is a construction company and a Government of India undertaking and is in the red. The company framed a scheme known as Voluntary Retirement Scheme for executives, non-executives, staff and workers and it was widely circulated amongst the employees through its circulars. Hindi version of the scheme was also widely circulated. A large number of workmen realising the spirit of and financial gain from the scheme and considering their physical condition opted for such scheme which was absolutely voluntary. The concerned workman opted for voluntary retirement and in terms of circular No. GMP&A/Estt/9/86 dated 31-5-86 submitted an application on 23-6-87 praying therein for retirement with effect from 30-6-87. The management accepted his prayer and by Office Order being No. HSCL/PL/VR/BNP/87-888 dated 27-6-87 issued order for retirement of fifteen workmen including the concerned workman under Voluntary Retirement Scheme with effect from 30-6-87. A copy of this order was received by all individual including the concerned workman who received it on 29-6-87. Thus, in terms of the aforesaid order the concerned workman stood retired from service and was relieved from duty of the company with effect from 30-6-87. The other fourteen workmen who are covered by Office Order dated 27-6-87 received their full and final payment in terms of their applications for retirement under Voluntary Retirement Scheme. The concerned workman submitted also an application for payment of gratuity and provident fund which lends support to his action in the matter of submitting option for voluntary retirement. The company prepared statement of account relating to his retirement benefit and the entire amount was tendered for payment to him which he refused. The management was surprised to receive a notice from Asstt. Labour Commissioner (C), Ranchi in respect of his voluntary retirement. Anyway the representative of the management explained the full facts before the Asstt. Labour Commissioner (C), Ranchi. He intended to withdraw his consent from voluntary retirement before Asstt. Labour Commissioner (C), Ranchi but that was not permissible because consent could be withdrawn before acceptance of any application for retirement under Voluntary Retirement Scheme. He has not been stopped from duty with effect from 1-7-1987. It is asserted that the management is fully justified in accepting his application for voluntary retirement. In the circumstances, the management has prayed that this Tribunal be pleased to hold that the concerned workman voluntarily retired from service with effect from 30-6-87 and that he was not stopped from work with effect from 1-7-87.

3. The case of the concerned workman as appearing in the written statement submitted, briefly stated, is as follows:

The concerned workman is represented by Bokaro Steel Rashtriya Mazdoor Sangh, Bhawanathpur Branch which is also called Palamou Chuna Pathar Khan Mazdoor Sangh. The present industrial dispute was raised by the Secretary of the union, Shri Sambhu Nath Singh before the Asstt. Labour Commissioner (C), Ranchi by his Memo dated 20-7-87. During the conciliation proceeding the management did not turn up even after due service of notice and considering the nature of the dispute the Conciliation Officer was pleased to refer the matter to the Ministry with his failure report. Consequently this dispute has been referred to this Tribunal for adjudication. The concerned workman was appointed in the service of Hindustan Steel Construction Limited as Driver on 29-10-73. After having specialised training he along with three others was upgraded from L.V. Driver to H.V. Driver with effect from 1-3-74 by Office Order dated 28-2-74. His pay was also revised by Office Order dated 29-11-74. He had also to execute an agreement dated 1-5-74 with the management. Since then he has rendered his service to the management without any blemish and during his service career no adverse remark was either made or communicated to him. He was required to serve in Bhawanathpur Lime Stone Mine as H.V. Driver; he was confirmed in the service and became a permanent employee. He served the management for more than 240 days in each calendar year after his appointment. He was orally told by some superior officer that he has been compulsorily retired from service with his consent. Since he had not signed any document relating to compulsory retirement or even voluntary retirement, he felt that the management wrongfully managed to retire him from service. He approached the management for re-consideration of his case, but the management did not relent. His date of birth is 10-2-1946 and therefore he was asked to cease the work at the age of 41 years when he should have been superannuated at the age of 60 years. This indicates that he was prematurely retired if the retirement plea of the management is found correct. The action of the management is, therefore, an instance of unfair labour practice in violation of Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947. He has prayed that he is entitled to reinstatement in service with full back wages.

4. In rejoinder to the written statement of the concerned workman, the management has denied that Bokaro Steel Rashtriya Mazdoor Sangh, Bhawanathpur Branch is also called Palamou Chuna Pathar Khan Mazdoor Sangh. Since the purported dispute was allegedly raised by the Branch Secretary of Bokaro Steel Rashtriya Mazdoor Sangh, the written statement could not be signed by Sambhu Nath Singh on behalf of the workman and for Bhawanathpur Chuna Pathar Khan Mazdoor Sangh. The management has asserted that the concerned workman being a Driver was never employed in the mine and as such the Government of Bihar is the appropriate Government. The concerned workman was engaged as Driver in the Construction Work of the management and was never engaged in the mine as alleged. The company framed rules under Voluntary Retirement Scheme and the concerned workman opted for voluntary retirement. The management did never cease the work of the concerned workman nor was he asked to stop work at the age of 41 years. He is called upon to prove that his date of birth is 10-2-46 and that he was asked to stop work on reaching the age of 41 years. The action of the management is not unfair labour practice or unjustified and the provision of Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 is not attracted in the case of voluntary retirement and, therefore, have not been violated.

5. In rejoinder to the written statement of the management, the concerned workman has disputed the substantive contention of the management and asserted that he was only 41 years of age. He had no reason to seek voluntary retirement as alleged nor had he opted for retirement under Voluntary Retirement Scheme. His positive case is that the management had obtained his signature on some papers which have been utilised for the purpose of voluntary retirement. He was asked to take advance for journey to Ranchi for medical check up but the Office Order was not received by him in time to present himself on the particular day for medical check up. He did not, therefore, undertake the journey to Ranchi and Civil Asstt. Surgeon, Bhawanathpur, did never make his medical check up. In the circumstances,

he has stated that the plea of the management as appearing in its written statement-cum-rejoinder is not worthy of acceptance.

6. The management, in order to justify its action, relating to voluntary retirement of the concerned workman under Voluntary Retirement Scheme, has examined two witnesses, namely, MW-1 Nand Kishore Prasad, now posted as Asstt. Manager (Personnel) of Hindustan Construction Works Limited at Bhabanathpur and MW-2 S. K. Sarkar, Asstt. Manager (Finance) of Hindustan Steel Works Construction Limited at Bhabanathpur and laid in evidence a sheaf of documents which have been marked Exts. M-1 to M-15.

On the other hand, the concerned workman has examined himself and laid in evidence some documents which have been marked Exts. W-1 to W-4.

7. The terms of reference of the present industrial dispute is whether the action of the management of Hindustan Steel Construction Limited, Bhabanathpur in stopping Bhagwan Das, Driver, from work with effect from 1-7-87 is justified or not. As a matter of fact the name of the employer should have been Hindustan Steel Works Construction Limited instead of Hindustan Steel Construction Limited. Anyway, it has been contended by the employer that the Central Government is not the appropriate Government to make this reference of industrial dispute for adjudication by this Tribunal.

Shri P. R. Rakhit, learned Advocate for the employer, the management of Hindustan Steel Works Construction Limited, Bhawanathpur, has submitted before me that the Central Government is not the appropriate Government competent to make this reference of industrial dispute for adjudication by this Tribunal. On the other hand, Shri J. P. Singh, learned Advocate for the concerned workman, has held fast to the view that the Central Government is the appropriate Government.

8. It has been admitted by the management in para 7(ii) that the company happens of W.S. to be a construction company and a Government undertaking. It transpires from the evidence of MW-1 Nand Kishore Prasad that the company is a Government company belonging to Government of India. In the context of these facts and evidence Shri Singh has contended that the Central Government is the appropriate Government competent to make the present reference.

There is no dispute that Hindustan Steel Works Construction Limited is a company incorporated under the Company's Act, 1956. Even so, there is no evidence that its entire share capital has been contributed by the Central Government and all its shares have been registered in the name of the President of India or an officer of the Central Government. The memorandum of Association and the Article of Association of the company have not been produced before me to show that large powers have been conferred on the Central Government including the power to give direction as regards the functioning of the company. The word 'authority', there being nothing in Section 2(a) of the Industrial Disputes Act to the contrary, must be construed according to its ordinary meaning and therefore must mean a legal power given by one person to another to do an act. It has been held in the case of Heavy Engineering Mazdoor Union Vs. State of Bihar and others, reported in 1969(II) LLJ, 549(SC) that the words 'under authority of' mean, pursuant to the authority, such as where an agent or a servant acts under or pursuant to the authority of the principal or master. The Hon'ble Court has held that a company incorporated under the Company's Act whose constitution, powers and functions are provided for and regulated by its memorandum of association and the articles of association can not be said to be carrying on business pursuant to the authority of the Central Government and that incorporated company has a separate existence and the law recognises it as a juristic person separate and distinct from its members. This new personality emerges from the moment of its incorporation and from that date the persons subscribing to its memorandum of association and others joining it as members are regarded as a body incorporate or a corporation aggregate and the new person begins to function as an entity. The mere fact that the entire share capital of the company has been contributed by the Central Government and the fact that all its shares are held by the President

and officers of the Central Government does not matter since the company so incorporated derives its powers and functions from and by virtue of its memorandum of association and its articles of association and is separate legal entity. Since the employer company is not an industry carried on by and under the authority of the Central Government, the Central Government is not the appropriate Government to make the present reference. This conclusion is reached by following the case of Heavy Engineering Mazdoor Union vs. the State of Bihar and others reported in 1969 (II) LLJ, 549 (SC) and the Hindustan Aeronautics Limited Vs. their Workmen and others reported in 1975 (II) LLJ, 336 (SC). This being the legal position the present reference is not maintainable as the Central Government is not considered to be the appropriate Government to make this reference.

9. Shri J. P. Singh, learned Advocate for the sponsoring union, has further submitted that since the concerned workman was employed in Bhawanathpur Lime Stone Mine of the management, the Central Government is the appropriate Government to make the instant reference of the industrial dispute before this Tribunal. Shri P. R. Rakhit, learned Advocate for the management has contended that the concerned workman was never employed in the mine as aforesaid and so the present reference is not maintainable.

The pleading of the sponsoring union discloses that the concerned workman was required to serve in Bhawanathpur Lime Stone Mine of the management as H. V. Driver. This has been totally disputed by the management in its rejoinder. The management has stated emphatically that the concerned workman was engaged as Driver in the Construction Work of the management and was never engaged in the mine as alleged and that the management company was never engaged in mine's work. In the context of this pleading the sponsoring union and for the matter of that the concerned workman are required to prove that the concerned workman was engaged by the management in Bhawanathpur Lime Stone Mine belonging to the management. Not a scintilla of evidence has been laid to establish the fact that the concerned workman was engaged Bhawanathpur mine by the management or that the said mine belongs to the management. Even the concerned workman has not examined himself on this point. That being so, I come to the inescapable conclusion that there is no merit in the contention of Shri Singh that the concerned workman was engaged in Bhawanathpur Lime Stone Mine of the management. In this view of the matter the present reference also founders on the ground.

10. The terms of reference indicates that the concerned workman was stopped from duty. The concerned workman has also fashioned his case on that footing in the written statement. But the management has contended that the concerned workman was never stopped from duty and that he retired from service voluntarily under Voluntary Retirement Scheme.

11. The concerned workman has not raised this industrial dispute under Sec. 2-A of the Industrial Disputes Act. It has been stated in the written statement of the concerned workman that he is represented by Bokaro Steel Rashtriya Mazdoor Sangh, Bhawanathpur Branch which is also called Palamou Chuna Pathar Khan Mazdoor Sangh and that the dispute was raised by the Secretary of the union Shri Sambhu Nath Singh before the Asstt. Labour Commissioner (C), Ranchi by his Memo No. BSRM No. 84/87 dated 20-7-87. The management has contended that neither any union nor representative mass of workmen has sponsored this industrial dispute and that Bokaro Steel Rashtriya Mazdoor Sangh, Bhawanathpur is not also called Palamou Chuna Pathar Khan Mazdoor Sangh. The written statement of the concerned workman has been signed by Shri Sambhu Singh as Branch Secretary of Bokaro Steel Rashtriya Mazdoor Sangh, Branch Chuna Pathar Khan, Bhawanathpur. This shows that in the written statement even the name of the union has not been correctly written. The concerned workman has not examined himself with respect of the fact that he was/is a member of the union. Sri Sambhu Singh has not come forward to vouch for the fact, although his name appeared in the list of witnesses produced by the sponsoring union, that he is the Branch Secretary of the union and that he was authorised by the concerned workman to raise the dispute on his behalf as member of the union. The concerned workman has stated in cross-examination that Sambhu Singh submitted the written statement for sponsoring union on his behalf, but in the

next breath he turned a volte face and stated that he does not know if Sri Singh has submitted written statement on his behalf and he does not know what has been written in the written statement. This being so, I come to the conclusion that the present dispute was not raised by a competent authorised person before the Asstt. Labour Commissioner (C), Ranchi. In this view of the matter also the present reference must founder on the ground.

12. It is the firm case of the sponsoring union that the concerned workman was appointed in the service of Hindustan Steel Works Construction Limited as a Driver on 29-10-73. This statement of fact has not been specifically denied by the management. Anyway, from the evidence on record it also appears that the concerned workman joined the service of the management as Driver on 29-10-73 (Ext. M-7).

The sponsoring union has asserted that the date of birth of the concerned workman is 10-2-46 and complained that he was asked to cease work by the management at the age of 41 years whereas he should have been superannuated at the age of 60 years. There is no vestige of evidence on record to indicate that the date of birth of the concerned workman is 10-2-1946. The age of superannuation has not been also correctly spell out in the written statement of the sponsoring union. MW-1 Nand Kishore Prasad is now holding the post of Asstt. Manager (Personnel) in Bhawanathpur office of the management. He has stated that the age of superannuation in the company is completion of 58 years of age. The concerned workman has not stated anything in his testimony to indicate the superannuation age. Hence, upon the evidence on record I am constrained to hold that the age of superannuation of workmen working in Hindustan Steel Works Construction Limited, a construction company, in completion of 58 years of age. It remains to be seen now as to what was the date of birth of the concerned workman. Proposal of sanction of benefit under Voluntary Retirement Scheme (Ext. M-7) indicates that the date of birth of the concerned workman is 2nd August, 1934. The concerned workman has stated in his testimony that he does not remember if he disclosed his date of birth as 2-8-1934 at the time of joining service. That being so, it appears that he has not denied his date of birth as 2-8-1934 at the time of joining service. Not a whit of document has been produced by the sponsoring union or the concerned workman in support of the fact that the date of birth of the concerned workman was 10-2-1946 as pleaded in the written statement. In the context of evidence on record, I come to the conclusion that the date of birth of the concerned workman as recorded in the records of the management is 2-8-1934.

13. According to the management the concerned workman on his own proposed to retire from service with effect from 30-6-87. So, the concerned workman was aged 52 years, 10 months and 28 days when he, according to the management, proposed to retire from service under Voluntary Retirement Scheme. In the context of this fact it has to be considered now as to whether the concerned workman really submitted application for retirement from service with effect from 30-6-1987 under Voluntary Retirement Scheme.

14. The management has produced the application for voluntary retirement under Voluntary Retirement Scheme purported to have been submitted by the concerned workman. This application has been marked Ext. M-3. The concerned workman has disputed his signature on the application. As a matter of fact he has disputed his signature as appearing in different documents, such as, (i) Articles of agreement (Ext. M-15), (ii) application for gratuity (Ext. M-9), (iii) leave card (marked X for identification), L.L.T.C. application (marked X-1 for identification), (iv) application for subscribing to provident fund (marked X-2 for identification), (v) joining report after availing of commuted leave (marked X-3 for identification), (vi) applications for encashment of leave (marked X-4 and X-5 for identification), (vii) his signature on L.T.C. sanction and advance (marked X-6 for identification) and (viii) application for encashment of leave (marked X-7 for identification) at all. His all out efforts to deny his signature on all these documents is suggestive of the fact that he has not the basic elemental honesty and truthfulness. Although it has been admitted in the written statement of the concerned union that the concerned workman was required to execute an agreement on 1-5-74, he has denied

his signature even on this document (Ext. M-15). In the written statement he has complained that he has not signed any document denoting his consent for compulsory retirement or even voluntary retirement. But in the rejoinder the position has been shifted by stating that the management took his signature on some papers and utilised them for the purpose of voluntary retirement. This means that his signatures are there, but the documents have been brought into being by the contrivance of the management. At the time of hearing, the concerned workman has denied his signature on different documents by distressing refrain. He seems to have developed bats in his belfry in his zeal to deny his signature on different documents. I have seen his admitted signature on the deposition-sheet and compared his signatures as appearing in different documents with his admitted signature and is of the opinion that the signature on different documents are those of the concerned workman. The documents relating to voluntary retirement (Ext. M-1 and M-1/1) indicate that the scheme offers various benefits to workman opting for the same, such as, (i) exgratia payment of an amount equivalent of one month's wages and (ii) special exgratia payment of one month's wages etc. It also bears out that some other workmen also opted for the scheme and have since voluntarily retired from service (Exts. M-4 to M-4/3, M-5 and M-6).

15. It appears that the management sent the dues of the concerned workman on different heads by registered post letter to his local address i.e. Quarter of the company at Bhawanathpur Township. All these letters could not be delivered to the concerned workman as he refused to accept the same (Exts. M-13 and M-14). The concerned workman has stated that he left the quarter immediately after he was stopped from service with effect from 30-6-87. He has stated in his testimony that he did not make over the possession of the quarter of the company which he was duty bound to do so. This means that he left the quarter on the sly without leaving any forwarding address. In the circumstance, I am constrained to hold that the envelope containing cheque his dues on different account were tendered to him.

16. The evidence on record discloses that he was not stopped from duty, but that he voluntarily retired from service with effect from 30-6-1987. Hence, the present reference on the assumption that he was stopped from duty does not bear out the real position. However, in any view of the matter the action of the management can not be held to be unjustified, and so, the concerned workman has got no relief in the present reference.

17. Accordingly, the following award is rendered—the action of the management of Hindustan Steel Works Construction Limited, Bhawanathpur, in retiring the concerned workman, Bhagwan Das, under Voluntary Retirement Scheme with effect from 1-7-1987 is justified.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-26012/18/87-D.II(B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1990

का. आ. 1116:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार वेस्टन रेलवे ग्रहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, ग्रहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th April, 1990

S.O. 1116.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of

Western Railway, Ahmedabad and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

BEFORE SHRI V. H. THAKORE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD.

Ref. (ITC) No. 52 of 1989.

ADJUDICATION :

BETWEEN :

The Executive Engineer (C) (Western Railway) Ahmedabad, ... First party

AND

The workmen employed under him.

.. Second party

In the matter of reversion of the workmen Shri Vikram Punjabhai from the post of driver to gangman.

APPEARANCES :—None

STATE :—Gujarat

AWARD

Ahmedabad: 13th March, 1990

An industrial dispute between the Executive Engineer (C) (Western Railway), Ahmedabad (hereinafter referred to as the 'Railway Administration') and the workmen employed under it was referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad under section 10(1) of the I.D. Act, 1947 by the Ministry of Labour Govt. of India by its Order No. L-41012/76/88-D II(B) dated 24th July, 1989, and it was allotted to the Industrial Tribunal of Shri A. N. Ram and it has been subsequently transferred to this Tribunal. The dispute pertains to the reversion of the workman Shri Vikram Punjabhai from post of driver to gangman by the Western Railway, Ahmedabad as is mentioned in the schedule attached to the order of reference.

The exact terms of reference are as under :

"Whether the action of the management of Western Railway, Ahmedabad in reverting Shri Vikram Punjabhai from the post of driver to gangman is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?"

2. Now as per the above mentioned order dated 24th July, 1989 it was directed that the party raising the dispute shall file a statement of claim completed with relevant documents, list of reliance and witnesses with the Tribunal within fifteen days of the receipt of this order of reference and also forward a copy of such statement to each one of the opposite parties involved in this dispute under Rule 10 B of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957.

3. After the receipt of the reference in this Tribunal parties were issued usual notices on 11-8-1989 directing them to remain present before this Tribunal either personally or through their representatives on 23-8-1989 and they were also directed to produce their witnesses and documents.

However, none of the parties remained present and so it was adjourned to 28-9-1989, but on that day it was adjourned to 16-11-1989. Even on that day none of the parties remained present and it was adjourned to 14-12-1989. On that day also none of the parties remained present and so fresh notices were issued to the parties i.e. The Executive Engineer (C) Western Railway, Kalapur Railway Station, Ahmedabad-380001, and General Secretary, Association of Railway and Post Employces, 37, Pankaj Society, Nr. Zalak Complex, Bhatha Paldi, Ahmedabad-380007 on 21-12-1989 and thereby they were directed to remain present before this Tribunal on 1-2-1990. The said notice was personally served on the first party by bailiff on 22-12-1989 while it was sent to the second party by registered post A.D. and that was duly received on 5-1-1990 and that acknowledgement is also received by the office of this Tribunal. However, none of the parties remained present before this Tribunal even on 1-2-1990 and so it was adjourned to 8-3-1990, but on that day also none remained present. Thus the second party has failed to appear before the Tribunal and to justify the demand despite notices having been issued to it. It has also not filed any statement of claim, even though a period of six months has elapsed since the reference was made to this Tribunal. There is no material on the record to enable it to adjudicate the matter. In the circumstances the Tribunal is constrained to reject the demand. The reference stands disposed of accordingly. No order as to cost.

Ahmedabad, 16th March, 1990

V. H. THAKORE, Presiding Officer
[No. L-41012/76/88-D II(B)]

का. आ. 1117 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार फ्रेश वाटर फिश फार्म के प्रवर्धन के सम्बन्ध में निर्यातकों और उनके कर्मचारियों के बीच अन्तर्धर्ष में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1117.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Fresh-water Fish Farm, Balabhadra and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD.

PRESENT :

Sri D. Ramalinga Swamy, B. Com., B.L.,
Industrial Tribunal.

Dated : 15th March, 1990.

Industrial Dispute No. 64 of 1988.

BETWEEN :

The Workman of Fresh Water Fish Farm,
Balabhadrapuram, East Godavari District.
(A.P.)

AND

The Management of Fresh Water Fish Farm,
Balabhadrapuram, East Godavari District.
(A.P.)

APPEARANCES :—

Sri B. P. Vijaya Kumar, Advocate for the
Workmen. Sri S. Venkat Reddy, Sri C.V.
Survayanarayana and Sri S. Subramanayam
Reddy, Advocates for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour
by its Order No. L-42012|16|87-D.II(B) dated
7-6-1988 referred the following dispute under Sec-
tion 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes
Act, 1947, between the employers in relation
to the Management of Fresh Water Fish Farm,
Balabhadrapuram and their workmen to this Tribu-
nal for adjudication :

“Whether the action of the management in
terminating the services of Sri P.V.K.
Reddy is justified? If not, to what relief
the workman is entitled to and from
what date?”

This reference is registered as Industrial Dispute
No. 64 of 1988 and notices were issued to the
parties.

2. The Workman filed his claim statement on
14-10-1988 and the case was posted for counter of
the Management from time to time till 21-12-1990.
On 21-2-1990, the Lawyer of the Management
represented that the worker was reinstated. On
15-3-1990 a joint memo was filed by the Manage-
ment and the workman stating, that as the work-
man was appointed afresh in a regular post, an
award may be passed closing the industrial dispute.

3. In view of the above, an Award is passed in
terms of the joint memo filed by both the parties.
The joint memo is enclosed to the Award.

Diciated to the Stenographer transcribed by him,
corrected by me and given under my hand and the
seal of this Tribunal, this the 15th day of March,
1990.

D. Ramalinga Swamy Industrial Tribunal

[No. L-42012|16|87-D.(B)(P)]

Appendix of Evidence.

NIL

का. आ. 1118—औद्योगिक विवाद अधिनियम
1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत
केन्द्रीय सरकार कैट बोर्ड कानपुर के प्रवन्धतंत्र के सम्बद्ध
नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्बन्ध में निर्दिष्ट
औद्योगिक विवाद में में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय
सरकार की 6-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1118.—In pursuance of Section 17 of the In-
dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award of the Cen-
tral Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown
in the Annexure, in the industrial dispute between
the employers in relation to the management of
Canti Board, Kanpur and their workmen, which was
received by the Central Government on 6-4-90.

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFI-
CER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-cum-LABOUR COURT, PANDU
NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 74 of 1987

In the matter of dispute between :

Shri Basant Kumar Agarwal, S/o Shri B. L.
Agarwal, C/o U. P. Mechanical Technical
and General Workers Union 106|162
Gandhi Nagar, Kanpur.

AND

Cantonment Executive Officer, Cantonment
Board.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour,
vide its notification no. L-13012|3|86-D.II(B) dt.,
29th June, 1987, has referred the following dispute
for adjudication to this Tribunal :

“Whether the action of Executive Officer Can-
tonment Board, Kanpur in terminating the
services of Shri Basant Kumar Agarwal
Junior Clerk w.e.f. 17-10-84 is fair legal
and justified ? If not, to what relief con-
cerned workman is entitled to ?”

2. The workman's case is that the Executive Offi-
cer Cantonment Board, engaged him as Junior Clerk
on daily wages for a short period in 1983. However,
w.e.f. 14-2-83, he was appointed temporarily as junior
clerk for a period of 3 months. Since the job was
of permanent nature, on representation he was an-
pointed on probation for a period of 2 years w.e.f.
14-2-83. The workman alleges that due to his trade
union activities and rivalry between Trade Unions,
his services were terminated by the Executive Officer
in violation of the mandatory provisions of sec. 25F
I. D. Act. He has, therefore, prayed that his order
of termination being void abinitio, the Executive Offi-
cer, Cantonment Board, Kanpur, be directed to rein-
state him with full back wages and continuity of
service.

3. The management plead that suspension of one
Shri R. K. Shukla a junior clerk resulted in disloca-
tion of work and to clear the pending work the
workman was appointed as junior clerk for 26 days
in August 1982 and for 24 days in Sept. 1982 on
daily wages. Later on 14-2-83, the workman was
appointed temporarily as Junior Clerk. However,
keeping in view the welfare of the workman and also
the fact that there was no likelihood of reinstate-
ment of Shri R. K. Shukla, on 5-5-83, the workman
was placed on probation for two years from the date
of appointment. The management deny that the
workman had ever been a Trade Union worker. The
management further plead that Shri R. K. Shukla

vide resolution no. 9 dated 28-6-84 of the Cantonment Board, Kanpur was reinstated. Since the workman had been appointed in place of Shri R. K. Shukla, his services were terminated by giving him one month's notice dated 17-9-84. By another letter of the same day the workman was asked to collect his retrenchment compensation amounting to Rs. 644.50 paise from the office, but the workman did not withdraw the same from the office. Thus the provisions of section 25F I. D. Act, were fully complied with by the management.

4. It is then pleaded by the management that the workman filed Original Suit no. 1669 of 1984 against the Cantonment Board, Kanpur, for permanent injunction restraining the Cantonment Board Kanpur, from enforcing its letter of termination dt. 17-9-84, till the expiry of the probation period. However, later on finding no force in the suit, he withdrew it by means of an application dt. 20-9-85. In the circumstances, the present case is barred by the principles of Resiudicata. The management also plead that the Cantonment Board having no authority to make the appointment in the absence of a sanctioned post. The workman cannot be given any appointment. It is also pleaded by the management that the workman was governed by Cantonment Fund Servants Rules, 1937 and not by the provisions of I. D. Act, 1947. Hence, the workman has no claim at all.

5. In his rejoinder, the workman alleges that he was not appointed in the vacancy of Shri R. K. Shukla Junior Clerk. In fact there existed two vacancies at that time and he and one Suresh Lal were appointed as probationers. Shri R. K. Shukla, was appointed on 16-5-81 whereas he was appointed on 14-2-83. He also alleges that it is wrong to say that no vacancy of Junior Clerk exists in the Cantonment Board, Kanpur. At present there exists 4 or 5 vacancies as a result of retrenchment of 3 permanent clerks, namely, S/Shri J. P. Gupta, Ayub Khan and Mahboob Husain.

6. In support of his case, the workman has filed his own affidavit and a number of documents. On the other hand the management in support of their case have filed the affidavits of S/Shri Satya Narain and B. M. Saxena, posted as peon and Office Suptd., respectively and a number of documents.

7. Ext. M. 1 is the copy of certificate dt. 17-10 (year not given) given by the Executive Officer, Cantonment Board, Kanpur, certifying that the workman during the period July 1982, to September, 1982, had worked for 64 days as Junior Clerk in the Cantonment Board, Kanpur.

8. Ext. M. 2 is the copy of letter of temporary appointment given to the workman, dated 14-2-83, issued by the Executive Officer Cantonment Board, Kanpur. It shows that the workman was appointed as Junior Clerk temporarily for a period of 3 months in the scale of Rs. 200-320 with usual admissible allowances.

9. Ext. M. 3 is the copy of office order dt 5-5-83, issued by Executive Officer, Cantonment Board, Kanpur. By means of this office order the said Executive Officer gave the workman, who had been earlier

appointed on temporary basis regular appointment on probation for a period of 2 years

10. Ext. W-4, is the copy of notice dt. 17-9-84 given by Executive Officer Cantt. Board Kanpur to the workman. By means of this notice the said Executive Officer informed the workman that his services would stand terminated on the expiry of the period of 30 days from its receipt. It was mentioned in the notice that consequent upon the reinstatement of Shri R. K. Shukla and in the absence of sanction from the higher authorities for creation of a post of junior clerk, his further retention in the service of the Cantonment Board was irregular.

11. From the above documents it thus stands proved that during the period of 12 months preceding the date of termination the workman had worked continuously for a year within the meaning of sec. 25B I. D. Act. In the case of the management of KSRIC Bangalore Versus M. Boraiah 1984 (48) FLR 89(SC), it was held that even in the case of probationers, the provisions of sec. 25F require to be complied with.

12. In the instant case we have seen that one month's notice was given by the Executive Officer Cantonment Board Kanpur to the workman while terminating the services of the workman. The receipt of the notice is not denied by the workman. The only dispute between the parties is whether or not retrenchment compensation was paid to the workman. The management have led evidence to show that by means of letter dt. 17-9-84, the delivery of which the workman refused to take, the workman was called upon to collect retrenchment compensation from the office of the Cantonment Board, Kanpur. The evidence consists of the statements of MW 1 Shri Satya Narain who is posted as Peon and MW 2 Shri B. M. Saxena, who is posted as Office Suptd. in the Cantonment Board, Kanpur.

13. The evidence given by Shri B. M. Saxena, Office Suptd. is not material as in his cross examination he has admitted that on 17-9-84, he was posted in the Cantonment Board, Lucknow, Shri Satya Narain has, however, deposed that on 17-9-84, he took letter no. 931/A dated 17-9-84, for delivery to the workman that very day, but the workman after reading it out returned it to him saying that he would not take it. In his cross examination he has deposed that the letter was entered in the Peon Book. He admitted that he had not brought the peon book. Even thereafter, no attempt was made by the management to produce the peon book. On the other hand, the workman has denied on oath that no such letter was tendered to him for delivery.

14. To me the evidence given by the workman appears to be for more reliable than the evidence adduced by the management. The copy of the aforesaid letter was filed by the management with the list of documents dt. 19-4-89 by means of which the workman was informed to collect a sum of Rs. 644.50 paise from the cashier of the office as retrenchment compensation admissible under the I. D. Act. Thus from the evidence which the management have ad-

duced it appears that on 17-9-84, the date on which the notice of termination was given to the workman, the retrenchment compensation payable to the workman had been calculated. If it were so, I fail to understand what prevented the management from making mention of this fact in the letter of termination asking the workman to collect the said sum as retrenchment compensation from the cashier of the Cantonment Board. There also does not appear to be good grounds for refusal to take delivery of this letter by the workman. If he could accept the letter of termination of the same date he could have well accepted this letter as well. Had there been any substance in the plea set up by the management, in the event of refusal, the management could have sent this letter to the workman by registered post with a covering letter explaining the circumstances which had compelled the management to send it by registered post. In view of the notice of termination dt. 17-9-84, retrenchment compensation could have been paid to the workman by 17-10-84. Thus there was sufficient time with the management to serve this letter on the workman by registered post.

15. Thus it stands proved that the provisions of Sec. 25F I. D. Act were not complied with by the management while terminating the services of the workman.

16. Let us examine the case of the workman from another angle. From the order of appointment dt. 5-5-83, copy Ext. W-3, it is clear that the workman was given a regular appointment of Junior Clerk on probation for a period of 2 years. His services therefore could be terminated on 2 counts, one on the ground of unsatisfactory work and the second on the ground of the abolition of the post on which he was appointed. None of these grounds exists in the present case. In para 8 of the claim statement it has been stated by the workman that through out he had a clean and unblemished record of service. In reply to it the management have pleaded in para 8 of the written statement that there was no adverse remark against the workman. The fact that the workman had worked for 64 days in 1982; and the fact that he had been given temporary appointment as Junior Clerk for 3 months w.e.f. 14-2-83; and the fact that he was given regular appointment on probation for a period of 2 years go to show that unless work has been satisfactory he would not have been given regular appointment as Junior Clerk by the management. There is no evidence that the post on which he was appointed was abolished. The plea which is now being taken by the management is that he was appointed in the vacancy of Shri R. K. Shukla who had been placed under suspension on 16-5-81. In all the documents pertaining to workman's appointment as Junior Clerk it is not so stated. Moreover such a situation would not have warranted the regular appointment of the workman. If he was given a regular appointment, it was given because of the fact that there had existed a vacancy of junior clerk. It does not lie in the mouth of the management to say now that there was no clear sanctioned post of junior clerk on which the workman could have been appointed.

17. Thus termination of the services of the workman cannot be upheld under any circumstance. In view of what has been found above the order of termination of the workman is held as illegal. It has been argued on behalf of the management that reinstatement of the workman should not be ordered. If at all any relief is to be granted to the workman it should be the wages for the remaining period of probation and not beyond. In support of his contention the management relied upon the ruling in the case of Brij Mohan Agarwal Vs. The Presiding Officer and others 1989 All India CJ 174. I have gone through this ruling and find that it is distinguishable on facts. In the said case, the petitioner was appointed on probation for a period of 3 months, and his services were terminated abruptly after he had worked for 17 days. It is clear from para 9 of the judgment that the petitioner had not continuously worked for one year within the meaning of Sec. 25B I. D. Act. It was in those circumstances it was ordered that the petitioner should be paid salary for the remaining period of probation. In the present case, therefore, I find that the workman is entitled for his reinstatement with full back wages and continuity of service.

18. Hence, it is held that the action of the Executive Officer, Cantonment Board, Kanpur, in terminating the services of the workman w.e.f. 17-10-84, is neither legal nor justified. Consequently, the workman is held entitled to his reinstatement as Junior Clerk with continuity of service and with full back wages.

19. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer
[No. L-13012/3/86-D II(B)]

का. आ. 1119—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार टैलीकाम डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, रोहतक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार कि 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1119.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Distt. Engineer, Rohtak and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-cum-LABOUR COURT,

CHANDIGARH

Case No. I. D. 75/90

Employers in relation to the management of Telecommunication, District Engineer, Rohtak.

AND

Their workman Suraj Pal Singh.

For the workman : None.

For the Management : Shri Arun Walia.

INDUSTRY : Telecommunication STATE : Haryana

AWARD

Central Government vide gazettee notification No. L-40012/89/88-D. II (B) dated 2nd May 1989 issued u/s 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri Suraj Pal Singh.

"Whether the action of the Telecommunication District Engineer, Rohtak in terminating the services of Sh. Suraj Pal Singh S/o Sh. Babu Singh, casual worker w.e.f. 1-4-88 is justified, fair and legal ? If not, what relief the worker concerned is entitled to ?"

2. On receipt of the reference the notice was issued to the workman but he did not respond and did not put appearance. Repeated registered letters were issued to him and the same were received with the report that the workman is not available. Thus the reference is returned for want of prosecution.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

[No. L-40012/89/88-D.II(B)(P)]

Chandigarh

16-3-1990.

का. आ. 1120—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे के प्रबन्धन के सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार कि 5-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1120.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway and their workmen, which was received by the Central Government on 5-4-90.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-cum-LABOUR COURT NO. 1 AT BOMBAY

(Presiding Officer : Justice S. N. Khatri)

Reference No. CGIT-2 of 1990

PARTIES :

Paschim Railway Karamchari Parishad.

V/s.

Their Workmen

Appearances

For the Management : Shri P. R. Rai Advocate

For the Workmen : No appearance.

Industry Railway State : Gujarat

Bombay, the 30th day of March, 1990

AWARD

The Central Government has referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication under section 10 of the Industrial Dispute Act.

"Whether the demand of Paschim Railway Karamchari Parishad for absorbing 105 casual labourers (list enclosed) on permanent basis in Baroda Division on the basis of their seniority and length of service is justified ? If yes, to what relief the workmen concerned are entitled to ?"

2. The Divisional Secretary, Paschim Railway Karamchari Parishad, who is representing the workmen, was duly served with notice to file their statement of claim on 24th Jan. 90. Thereafter at his request the matter was adjourned to 14th Feb. 90. The workmen did not appear on that day. Again the reference was adjourned for 29th March 90, with a notice to the workmen that the reference would be decided in their absence, if they failed to turn up on that day. This notice is duly served on the Union on 3rd March, that is more than three weeks ago. They have not cared to appear or file their statement of claim. It appears they are not interested in pursuing the matter. The management have also not filed their written statement, in absence of the workmen's statement of claim.

3. In absence of any materials, the Tribunal is not in a position to hold that the demand of the Paschim Railway Karamchari Parishad for absorbing the 105 casual labourers on permanent basis, is justified. Eventually they are not entitled to any relief. No orders as to costs Award accordingly.

S. N. KHATRI, Presiding Officer

[No. L-41011/46/88-D.II(B)(P)]

का. आ. 1121 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे लखनऊ के प्रबन्धन के सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1121.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 79 of 1989

In the matter of dispute between :

The Divisional Secretary, Uttar Railway Karamchari Union 39-II-J Multistoreyed Railway Colony, Charbagh Lucknow.

AND

The Divisional Railway Manager, Northern Railway, Hazratganj, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-41011/4/87-D. II-(B) dt. 20th March 1989 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Kya Prabhagiya Railway Prabandh Uttar Railway Lucknow Dwara S/Shri Surat Prasad, Ramakant Shukla and Badra ko Porters ke Roop Me Niyamit Na Kiya Jana Nyayochit Hai ? Yadi Nahi to Yeh Karamkar Kis Anutosh Ke Haqdar Hai ?

2. The industrial dispute on behalf of all the 3 workmen has been raised by the Zonal Working President Uttar Railway Karamchari Union (hereinafter referred to as Union), Lucknow. In the claim statement which is signed by Shri B. D. Tewari as Zonal Working President, of the Union, it is alleged that S/Shri Surat Prasad Ramakant Shukla and Badri were engaged as substitute porters at railway station Lucknow on 20-5-61, 19-6-76 and 20-6-64 respectively. The regularisation of their services was due in 1979. However, the names of S/Shri Surat Prasad and Badri were not included in the list of names of persons which was screened on the ground that they were overage. In the next screening test which was held in 1985-86, S/Shri Surat Prasad and Ramakant Shukla were declared successful and they were regularised with immediate effect. However, Badri was not called for the test. It has therefore been prayed that the services of all the three workmen be regularised from the dates noted against their names in annexure 2 which is the copy of letter dt. 7-10-86 from the Divisional Office to ALC(C) Lucknow. In the circumstances later dates of original appointment and dates from which they have been working in the scale of Rs. 196-232 (RS) are given. The dates from which they have been working in the said scale are given as 1-3-86 and 1-7-86 in respect of S/Shri Surat Prasad, Ramakant Shukla and Badri respectively. I may state here that in the claim statement reference has been made to another workman by the name of Shri Manohar Lal but since he is not named in the reference order I have not referred to him while referring to the facts alleged in the claim statement.

3. The management plead that S/Shri Surat Prasad Ramakant Shukla and Badri temporary status on 13-2-79, 16-3-80 and 29-1-79 respectively. The management deny that any Screening Test was ever held in 1970. A number of workmen were called by the

Railway Administration for Screening Test on the basis of which result was declared on 17-12-87. S/Shri Surat Prasad and Ramakant Shukla were declared successful. Shri Badri did not appear before the Screening Test. The management further plead that the claim statement is not legally admissible because it is not signed by the workmen. The alleged Zonal Working President has no legal right to raise the industrial dispute on behalf of the workmen as the alleged Union is not recognised Union. Lastly, the management plead that there is no valid industrial dispute under sec. 2k I.D. Act.

4. In support of its case, the Union has filed the affidavit of Shri Surat Prasad and a few documents. On the other hand, the management have simply relied on documents/evidence in support of their case.

5. In para 2 of his statement in cross examination Shri Surat Prasad has deposed that his services and the services of Shri Ramakant Shukla on the post of porter have been regularised w.e.f. 17-12-87. The date should be 7-12-87 as it appears from Ext. M-1, which is the copy of provisional panel for transportation and commercial class IV Staff of Lucknow Division. It is dated 7-12-87. Shri Surat Prasad has further deposed that so far as he and Shri Ramakant Shukla are concerned there is absolutely no dispute between them and the management except on the question of grant of increment to them. The question of increments cannot be considered in this case as it is beyond the scope of the reference. Therefore, so far as these two workmen are concerned, with the regularisation of their services on the post of porter w.e.f. 7-12-87, the reference has become infructuous.

7. Now let us examine the case of Shri Badri. The case set up by the Union is that he was not called for Screening Test which was held in 1970 and 1985-86. On the other hand, the case of the management is that no screening test was held in 1970. In the next test according to the management, although all the 3 workmen were called, Shri Badri did not appear prior before the Screening Committee.

8. There cannot be any dispute about the fact that so long as Shri Badri does not pass the screening test, he cannot be regularised himself. So far Badri has not appeared before the Screening Committee. It may be because of his own fault and it may also be because of the fault on the part of the Railway Administration.

9. From the statement of Shri Surat Prasad in cross examination it appears that a list of 60 persons in which the name of Shri Badri also appeared was sent to the DRM Office for approval by the Station Superintendent, Lucknow. According to him the entire list was approved and the said list was pasted on the notice board at the office of Station Suptd. Northern Railway, Lucknow. In the list 4 dates of interview were also mentioned. He admits that Shri Badri had at that time working at Railway Station Lucknow as Box Porter. According to him Shri Badri who is IVth or Vth class passenger also read the notice. After making these statements the witness took a solemn oath and said that the list which was received after approval

val from the DRM Office did not have the name of Shri Badri. The Station Suptd. wrote about it to DRM Office but nothing has been heard upto this date.

10. Badri seems to be a substitute porter at Railway Station Lucknow since long. In the claim statement the Union alleged that he was engaged at Lucknow Rly. Station on 20-6-64. The Union has tried to corroborate it from the letter copy annexure II to the claim statement which has been proved by the Union witness Shri Surat Prasad. It will be therefore just and fair if Badri is given an another chance to appear before the Screening Committee when screening test is held next time irrespective of the fact whether he is over age or not.

11. Accordingly it is held that so far as Surat Prasad and Ramakant Shukla are concerned the present reference has become infructuous. However, as regard Shri Badri the management is directed to give him another chance to appear before the Screening Committee whenever Screening Test is held next time.

12. The reference is answered accordingly.

ARIAN DEV, Presiding Officer
[No. L-41011/87-D.II(B)(Pt.)]

का. आ. 1122—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सीनियर सुपरिन्टेण्डेंट टेलीग्राफ टैफिक कानपुर के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1122.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sr. Supdt. Telegraph Traffic, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR.

Industrial Dispute No. 260 of 1989
In the matter of dispute between

Shri Anil Kumar,
S/o Shri Goverdhan Lal,

Applicant.

105/473, Sri Nagar,
Kanpur.

AND

Senior Suptd. Telegraph Traffic,
Bihari Niwas,

Opp. Party.

Dwarikadhish Road,
Kanpur.
1023 GI/90—11

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-40012/5/89-D.II(B) dt. 23-10-89, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;

“क्या सीनियर सुपरिन्टेण्डेंट टेलीग्राफ कानपुर के टैफिक अधीन कार्य करने वाले श्री अनिल कुमार भूतपूर्व कैंजुअल खेबर की दिनांक 13-1-85 से पुनः नौकरी पर पूरे पिछले वेतन के साथ रखे जाने की मांग न्याय संगत है? यदि नहीं तो संबंधित कार्यकार किस अनुतोष का हकदार है ?

2. In this case the Industrial Dispute has been raised by the workman concerned the workman remained absent on 20-12-89, 24-11-90 and on 27/2/90, but the management attended the case on all the dates. No claim statement has been filed nor there is any application from the workman.

3. As such it appears that he is not interested in contesting the case and a no claim award is given against him in the circumstances stated above.

ARJAN DEV, Presiding Officer
[No. L-40012/5/89-D.II(B)]

का.आ. 1123—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार टेलीकमानीकेशन रोहताक के प्रबन्धन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1123.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecommunication Rohtak and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 72/89

Employers in relation to the management of
Telecommunication, District Engineer,
Rohtak.

AND

Their workman-Ved Parkash.

For the workman.—None

For the management.—Shri Arun Walla

INDUSTRY : Telecommunication. STATE : Haryana

AWARD

Central Govt. vide Gazettee notification No. L-40012/86/88-D.2(B) dated 2nd May 1989 issued

U/S 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri Ved Parkash :

"Whether the action of the Telecommunication District Engineer, Rohtak in terminating the services of Shri Ved Parkash son of Shri Hari Ram Saini, casual worker w.e.f. 1-4-1988 is justified, fair and legal? If not to what relief the worker concerned is entitled to ?"

2. On receipt of the reference the notice was issued to the workman but he did not respond and did not put appearance. Repeated registered letters were issued to him and the same were received with the report that the workman is not available. Thus the reference is returned for want of prosecution.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer
[No. L-40012/86/88-D.II(B)]

का.ग्रा. 1124—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार टेलीकम्युनिकेशन रोहतक के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1124. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecommunication, Rohtak and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGORH.

Case No. I.D. 82/89

Employers in relation to the management of Telecommunication, District Engineer, Rohtak.

AND

Their workman-Ajanti Singh

For the workman.—None

For the management.—Shri Arun Walia

INDUSTRY.—Telecommunication State-Haryana

AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-40012/61/88-D.II(B) dated 2nd May 1989 issued U/S 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri Ajanti Singh :

"Whether the action of the Telecommunication District Engineer, Rohtak in terminating the services of Sh. Ajanti Singh Slo Sh. Raj Pal casual worker w.e.f. 1-4-88 is justified, fair and legal? If not, to what

relief the worker concerned is entitled to?"

2. On receipt of the reference the notice was issued to the workman but he did not respond and did not put appearance. Repeated registered letters were issued to him and the same were received with the report that the workman is not available. Thus the reference is returned for want of prosecution.

Chandigarh.

16-3-1990.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer
[No. L-40012/61/88-D.II(B)(Pt)]

का.ग्रा. 1125—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दूर-दर्शन केन्द्र रांची के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1125.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No.1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Doordarshan Kendra Ranchi and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90

Before the Central Government Industrial Tribunal No. I, Dhanbad.

In the matter of a reference under-section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.
Reference No. 36 of 1989.

PARTIES :

7employers in relation to the management of Doordarshan Kendra, Ranchi.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S.K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri Md. Qameruddin along with Kr. Usha Tirkey, Administrative Officer.

For the Workmen.—Shri D. Prasad, Working President, Doordarshan Kendra Karma-chari Sangh.

STATE.—Bihra.

INDUSTRY.—Doordarshan.

Dated, the 21st March, 1990

AWARD

By Order No. L-42012/151/87-D-II(B), dated, the 20th March, 1989, the Central Government in

the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1946, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Doordarshan Kendra, Ranchi, in terminating the service of S|Shri P. K. Jha, Satish Kumar, Nand Kumar and Sarjug Das is justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2. The case of the management of Doordarshan Kendra, Ranchi, as appearing in the written statement submitted by the Director of Doordarshan Kendra, Ranchi, details apart is as follows :

The concerned workmen, S|Shri Satish Kumar, Prabodh Kr. Jha, Nand Kumar and Sarjug Das alias Sarju Das were engaged as casual labourers on daily wages for assisting the O.B. Units as and when required during the years and number of days as shown against their names :

	1984	1985	1986	1987
1. Satish Kumar	—	80	234	—
		Days	Days	
2. Prabodh Kr. Jha	—	80	235	—
3. Nand Kumar	—	80	107	—
4. Sarjug Das alias Sarju	—	—	210	—

In the case of casual employees letters of appointment and letters of dismissal are not issued. They are simply called for interview before the Head of the Kendra and informed verbally before engagement or discontinuation of their services. Regularisation of casual workmen are considered for regularisation in Group D posts if otherwise eligible, if such casual workmen have put in 2 years of continuous service with 206 working days during each year of service. But in the case of Central Government offices which work for 6 days a week like Doordarshans, casual workers are eligible for regularisation after rendering 240 days of service during the period of two consecutive years. Since the inception of Ranchi Doordarshan Kendra the Ministry has been approached for sanction of Group-D posts, but that is still under consideration of the Government, and consequently, the work is managed by engaging casual workers from time to time. The jobs of such casual workers are seasonal in nature and hence the question of their regularisation does not arise. Doordarshan Kendra can not be treated as 'industry' and the question whether the Doordarshan Kendra is an 'industry' or not is still sub-judice before Hon'ble Supreme Court. It has been asserted that there is no justification for the grievance of the concerned workmen and the action of the management is justified.

3. The case of the concerned workmen as appearing from the written statement submitted by the sponsoring union, namely, Doordarshan Kendra Karmchari Sangh, Ranchi on their behalf, briefly stated, is as follows :

The concerned workmen are workmen within the definition of Industrial Disputes Act and they were

working as Lighting Assistants in Ranchi Doordarshan Kendra. They are bonafide and active members of the union. They have participated in their union activities for which the management became biased and their services were terminated with effect from 1-12-86, without assigning any valid reason and without complying with the provision of Section 25F of the Industrial Disputes Act. They have rendered service for over three years date of appointment and working days year-wise are as follows :

Names	Date of appointment	Yearwise working days actually they worked			
		1983	1984	1985	1986
P.K. Jha	1-11-83	48	268	289	290
Satish Kumar	22-10-84	—	59	289	290
Nand Kumar	25-10-84	—	57	290	281
Sarjug Das	1-1-85	—	—	268	219

All of them have worked in the capacity of skilled workers and the management of Doordarshan Kendra issued certificates to them but did not pay them refrenchment compensation. They were not even issued either notice or pay in lieu of notice in terms of the provisions of Industrial Disputes Act. It is alleged that the services of the concerned workman have been terminated in illegal manner and in violation of the rules and regulations and provisions of Industrial Disputes Act. In the circumstances, the sponsoring union has prayed that the Tribunal be pleased to give an award in favour of the workmen holding that they are entitled to be reinstated in services with retrospective effect and all benefits.

4. In rejoinder to the written statement of the management the union has asserted that the statement of facts of the management relating to appointment and dismissal of casual workmen are not correct. It has been asserted that Doordarshan Kendra is an 'industry' and so the present reference is maintainable.

5. The management has examined only one witness, namely, MW-1 Md. Qumeruddin, presently posted as Clerk Grade-I in Doordarshan Kendra, Ranchi, but has laid no documentary evidence in support of its action.

The sponsoring union, on the other hand, has examined all the concerned workmen and laid in evidence a mass of documents which have been marked Exts. W-1 to W-10.

6. Admittedly, the concerned workmen were engaged by the management of Ranchi Doordarshan Kendra. It has been asserted by the management that all of them were engaged as casual workmen. The sponsoring union has not specifically disputed the fact that the concerned workmen were engaged as casual workmen, but has asserted that all of them had worked in the capacity of skilled workers. None of the concerned workmen has vouched for the fact that they were not appointed as casual workers. On the other hand, identity cards issued to the concerned by the management (Exts. W-5, W-8, W-9 and W-10) are indicative of the fact that the concerned workmen were appointed as casual workers.

It appears that the skilled labour certificates were issued in favour of the concerned workmen P.K. Jha and Satish Kumar (Exts. W-1 to W-4, W-6 and W-7). It appears from these certificates that skilled labour certificates were issued by the management in favour of P.K. Jha and Satish Kumar when they were working as Lighting Assistants. The other two workmen, namely, Nand Kumar and Sarjug Das also have vouched for the fact in their testimony that they worked in Doordarshan Kendra, Ranchi, as Lighting Assistants. Nothing has been elicited in cross-examination to militate against the testimony of their as engagement as Lighting Assistants. This being so, I come to the conclusion that although all the concerned workmen were engaged to casual workers nevertheless they were engaged as skilled casual workmen.

7. Upon perusal of the written statement of the contending parties it appears that there remains variations as to the number of days the concerned workmen were employed by the management of Doordarshan Kendra, Ranchi. The management has not produced even a whit of evidence in support of its statement with regard to the number of attendance put in by each of the concerned workman in any particular year. On the other hand, the concerned workmen have examined themselves on this point. P. K. Jha figuring as WW-1 has stated that he joined Doordarshan Kendra, Ranchi on 1-11-83 as Store Assistant and that he worked in that capacity for one year and from 1-11-84 to 30-11-86 he worked as Lighting Assistant. Another concerned workman Satish Kumar figuring as WW-2 has stated that he joined Ranchi Doordarshan Kendra as Lighting Assistant on 22-10-84 and worked there till 30-11-86 continuously as Lighting Assistant. Another concerned workman, Nand Kumar, figuring as WW-3 has stated that he joined Doordarshan Kendra, Ranchi on 25-10-84 as Lighting Assistant and worked there continuously upto 1-12-86. Sarjug Das figuring as WW-4 has stated that he joined Doordarshan Kendra, Ranchi on 1-1-85 as Lighting Assistant and worked there continuously upto 30-9-86. The certificates produced by the sponsoring union Exts. W-1 to W-4 establish the fact that P. K. Jha was appointed in Ranchi Doordarshan Kendra from November, 1983 and worked in that Kendra till 30-5-86. Another set of certificates issued in favour of Satish Kumar establishes the fact that he was engaged in Doordarshan Kendra on 22-10-84 and worked there till 30-5-86 (Exts. W-6 and W-7). Thus, the evidence of the witness along with the documents on record establishes the position that P. K. Jha was appointed on 1-11-83, Satish Kumar on 22-10-84, Nand Kumar on 25-10-84 and Sarjug Das on 1-1-85. It appears from evidence that they worked in the Kendra continuously and P. K. Jha, Satish Kumar and Nand Kumar were stopped from duty with effect from 1-12-86 while Sarjug Das was stopped from duty with effect from 10-10-1986. The sponsoring union called for production of attendance register in respect of the concerned workman by the management and by order dated 20-9-89 the management was directed to produce the documents on the date of hearing. But the management

did not produce the Attendance Register nor has it submitted any explanation for non-production of this document. The management undertook to produce the daily wage register and vouchers in respect of the concerned workmen from which the attendance of the concerned workmen would be evident. But this register and vouchers were never produced. Even MW-1 Md. Quameruddin has stated that all the concerned workmen were working as Lighting Assistant in Doordarshan Kendra, Ranchi and that he had seen them working in Doordarshan Kendra as Lighting Assistant in 1985 and that he had also seen them working in the same capacity for sometime in 1986 also. Thus, from the evidence on record, I have no hesitation to conclude that the concerned workmen put in more than 240 days attendance in 1985 and 1986 and that they were stopped from duty after having put in more than 240 days attendance in 1986.

8. Admittedly, the management has not given any notice or wages in lieu of notice to the concerned workman. The management has not paid them even the retrenchment compensation. In the circumstances, the management has violated the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act and hence the order of dismissal of the concerned workman by the management without complying with the provisions of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act must be held to be illegal and invalid.

9. Even casual workmen are entitled to be reinstated in service because they are workmen within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act. In the case reported in 1989(11) LLJ. 86 (Andhra Pradesh) the Hon'ble High Court was pleased to reinstate a casual workman in service with back wages. In this view of the matter the concerned workmen are entitled to be reinstated in service with effect from the date of their dismissal from service.

10. Where termination of service is not justified, awarding of full back wages is the normal rule. The burden of showing that the normal rule should not be followed and that the employee should not be awarded full back wages is on the employer. The management of Doordarshan Kendra, Ranchi has not discharged its burden in any way. That being so, the concerned workmen are entitled to back wages with effect from the date of their termination of service.

11. A question has been raised as to whether Doordarshan Kendra is an 'industry' or not. It appears from the decision reported in 1988 (II) LLJ. 83 (Allahabad) that Hon'ble High Court on a Writ filed by Doordarshan Karmachari Congress for declaration of Doordarshan Kendra as an 'industry' under the Industrial Disputes Act, referred the Karmachari Sang for approaching the Central Government for reference of the dispute to the Industrial Court. It is not known whether the matter was pursued further by the Karmachari Congress or whether the Central Government or appropriate Government made a reference of the dispute to the Industrial Tribunal or not. Anyway in the present cases the appropriate Government was

presumably satisfied that Doordarshan Kendra is an 'industry' and was pleased to refer the dispute for adjudication by this Tribunal. The management not laid any contra evidence to prove that Doordarshan Kendra is not an 'industry'. This being so, I hold that the present reference is maintainable.

12. Accordingly, the following award is rendered—the action of the management of Doordarshan Kendra, Ranchi, in terminating the service of S/Shri P. K. Jha, Satish Kumar, Nand Kumar and Sarju Das is not justified. The management of Doordarshan Kendra is directed to reinstate the concerned workmen in service with effect from the date of termination of their service and pay them back wages, also with effect from the date of termination of their service.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

[No. L-42012/151/87-D.II(B)(Pt)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1990

का.आ. — 112 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वये में केन्द्रीय सरकार व मैमर्जी एस.सी. सी. लि. मण्डमारी विभाग के प्रबन्धन से संबंधित नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच अन्तर्गत में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार का 4-4-90 प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 15th April, 1990

S.O. 1126.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. S.C. Co. Ltd., Mandamarri Division and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri D. Ramalinga Sway, B.Com., B.L., Industrial Tribunal.

Dated : 13th March, 1990

Industrial Dispute No. 35 of 1982

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division, Adilabad District (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited Mandamarri Division, Adilabad District (A.P.).

APPEARANCES :

Sri J. Viswanatha Reddy, Chief Vice President, A.P. Collieries Mazdoor Sangh for the Workmen.

Sri K. Srinivassa Murthy and Miss G. Sudha, Advocates for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-21012(8)/82-D.IV (B), dated 23-8-1982 referred the following dispute under Section 10(1)(d) & (7A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division, and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division is justified in dismissing Sri T. Komariah, Lorry Driver, with effect from 23-10-1977 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 3 of 1982 and notices were issued to the parties.

2. The brief facts of this dispute are as follows : Sri T. Komariah was working as a Driver in the employment of Singareni Collieries Company Limited. He was sent to Ballarajah as a Driver along with the lorry APH 2150 belonging to the Company, to fetch back some loads to Mandamarri. On his return journey from Bellarajah to Mandamarri, he picked up three passengers and allowed them to travel in the lorry. While the lorry was proceeding from Asifabad towards Mandamarri, at about 5.30 P.M., the lorry met with an accident at a distance of about five kilometres from Asifabad, and the lorry fell turtle across the road resulting in injuries to the passengers. The Management issued a charge sheet Ex. M2 dt. 17-7-1977 against the driver, and he gave his explanation Ex. M3 dt. 1-8-1987. He pleaded in his explanation that while he was driving the lorry after passing Asifabad towards Rebana, he noticed that the ropes tied over the load of the lorry got loosened; and that then he stopped the lorry and sought the help of some pedestrian as there was no Cleaner with him that after properly tying these ropes, the pedestrian wanted a lift and he obliged them. He denied, that the accident is due to his rash and negligent driving. The Enquiry Officer conducted a domestic enquiry and ultimately the Management dismissed him with effect from 23-10-1977. Hence this dispute resulting in the reference.

3. Before this Tribunal, the Management sought a finding regarding the validity of the domestic enquiry as a preliminary issue, and this Tribunal passed an order dt. 19-11-1983 holding, that it is not valid as no proper opportunity was given to the workman for defending his case. The Management examined four witnesses before this Tribunal as M.Ws. 1 to 4 and marked Exs. M1 to M15. M.W4 was examined on 6-7-1988 on which date, the evidence of the Management was closed. When the matter was coming on for the evidence of the workman, the Driver died on 18-8-1988, and his widow and children were brought on record as his L.Rs. as per the order passed in M.P. No. 202/88. Thus there is no oral or documentary evidence adduced for the workman in this case. After hearing the arguments of both sides and on a perusal of the entire record, I have passed this Award.

4. The following points will arise for my consideration :

- (1) Whether the Driver is guilty of unauthorisedly carrying passengers in the lorry opposed to the discipline of employees?
- (2) Whether the accident is due to rash and negligent driving of the Driver?
- (3) To what result?

5. Point (1):—It is an admitted fact, that the Driver picked up some passengers on the way and allowed them to travel in the lorry, and they also sustained injuries in the occurrence. His case is, that they are only gratuitous passengers, and that he did not collect any money from them. The question is not, whether he allowed them to travel either gratuitously or for consideration? Allowing passengers to travel on a lorry is itself an offence. He admitted in his claim statement, that he was charged sheeted for the offence, that he was convicted and fined in a criminal court. M.W4 is one of the passengers, and according to him, the Driver allowed them to travel in the lorry by collecting fares from him, the daughter and his brother. M.W2 is S. Satyanarayana a Mazdoor of the Singa-

reni Collieries Company Limited and his evidence shows, that he was sent as a Cleaner-cum-Mazdoor along with the lorry, that he was also travelling in the lorry, that at Asifabad this Driver picked up these passengers. Thus, the Driver unauthorisedly carried passengers which is an offence. Apart from it, when a passengers of the lorry is involved in an accident, under the provisions of M.V. Act, the owner and the Insurance Company are liable for compensation for the injuries caused to these passengers. Therefore, by allowing unauthorised passengers to travel in the lorry, he not only committed an offence, but he also had taken the risk of making the Management liable for the damages and compensation. Hence I find, that it amounts to misconduct and this point is answered accordingly.

6. Point (2):—He pleaded in his explanation and also in the claim statement, that there was rain, the road margins were muddy and slippery, and in order to avoid striking a buffellow, he turned the lorry from the road towards one side, and that therefore, the lorry turtled. M.W4 deposed, that he does not know how the occurrence took place. MW-2 deposed, that at the time of occurrence, there was good daylight and there was no signs of witness at any where the accident took place. At the time of the accident, the entire road was clear and there were no vehicles or animals coming opposite to the lorry. The accident was on level road, the road margins were at normal level. According to him, the road eroded on one side, and the lorry got down in that eroded portion and that this Driver lost the steering control and the vehicle fell on the road. Therefore, in view of this unchallenged evidence of M.W2, it is evident, that there was no rain, the road margins were not wet, slippery and muddy, and that the occurrence took place due to the loss of control over the steering. When the road was bad, a cautious driver should go slowly and cautiously. If the vehicle was not going at a rash speed, and negligently, the occurrence would not have happened. Hence I find, that the Driver is guilty of rash and negligent driving resulting in the accident and this point is answered accordingly.

7. Point (3):—It is contended for the Driver-Workman, that in any way the punishment of removal from service is disproportionate to the gravity of the misconduct. The rash and negligent driving is also an offence besides carrying unauthorised passengers in a lorry. But by permitting unauthorised persons to travel in the lorry, the driver also made the management responsible for paying damage and compensation to the injured persons, and I feel that he is guilty of gross misconduct, and that it should not be viewed leniently. It is contended for the Driver, that he was already fined in the Criminal Court and that therefore, a departmental action will amount to double jeopardy. The learned Advocate of the workman could not cite any authorities for the proposition, that where a workman was convicted for some offence, with regard to the same acts which also amount to misconduct, departmentally, he is not liable for departmental disciplinary action. In the circumstances, I feel that the Management justly dismissed the workman from service.

8. In the result, an Award is hereby passed finding, that the Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri Division is justified in dismissing Sri T. Komaraiah, Lorry Driver, with effect from 23-10-1977 and that therefore, the Driver or his dependents are not entitled for any relief.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 13th day of March, 1990.

D. RAMALINGA SWAMY, Industrial Tribunal
[No. L-21012(8)/82-D.IV.B/IR(C.II)]

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined
for the Management :

Witnesses Examined
for the Workmen :
NIL

M.W1 Isap Hussain
M.W2 S. Satyanarayana
M.W3 M. Srirama
M. W4 V. Mongu

Documents marked for the Management:

- Ex. M-1—By consent Domestic enquiry report pertaining to T. Komaraiah.
- Ex. M2. Charge Sheet dt. 17/30-7-77 issued to T. Komaraiah by Dy. C.O.S., M.M. (in Ex. M1 at page 20).
- Ex. M3 Explanation dt. 1-8-77 to the charge sheet submitted by T. Komaraiah to the Assistant Controller of Stores, Mandamarri Division (in Ex. M1 at page 21).
- Ex. M4 True copy of the charge sheet dt. 9-8-70 issued to T. Komaraiah by ACOS, M.M. S.C. Co. Ltd.
- Ex. M5 True Copy of the explanation dt. 13-8-70 submitted by T. Komaraiah to the Assistant controller of Stores, Mandamarri Division.
- Ex. M6 True copy of the enquiry notice dt. 26-8-70 issued to T. Komaraiah by the Assistant Controller of Stores, Mandamarri Division.
- Ex. M7 True Copy of the statement of T. Komaraiah dt. 9-8-70.
- Ex. M8 True Copy of the letter dt. 25-9-70 of P.T. Thomas A.P.O., M.M. to A.C.O.S., MM with regard to enquiry on 3-9-70 against T. Komaraiah.
- Ex. M9 True Copy of the Warning letter dt. 2-11-70 issued to T. Komaraiah by ACOS, M.M. S.C. Co. Ltd.
- Ex. 10. True copy of the Charge Sheet dt. 28-3-76 issued to T. Komaraiah by the Dy. C.O.S., M.M. S.C. Co. Ltd.
- Ex. M11 True Copy of the letter of Colliery Manager, Ravindre Khani No. 5 dt. 1-3-76 to D. S. RKP. with regard to 15 H.P. Motor.
- Ex. M12 True Copy of the explanation dt. 1-4-76 to the charge sheet dt. 28-3-76 (Ex. M10) submitted by T. Komaraiah to the Dy. C.O.S. Mandamarri Divisional Stores.
- Ex. M13 True Copy of the statement of T. Komaraiah dt. 1-3-76.
- Ex. M14 True Copy of the Statement of Gant Shankaraiah dt. 29-4-76.
- Ex. M15 True Copy of the Suspension Order dt. 12-7-76 issued to T. Komaraiah by Dy. C.O.S., M.M., S.C. Co. Ltd.

Documents marked for the Workmen:

NIL

D. RAMALINGA SWAMY, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1990

का.आ. 1127—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में- केन्द्रीय सरकार व मैमर्जे सिंगरानी कोलियरीज के.लि. रामाकुण्णापुर के प्रबन्ध-तन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th April, 1990

S.O. 1127.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial

Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., Ramakrishnapur and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-90.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri D. Ramalinga Swamy, B.Com. B.L., Industrial Tribunal.

Dated, the 5th March, 1990

Industrial Dispute No. 28 of 1986

BETWEEN :

The Workmen of S. C. Co. Ltd., Ramakrishnapur I Division, P. O. Ramakrishnapur, Adilabad District (A.P.).

AND

The Management of M/s. S. C. Co. Ltd., Ramakrishnapur Division-I, P. O. Ramakrishnapur, Adilabad District (A.P.).

APPEARANCES :

Sarvasri V. Venkata Ramana and V. Srinivas, Advocates for Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Miss G. Sudha and Miss V. Usha Rani Advocate for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-21012/9/85-D.III(B) dt. 15-7-1986 referred the following dispute under Section 10(1)(d) & (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employer in relation to the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur-I Division, P. O. Ramakrishnapur, District Adilabad (A. P.) and their workmen to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the management of S. Co. Ltd., RKPJ Division in terminating the services of Sri Rajendi Mallaiah ‘C’ Grade Fitter on superannuation treating his age to be 60 years without medical examination and assessment of the same by the Medical Officer in terms of the Company’s age retirement rules and settlements dated 26-2-65 and 17-9-69 with effect from 31-1-85 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?”

This reference was registered as Industrial Dispute No. 28 of 1986 and notices were issued to the parties.

2. The brief facts of this dispute are as follows :—Sri Rajendi Mallaiah worked as Fitter in Singareni Collieries Company Limited and the Management served Ex. W1 proceedings dt. 1-1-1985 on him informing, that he attains the age of superannuation of 60 years by 31-1-1985 and that therefore, he will be retired from service w.e.f. that date. The Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli espoused the cause of the worker and sent Ex. W2 communication dt. 13-1-1985 to the Management stating, that the worker joined the service at the age of 18 years, that in the year 1957 a Bonus-cum-Identity card was issued to him stating that he was aged 27 years, that therefore he was aged only 55 years by 31-1-1985, that as per the Settlement dt. 26-2-1965 and 17-9-1969 his age has to be determined by the Medical Officer, and that the age of the worker may be corrected as 55 years. The Management retired the workman from service w.e.f. 31-1-1985 as stated in Ex. W1. Hence this dispute.

3. The point that arises for consideration in this reference are :—

- (1) Where the action of the Management in terminating the services of the workman on superannuation treating his age as 60 years without medical examination in terms of the Company Age Retirement Rules and Settlements dt. 26-2-1965 and 17-9-1969 w.e.f. 31-1-1985 is justified ?

(2) To what result ?

4. Point (1).—The Union filed a claim statement pleading : that Rajendi Mallaiah was appointed in the year 1948 at the age of 18 years : that as per the agreement dated 26-2-1965 and 17-9-1969 the workman should have been sent to the Medical Officer for determination of his age; that the Management had given the workman age to the L.I.C. Policy as wrongly mentioned in the Service Book but not as per the decision of the Medical Board; and that, therefore, the termination of his services on the ground of superannuation is illegal and unjust.

5. The Management filed a counter pleadings : that the workman was appointed not in the year 1948 but in the year 1940: that by the year 1948 by which time the service-record was started he was aged 24 years; that the Management issued Identity Cards to all the employees in the year 1973-74; that in pursuance of the Settlement of the years 1965 and 1969 the Union identified some of the cases of the employees about whom there are disputes regarding the age and that all such cases were dealt with according to those Settlements; that in the year 1981, there was another revision of the procedure for determining the age: that this workman never raised any dispute with regard to his age till 13-1-1985; that the Circular dt. 6-7-1981 alone governs the determination of age but not the Settlement dt. 26-2-1965 and 17-9-1969; and that therefore, the termination of services of this workman on his retirement is correct.

6. Before going into the fact in dispute, it is necessary to consider the procedure laid down for determining the age of the workman by virtue of the Settlements between the workmen and the management. The workman relied upon Exs. W5 and W6 Settlements. As per Clause (1) of Ex. W5 Settlement dt. 26-2-1965, a tentative procedure was agreed upon pending the proper verification of the age recorded till after the Wage Board Recommendations is known. The interim procedure agreed thereunder is “In the meantime it is agreed that in all cases the workers were asked to retire on attaining the age of 60 on the basis of the existing entries in the service record they should be referred to the Company’s Medical Officer for his opinion regarding the correctness of the age. The opinion expressed by the Company’s Medical Officer shall be final and binding on all the parties” Thus, this is only an interim arrangement as to what to do till the final decision is taken after the Wage Board Recommendations are made known. This interim procedure should apply, only to those persons who are asked to retire meanwhile on the basis of the ages as recorded by the service record. But subsequently there was another Settlement Ex. W6 dt. 17-9-1969. As Ex. W5 was only an interim arrangement, it had no life after Ex. W6 came into effect. It was agreed as per Ex. W6: “.the individual employee who joined the Company’s service before 1960 and whose age or date of birth as entered in the service record has not been verified by the Company’s Medical Officer after the introduction of the Gratuity Scheme in 1959, will be sent up by the Company Medical Officer wherever the age or date of birth is entered in the service record is contested, and the opinion of the Medical Officer in this regard shall be final.” In the present case, admittedly Rajendi Mallaiah was never sent for medical opinion with regard to his age though some age was recorded in the record of his service. Therefore, based on Ex. W6, this dispute is raised by the Union. But as can be seen from Ex. M2 dt. 6-7-1981 the determination or verification of the age of the employees was finalised by the Joint Bipartite Committee for Coal Industry and the procedure prescribed therein with regard to the existing employees was laid down in Part (B) Clause 1(a) and it reads :

1. (a) “Wherever there is no variation in records, such cases will not be reopened unless there is a very glaring and apparent wrong entry brought to the notice of the Management. The management after being satisfied on the merits of the case will take appropriate action for correction through age determination Committee/Medical Board.”

2.
3.
4.

5. The decision of the Committee will be binding and final.

6. The above procedure will come into force with immediate effect and will supersede the existing procedure orders, if any, on this subject."

The fact, that there was a revision of the procedure by the Joint Bipartite Committee for Coal Industry was also pleaded in para 7 of the counter by the Management, and the Union did not file any rejoinder therefor. W.W1 is the concerned workman, who cannot be expected to know about these agreements. M.W1 is the Senior Personnel Officer of the S. C. Company Limited and he deposed : that Exs M2 to M5 are the various circulars of the J.B.C.C.I. with regard to the mode of the determination of the age. In view of Clause 6 of Ex. M2 I have no doubt in my mind about the fact, that the settlements covered by Exs. W5 and W6 were superseded under Ex. M2. The contention of the workman, that Exs. W5 and W6 were still in force in the year 1985 has no legs to stand. We are not concerned about the subsequent circulars Exs. M3 to M5 issued in the years 1988 and 1989 long after the disputed event of the termination of the services of this worker. Therefore I find, that by the year 1985 the procedure laid down in Ex. M2 alone governs this case.

7. The workmen did not file any documentary evidence to show, as to what is his exact date of birth, or as could have been the year of his birth, but he merely relies on the entries in Ex. W3 Bonus Card. The first dispute by the workman reflects in Ex. W2 which is a communication sent by the Union stating, that in the Bonus-cum-Identity Card issued to him in the year 1957, his age was shown as 27 years, and that therefore by the year 1985 he was aged 55 years. But when Ex. W3 Bonus Card was produced before the Tribunal, there is obviously a correction of the age noted therein. The first figure No. 2 is in the same ink of the other writings, but the next figure No. 4 is obviously a correction made in some different ink in the place of some other figure there. Obviously there is interpolation by some mischievous correction before Ex. W3 was produced before the Tribunal. Hence no reliance can be placed on the entry made in Ex. W3. W.W1 i.e., R. Malliah admitted in his evidence that a Bonus Card containing his photo and signature was issued. Evidently Ex. W3 does not contain his photo. He claims, that he has another Bonus Card with his photo and signature thereon, and he will file it in the Tribunal. He denies the suggestion, that the Bonus Cards were issued for the first time in the year 1973-74. It is immaterial, whether the Bonus Cards were issued in the year 1973-74 for the first time or earlier in the year 1957. W.W1 stated that he has another Bonus Card with him containing his signature and photo, but he did not produce it to show, as to what was the age recorded in such Bonus Card, and when that Bonus Card was issued. The workman now relied on the expert opinion of Prof. of Forensic Medicine. This Tribunal sent W.W1 for medical examination for determination of his age to W.W2 who is a Professor of Forensic Medicines of Omania University. She gave her medical report Ex. W7 dt. 8-8-1988 stating, that the workman might be aged 60 years. As per Ex. W-7 the Medical expert examined the workman on 8-8-1988 and opined, that he is aged about 60 years. In the cross examination W.W2 admitted, that with regard to a person who completes age of 25 years, the determination of age by medical tests is more based on guess, and that normally the age determined may vary between 2 to 5 years either this way or that way by adding or deducting. If this is so, the possible error is unto a margin of 5 years either by deducting or by adding. Hence when W.W2 opined that the workman was aged 60 years by the year 1985, he might be aged either 65 years or 55 years. As per the Management, he completed the age of 60 years by 31-1-1985, but as per the Union the workman was aged only 55 years by that time. In the light of the admission of W.W2, it cannot be concluded that the age of the workman could not be 60 years by 31-1-1985. Apart from it, under the reference this Tribunal is not competent to determine as to what was his age by 31-1-1985. Since the scope of the reference is categorically laid down therein.

8. In the aforesaid circumstances it is suffice to state, that the workman could not place any prima facie evidence to probablise, that he was not aged 60 years by 31-1-1985.

9. It is the admitted case, that this Management started maintaining service record for the workmen only from the year 1948 onwards. Ex. M1 is the service card wherein his age was shown as 24 years by 21-8-1948 on which date the service card was prepared. If this is so, his probable year

of birth will be either 1924 or 1925. The order of appointment was also shown as 1940 therein. If this is so, he might have joined the service while he was aged 15 years or 16 years. Even in Ex. W3 Bonus Card, the date of appointment was noted as 1940 only. It is in the evidence of MW-1 that the workman requested the Management to give his age certificate for furnishing it to L.I.C. and they issued a certificate as per Ex. M6 dt. 19-2-1970. The fact that the age certificate was obtained from the Management for the purpose of LIC as per the age entered in the service book is admitted in the claims statement. Therefore, I have no hesitation in my mind to believe, that the original of Ex. M-6 was issued to the workman for the purpose of producing it before LIC. Even in Ex. M-6 his age was stated as 24 years by 21-8-1948. The reason as to why the year of his appointment is being disputed by the workman as 1948 but not 1940 is obvious. In the claim statement and also in Ex. W-2 he stated, that he joined the service at the age of 18 years. If the year of joining the service is 1940, his year of birth will be somewhere in the year 1922 would will make him elder than even the age that was mentioned in the service card. Therefore, he is obviously pleading, that he joined the service in the year 1948, and it is quite inconsistent with the entries made in Ex. W-3. I believe that this workman joined the service MW-1 and the entries found in the various records including Ex. W-3, I believe that this workman joined the service only in the year 1940 but not in the year 1948. If he was born in about the year 1930, he would be only a child of 10 years by the year 1940. His joining the service at that under age is quite improbable. On the other hand, he categorically admitted in his evidence, that he did not join as a child but he joined while he was aged 18 years, when he was sufficiently able to carry the loads. In the circumstances, there is nothing improbable if the age furnished in Ex. M-1 is correct. MW-1 deposed, that in the years 1959 and 60 Union have brought out the employees list with regard to change of date of births and all their cases were settled and their date of births were changed accordingly. The case of Malliah was not put forth for any change. For the first time his age being disputed by the Union only after Ex. M-2 was issued. There is no oral or documentary evidence to prove, that this workman or the Union made any requests to the Management to revise the date of the birth of this workman under the guidelines laid down in Exs. W-5 W-6 and M-2. It is not as though, that the workman was not aware of the age as noted in the service record. He obtained a certificate from the Management as per Ex. M-6 for producing it before the L.I.C. and obviously he was aware that his age was shown as 24 years by the year 1948 in the service record. He never raised any dispute. He did not produce the so called bonus card containing his photo and signature, though he admitted that he has such a bonus card. The Management denies the truth and the genuineness of Ex. W-3 Bonus Card as it is their case, that the Bonus Card was issued for the first time in the year 1973-74. There can be no doubt about the fact, that the worker was aware of the age as noted in the record of service atleast ever since the year 1970. Apart from it, the evidence of MW-1 is, that this workman signed in the service record and it was counter-signed by one Gosalan the Welfare Officer and that the worker also affixed his thumb mark thereon. There is no reason why his evidence may not be believed, especially when the service card contains the purported signature and the thumb mark of the workman. In spite of the knowledge of his age noted in the records of the service, this workman or the Union never disputed about the correctness of the same either under Exs. W-5, W-6 or M-2 and did no demand for determination of the age by the Company's Medical Officer. Even under Ex. W-6 Settlement dated 17-9-1969, it is only in the case of a workman who contests about the entries made in the service record with regard to his age need he sent for the opinion of the Medical Officer but not all cases. This procedure is superseded by Ex. M-2 as stated earlier. As per Ex. M-2 even if there is any variation in records such cases will not be reopened unless there is glaring and apparent wrong entry brought to the notice of the Management. In this case the record is always constant and there are no variations between the records. Hence there is no evidence to show, that there is any glaring and apparent wrong entry about the age of this workman. The workman, never raised or disputed about the entries made in the records regarding his age though he was aware

of it all through till he received Ex. W-1. Therefore, based on the entries made in the service record and in view of the procedure laid down in Ex. W-6 and M-2, I think that the Management rightly terminated the services of this workman. I find, hat the action of the Management in terminating the service of Rajendi Mallaiah on superannuation treating his age as 60 years without medical examination and assessment of the same by the Medical Officer in terms of the Company's age retirement rules and settlements dated 26-2-1965 and 17-9-1969 and also the subsequent proceedings Ex. M-2 dated 6-7-1981 is justified. This point is answered accordingly.

10. In the result the action of the Management of Singareni Collieries Company Limited, RKP-I Division in terminating the services of Sri Rajendi Mallaiah 'C' Grade Fitter on superannuation treating his age to be 60 years without medical examination and assessment of the same by the Medical Officer in terms of the Company's age retirement rules and settlements dated 26-2-65 and 17-9-69 with effect from 31-1-85 is justified and the workman is not entitled to any relief.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 5th day of March, 1990.

D. RAMALINGA SWAMY, Industrial Tribunal
[No. L-21012(9)/85-D.III (B)/IR (C-II)]

APPENDIX OF EVIDENCE

Witness Examined

for the Workmen :

WW-1 --Rajendi Mallaiah

WW-2—Dr. Srimathi Raja Gopalan.

Witness Examined

for the Management :

MW-1—M. Jonathan.

Documents marked for the Workmen

Ex. W-1—Photostat copy of the letter dated 1-1-85 addressed to Rajendi Mallaiah by the Senior Divisional Engineer Ramakrishnapur Workshop, S.C. Co. Ltd., Ramakrishnapur with regard to termination of employment due to superannuation.

Ex. W-2—True copy of the Representation dated 13-1-1985 made by the President, Tandur Coal Mines Labour Union (INTUC) Bellampalli with regard to illegal termination notice issued to Rajendi Mallaiah.

Ex. W-3—Bonus Card of Rajendi Mallaiah.

Ex. W-4—Copy of the age retirement rules.

Ex. W-5—Copy of the Memorandum of Settlement arrived at during the conciliation proceedings held by the Regional Labour Commissioner (C), Hyderabad under Section 12 of the I. D. Act, 1947 on 26-2-1965 in the dispute between the Management of S.C. Co. Ltd., and the workers of S.C. Co. Ltd, Bellampalli represented by the Tandur Coal Mines Labour Union.

Ex. W-6—Copy of the Memorandum of Settlement arrived at in the Conciliation Proceedings held by the Chief Labour Commissioner (C) New Delhi under Section 12(3) of the I. D. Act, 1947 in the dispute between the Management of the S.C. Co. Ltd., and their workmen represented by the Singareni Collieries Workers' Union, Kothagudem and Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli.

Ex. W-7—Opinion of the doctor with regard to age of the worker (R. Mallaiah).

Documents marked for the Management

Ex. M-1—Identity and Service Record of R. Mallaiah.

Ex. M-2— Photostat copy of Circular dated 6-7-1981 of Chief General Manager, S.C. Co. Ltd., Kothagudem Collieries with regard to procedure for determination/verification of the age of the employees

Ex. M-3—Photostat copy of the circular dated 1-8-88 of the Director (Personnel), S.C. Co. Ltd., Kothagudem Collieries with regard to procedure for determination/verification of age of the employee and for resolution of dispute cases of service records.

Ex. M-4—Photostat copy of National Coal Wage Agreement III implementation instruction No. 76 dated 25-4-1988.

Ex. M-5—Photostat copy of the Circular dated 1-8-89 of the Director (Personnel), S.C. Co. Ltd., Kothagudem Collieries with regard to procedure for determination/verification of age of the employee and for resolution of disputed cases of service records.

Ex. M-6—Certificate of age as per the Service Records of R. Mallaiah.

D. RAMALINGA SWAMY, Industrial Tribunal

का.आ.1128.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार व मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड लि. की धीमोमैन कोलियरी के प्रबन्धनत्व में संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणभ कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार की 2-4-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1128.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dhemommain Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 2-4-90.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

Reference No. 66 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dhemommain Colliery of M/s. Eastern Coal fields Ltd.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Sukumar Chakravarty, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employer.—None.

On behalf of Workmen.—None.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Coal.

AWARD

By order No. L-19012/123/86-D.IV(B) dated 29th May, 1987, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this tribunal for adjudication :

“Whether the action of the Management of Dhemommain Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited in dismissing Smt. Bara Sonamoni, Casual Wagon Loader from 20-5-85 was justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?”

2. When the case was called out on 20-3-1990 nobody appeared on either side. A petition has however been received from the workmen stating therein that the union is no longer interested to pursue the present reference case.

3. On due consideration of the petition of the union, I find that this Tribunal has no other alternative but to pass a "No dispute Award" and accordingly a "No Dispute Award" is passed.

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 23rd March, 1990.

SUKUMAR CHAKRAVARTY, Presiding Officer

[No. L-19012(123)/86-D.IV.B/IR(C.II)]

का. आ. 1129.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व मैसर्स ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमि. की टोपसी कोलियरी के प्रबन्धन में संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-3-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1129.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Topsi Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 30-3-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL
Reference No. 51/89

PARTIES :

Employers in relation to the management of Topsi Colliery of M/s. E. C. Ltd.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Sri Prasanta Banerjee, Advocate.

For the Workman.—Sri Manoj Mukherjee, Advocate.

Industry : Coal

State : West Bengal

Dated, the 20th March, 1990

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for

adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(198)/89-IR(C. II) dated the 14th December, 1989.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Topsi Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., in dismissing Sri Tanku Das, Underground Loader w.e.f. 26-4-88 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed by the parties to day in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement and I make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

N. K. SAHA, Presiding Officer

[No. L-22012(198)/89-IR(C. II)]

Enclose Settlement.

FORM 'H'

Name of the Parties :

Sri G. R. Singh, Dy. Chief Personnel Manager, Kunusteria Area, E.C.L. P.O.s Toposi, Dt. Burdwan.

Representative of the workman :

Sri C. S. Banerjee, General Secretary, CMU (INTUC) Cinema Road, Ukhta.

Sri Tanku Das, Workman concern.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Sri Tanku Das, Ex-U. G. Leader of Toposi Colliery was dismissed on the misconduct of unauthorised absenteeism vide letter No. A KNT/P&IR/26B/1885 dated 26-4-88 after proper enquiry into the chargesheet issued to him for the above misconduct.

Sri Tanku Das as well as Sri C. S. Banerjee, General Secretary, CMU (INTUC) represented to the management for the re-instatement of Sri Tanku Das. On their request the matter was discussed at different level and after prolonged discussion the competent authority has approved the re-instatement of Sri Tanku Das which has been communicated vide letter No. ECL/CMB/C-6E/14-586 dated 23-25th Oct. '89 on the following terms and conditions :—

1. Sri Tanku Das, Ex-Ug. Leader will be re-instated as Casual U. G. Leader and the performance shall be watched for one year and in case he put in 190 days physical attendance during one year period, he can be declared permanent Ug Leader and the continuity of service could be granted to him at that stage.
2. That the period of idleness from the date of dismissal to the date of resumption of duty

shall be treated as dies-non and no back wages shall be paid for the period of idleness.

3. Sri Tanku Das will be posted Toposi coll. Representing the workman :

1. Sri C. S. Banerjee,
General Secretary,
CMU (INTUC)
Cinema Road, Ukhta.

2. Sri Tanku Das,
Workman concern.
Representing the employer

1. Sri G. R. Singh,
Dy. Chief Personnel Manager,
Kunusteria Area, E.C. Ltd.,
P.O. Toposi, Dt. Burdwan.

2. Smt. R. Rathors
Dy. Personnel Manager (IR),
Kunusteria Area, E.C. Ltd.,
P.O. Toposi, Dt. Burdwan.

का. आ. 1130.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व मैसर्स ई. सी. लिमि. की टिलाबोनी कोलियरी के प्रबंधन से संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-3-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1130.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tilaboni Colliery of M/s E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 30-3-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 41/89

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Tilaboni Colliery of M/s. Eastern Coal-
fields Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer.—Sri P.K. Das, Advocate.

For the Workmen.—Sri Manoj Mukherjee,
Advocate.

INDUSTRY.—Coal.

STATE.—West Bengal.

Dated, the 19th March, 1990.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(5)/89-IR(C-II) dated the 2nd August, 1989.

Schedule

"Whether the action of the Management of Tilaboni Colliery of M/s. E.C. Ltd., in denying regularisation to S/Sri Muktidhar Gorai, C.D. Chatterjee, Anil Dhitar, Debasis Sen, Sd. Abdul Jalil, N.G. Dutta in Grade II w.e.f. 18-4-1986 is justified ? If not, in Grade II w.e.f. 18-4-1986 is justified ? entitled ?"

2. Today (19-3-90) Sri Manoj Mukherjee the learned Advocate for the workmen has submitted that he has no instruction to proceed with the case. He has also prayed for passing appropriate order. Sri P. K. Das the learned Advocate for the management is also present.

3. As the learned Advocate for the workmen has no instruction from his clients to proceed with the case, it must be presumed that no dispute exists between the parties. As such I have no other alternative but to pass a 'no dispute' award in this case. Hence a 'no dispute' award is passed.

This is my award.

[No. L-22012(5)/89-IR(C.II)]
R. K. GUPTA, Desk Officer

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1990

(आयकर)

का.आ. 1131.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड II (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आवास विकास वित्त निगम लि., बम्बई द्वारा जारी किए गए "13 प्रतिशत आ. वि. नि. व्यास बंधपत्र-शृंखला 'क' को उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

परन्तु उक्त परन्तुक के तहत लाभ ऐसे बंधपत्रों के पृष्ठांकन या डिलीवरी द्वारा अंतरण की दशा में तभी अनु-
ज्ञेय होगा, जब अंतरिती ऐसे अंतरण के 60 दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड को सूचित करता है।

[सं. 8615/पा.सं. 275/127/89-आ. करीब]
बी. ई. एलैक्जेंडर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 21st March, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1131.—In exercise of the powers conferred by clause (iib) of the proviso to section 193 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby specifies the "13 per cent—HDFC Trust Bonds—Series A" issued by the Housing Development Finance Corporation Limited, Bombay, for the purposes of said clause :

Provided that the benefit under the said proviso shall be admissible in the case of transfer of such bonds, by endorsement or delivery, only if the transferee informs the Housing Development Finance Corporation Limited, by registered post within a period of sixty days of such transfer.

[No. 8615/F. No. 275/127/89-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

[महानिदेशक (आयकर छूट) का कार्यालय]

कलकत्ता, 6 फरवरी 1990

(आयकर)

का.आ. 1131.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961, की धारा 35 (पैतीरा/एक/दो) की उप धारा (1) के खण्ड (2) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय प्रवर्ग" के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख), सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक

(आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री सत्या साई इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग प्रशान्ति निलयम जिला-अन्नतपुर आंध्र प्रदेश पिन-515134

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-91 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 101/फा. सं.डी.जी./ए.पी.-5/कल 35(1)
(ii) 89-आ. कर (छूट)]

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL

Calcutta, the 6th February, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1132.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of Sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May, of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June, each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning,
Prasanthinilayam, District Anantapur,
Andhra Pradesh, Pin-515134.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1991.

[No. 101/F. No. DG/AP-5/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

कलकत्ता, 14 फरवरी, 1990

Calcutta, the 14th February, 1990

(INCOME-TAX)

(आयकर)

का.आ. 1133.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजा जाएगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षण वार्षिक लेखा की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्थिया एवं दत्तदायिता के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दि निजामस इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस पंजागुट्टा हैदराबाद-500482।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-88 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 102/फा. सं. जी.जी./एपी-8/कल./35(1)(ii)
89-आ. कर (छूट)]

S.O. 1135.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Nizam's Institute of Medical Sciences,
Punjabgutta, Hyderabad-500482.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1988 to 31st March, 1990.

[No. 102/F. No. DG/AP-8/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1134.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (I) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्यो-

गिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा (यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र श्री छः प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इन्स्टिट्यूट ऑफ मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट 62-एफ सुजानगर पार्क, नई दिल्ली 110003।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 103/फा.सं.जी.डी./एनडी-1 कल/35(1)(iii)/89 आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1134.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in Triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax

Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, there months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Institute of Marketing & Management,
62-F, Sujangarh Park,
New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No. 163/F. No. DG/ND-1/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1135 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैरिस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्टर फार रिसर्च प्लानिंग एण्ड एक्शन
16, दक्षिणेश्वर

10, हैले मार्ग नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 104/फा.सं. डी.जी./एन.डी-16/कल./35 (i)
(iii)/89/आ.कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1133.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Research, Planning & Action,
16, Dakshineswar,
10, Hailey Road,
New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No. 104/F. No. DG/ND-16/Cal./35(1)(iii)/89-I(T)]

(आयकर)

का.आ. 1136.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6

के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है :

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016, को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

पीपुल्स इन्स्टिट्यूट फार डेवेलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग
4-ए, शाहपुर जाट, नई दिल्ली-110016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 105/फा.सं. डी./जी./एन.डी/33 कल. 35 (i)
(iii)/89-आ. क. (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1136.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

People's Institute for Development and Training,
4-A, Shahpur Jat,
New Delhi-110016.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1988 to 31st March, 1990

[No. 105/F. No. DG/ND-33/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आर-कर)

का. आ. 1137.—सर्वसाधारण को सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में

संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दि इण्डियन इकॉनोमेट्रिक सोसायटी
इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ
यूनिवर्सिटी इन्क्लेव दिल्ली-110007

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 106/फा.सं.डी.जी./एन.डी-37 कल./35 (i)
(iii)/89-आ.कर. (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1137.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Indian Econometric Society,
Institute of Economic Growth,
University Enclave,
Delhi-110007.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No. 106/F. No. DG/ND-37/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

का. प्रा. 1138.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीम एक/तीन) की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016, को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त, आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया
पो. बॉक्स नं. 7100 इन्द्रप्रस्था मार्ग
नई दिल्ली-110002

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-88 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 107/फा.सं.डी.जी./एनडी-46 कल./35(i)
(iii) 89/आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1138.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & 1023 GI/90—13

Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Chartered Accountants of India,
Post Box No. 7100,
Indraprastha Marg,
New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No. 107/F. No. DG/ND-46/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

आयकर

का.प्रा. 1139.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीम एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वास्तु शिल्प फाउण्डेशन फार स्टडिस एण्ड रिसर्च इन एन-वाइरॉनमेंटल डिजाइन
संगेत थालतेज मार्ग अहमदाबाद-380054

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-88 से 31-3-89 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 108/फा.सं.डी.जी./जी-25/कल./35(1) (ii)/
89-आ.कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1139.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three

months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Vastu Shilpa Foundation for Studies & Research in Environmental Design,
Sangeth, Thalhej Road,
Ahmedabad-380054.

This Notification is effective for the period from 1st April 1988 to 31st March, 1990.

[No. 108/F. No. DG/G-25/Cal./35(1)(ii)89/IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1140.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा (यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कर्नाटक इन्स्टिट्यूट आफ एप्लाइड एग्रिकल्चरल रिसर्च
समीरवाडी जिला-बीजापुर
कर्नाटक इस्टेट

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की
अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 109/फा. सं. डी.जी./कटी-11/कल. 35(1)(ii)/
89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1140.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Karnataka Institute of Applied Agricultural Research,
Sameerwadi, District Bijapur,
Karnataka Estate.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 109/F. KT-11/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1141.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित
संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैनीस/
एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव,

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से,
आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधि-
कारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित
शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेक्टर फार रिसर्च इन कूलर एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट
2ए सेक्टर
19-ए मध्य मार्ग, चण्डीगढ़-160019

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की
अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 110/फा. सं. डी.जी./पी.-2 कल. 35 (1)(iii)
89-आ. कर. (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1141.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Research in Rural & Industrial Development,
2-A Sector 19-A, Madhya Marg,
Chandigarh-160019.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No. 110/F. No. DG/P-2/Cal. 35/(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1142.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/तीन) की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, प्राप्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/

आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचूरी इंडिया सोसायटी
2-ए, सेक्टर 19-ए मध्य मार्ग
चण्डीगढ़-160019

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं 111/फा. सं. डी.जी./पी. 3 कल./35 (1)(iii)/
89-आय.कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1142.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Twenty-First Century India Society,
2-A, Section 19-A, Madhya Marg,
Chandigarh-160019.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990

[No. 111/F. No. DG/P-3/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

आयकर

का.आ. 1143—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतिस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री अरविन्द इंटरनेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एडुकेशनल रिसर्च औरोविला, कोटाकुप्पम
तामिलनाडु-605104

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 112/फा. सं.डी.जी./टी. एन-8 कल./35(i)
(iii)/89-आ.कर. (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1143.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-

section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Sri Aurobindo International Institute of Educational Research,
Aurovillla, Kottakuppam,
Tamil Nadu-605104.

This Notification is effective for the period from 1st April 1989 to 31st March, 1990.

[No. 112/F. No. DG/TN-8/Cal./35(1)(iii)/89-17(E)]

(आयकर)

का.आ. 1144—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतिस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 3 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और
(ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट),
जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

डायबेटोज रिसर्च सेंटर फाउण्डेशन
5, मेन रोड, रोयापुरम्
मद्रास-600013.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 113/फा. सं. डी.जी. टी.एन.-18/कल./35 (1)
(ii)/89-आ.कर. (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1144.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association", subject to the following conditions :

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Diabetes Research Centre Foundation,
5, Main Road, Royapuram,
Madras-600013.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No. 113/F. No. DG(TN-18/Cal.35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1145—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतिस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संव" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

म्मान इण्डस्ट्रीज टेस्टिंग एण्ड रिसर्च सेंटर
25 ए एवारासपलायम मार्ग
के. आर. पुरम पो. आ.-कोयम्बटूर-641006

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 114/फा. सं. डी.जी./टी.एन.-26/कल./35-
(1) (ii)/89-आ.कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1145.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific &

Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two), of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association", subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Small Industries Testing & Research Centre,
25-A, Avarampalayam Road, K. R. Puram,
P.O. Coimbatore-641006

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No. 114/F. No. DG/TN-26/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 114.6.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतिस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी अन्य-व्यय आस्तियों एवं देदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन का अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक छूट, जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इन्स्टिट्यूट फर फिनान्सियल मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च
30 कोटारी मार्ग पो.बक्स नं.-3330
नूंगम्बक्कम मद्रास-34

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 115 फा. सं. टी.डी.जी. टी.एन.-28 कल./35
(1)(iii) 89-आ.कर. (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1146.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Institute for Financial Management & Research,
30, Kothari Road, Post Box No. 3330,
Nungambakkam, Madras-34.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1989 to 31st March, 1990.

[No 115/F. No. DG/TN-28/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

(INCOME-TAX)

का.आ. 1147 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा, (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संघ' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016, को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बाल-मन्दिर रिसर्च फाउण्डेशन
नं.-126, एम. एन. चैट्टी मार्ग
टी., नगर, मद्रास-600017

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 116/ता. सं. डी.जी./टी. एन.-29/कल./35(1)
(ii)/89-आ.कर (छूट)]

S.O. 1147.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June, each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Bala Mandir Research Foundation,
No. 126, S. N. Chetty Road, T. Nagar,
Madras-600017.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 116/F. No. DG/TN 29/CaL/35(1)(ii)/89-IT(E)]

का.आ. 1148 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 25 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और

(ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट)
जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

निम्बकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट
फाल्ता-415523, जिला-सतारा
महाराष्ट्र (भारत)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 117/फा. सं. डी.जी./एम.-16/कल./35 (1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1148.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Nimbkar Agricultural Research Institute,
Phaltan-415523, Dist Satara,
Maharashtra (India).

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 117/F. No. DG/M-16/Cal./35(1)(ii)/89-IT(P)]
1023 GI/90-14.

(आयकर)

का.आ. 1149.—मर्वमाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैसीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, औद्योगिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

डा. रामजिनी रिमर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्स्पेशनल
हैल्थ सर्विसेज,
557, गुरुवार पथ, पुणे-411002

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 118/फा. सं. डी.जी./एम.-32/कल/35 (1)(ii)/-
89 आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1149.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in

concurrency with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Dr. Ramazini Research Institute of Occupational Health Services, 557, Shukrawar Path, Pune-411002.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 118/F. No. DG/M-32/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1150.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की श्रद्धा बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की श्रद्धा बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

ग्रासिम मेडिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट

निरलाग्राम-456331

नागडा (मध्य प्रदेश)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की श्रद्धा के लिये प्रभावी है।

[सं. 119/फा. सं. डी. जी./एम.पी.-1/कल./35 (1)

(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1150.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1961, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Grasim Medical Research Institute, Birlagram-456331, Nagda (MP).

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 119/F. No. DG/MP-1/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

कलकत्ता, 12 जनवरी, 1990

Calcutta, the 12th January, 1990

(INCOME-TAX)

आय-कर

का. आ. 1151.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीम/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 8 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मंगलम्
ए-445, इन्दिरानगर
लखनऊ-226016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 120/फा. सं. डी.जी./पू.पी.-5/कल./35 (1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

S.O. 1151.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research; and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Mangalam,
A/445, Indiranagar,
Lucknow-226016.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 120/F. No. DG/UP-5/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

कलकत्ता, 17 जनवरी, 1990

(आयकर)

का. आ. 1152.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीम/एक/तीन) की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के

लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिरला इकनॉमिक रिसर्च फाउण्डेशन
9/1, आर. एन. मुखर्जी मार्ग
कलकत्ता-700001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 121/फा. सं.डी. जी./इकन्यू-8/कल./35 (1)
(iii)/89-आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 17th January, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1152.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.

It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Economic Research Foundation,
9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700001.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 121/F. No. DG/WB-8/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

कलकत्ता, 19 फरवरी, 1990

(आयकर)

का. आ. 1153.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सीताराम भारतीय इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्टिफिक-रिसर्च,
प्लेट नं. 1-ई. 216, ए.जी. सी. बोस मार्ग, कलकत्ता-
700017

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 122/का. स. डी. जी./एम.जी./एनडी.-II/कल./-
35 (1) (ii)/89-आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 19th February, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1153.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Sitararam Bhartia Institute of Scientific Research
Plot No. 1/E, 216, A.J.C. Bose Road,
Calcutta-700017.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90

[No. 122/F No. DG/ND-11/Cal/35(1)(ii)/89-IT(F)]

(आयकर)

का. आ. 1154—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वि सोसायटी फॉर रिकन्स्ट्रक्चर्ड सर्जरी, रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज बाजार (उरी संजिल) फ्लैट नं. 400001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 123/का. स. डी. जी./एम.-86/कल./35
(1) (ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1154 - It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific

and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section 1 of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Society for Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Research, Shree Chetrapati Shivaji Maharaj Market (3rd floor), Phallon Road, Bombay-400001

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 123/F. No. DG/M-86/Cal./35(1)(ii)/89-TT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1155:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परिक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आंशिक एवं वित्तीयों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक

(आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मद्रास इन्स्टिट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज 79, सेकण्ड मैन रोड, गांधी नगर, अद्वयार, मद्रास-600020

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 124/फा. सं. डी.जी./टी.एन. 27/कल./35(1)

(iii)/89-आ.कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1155.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for

extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research,

(संगठन) का नाम

NAME OF THE ORGANISATION

Madras Institute of Development Studies,
79, Second Main Road, Gandhi Nagar,
Adyar, Madras-600020.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 124/F. No. DG/TN-27/Cal./35(1)(iii), 89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1156:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनु-मोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति भी अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

दि यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन ऑफ मद्रास इंडिया,
"ग्लेनव्यू", पो.वा -11,

कुंनूर-643101 (तमिलनाडु)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[म. 125/का. सं. डी.जी./टी.एन.-30/कल. :/35
(1)(ii)/89-आ.कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1156.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The United Planter's Association of Southern India,
"Glenview", P.B. No. 11,
Coonoor-643101,
Tamil Nadu.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 125/F. No. DG/TN-30/Cal./35(1)(ii), 89-IT(F)]

(आयकर)

कलकत्ता, 27 फरवरी, 1990

का. आ. 1157:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (2) के लिये सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम 1962 के नियम 6 के

अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है ।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा ।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली—110016 को भेजेगा ।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा ।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिसके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड निवरो साइंस पोस्ट नं.-2900, बैंगलोर-560029

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है ।

[सं. 126/फा. सं. डी.जी./क.टी.-8/कल./35(1)
(ii) /89-आ.कर. (छूट)]

Calcutta, the 27th February, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1157.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (i) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.

(iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

(iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

National Institute of Mental Health and Neuro Sciences,
Post Bag No. 2900,
Bangalore-560029.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 126/F No. DG/KT-8/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1158.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए पत्रद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है ।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा ।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा ।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा ।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलोर-560080, इंडिया

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 127/फा. गं. डी.जी./के.टी.-16/कल./35(1)
(ii)/89-आ.कर(छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1158.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Raman Research Institute,
Bangalore-560080,
India.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[127/F. No. DG/KT-16/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

1023 GI/90—15

(आयकर)

का. आ. 1159—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, शास्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वि मादर सीभीस सोयाईटी प्लोट-4, बेंकटा नगर
एकमटेंशन पोण्डीचेरी-605011

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 128/फा. स. डी.जी./पी.एम.-4/कल./35(1)
(iii)/89-आ.कर(छूट)]

Calcutta, the 11th January, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1159.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (i) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961, under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/The Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Mother's Service Society,
Plot 4 Venkata Nagar Extension,
Pondicherry-605011.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 128/F. No. DG/Pon-4/Cal./35(1)(iii)/89-IT(I)]

(आयकर)

का. आ. 1160 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परिक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ना है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र का 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

केरला फरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पृची-680653,
त्रिचूर (केरला)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[मं. 129/फा. गं. डी.जी./के.-5/कल./35(1)
(ii)/89-आ.कर(छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1160.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income tax Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

(INCOME-TAX)

Kerala Forest Research Institute,
Puthi-680653
Trichur (Kerala).

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90

[No. 129/F. No. DG/K-5/Cal./35(1)(ii)[89-IT(F)]

(आयकर)

का. आ. 1161 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैरोस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष को 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हेक्समार एग्रिकल्चर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फाउण्डेशन,
हेक्समार हाउस, बम्बई-400025 28, सयानी रोड

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है :

[सं. 130/का. ग. पी.जी./एम. 3/कल./35(1)
(ii)/89-आ.कर. (छूट)]

S.O. 1161.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Hexamar Agricultural Research and
Development Foundation, Hexamar House,
28, Sayyani Road, Bombay-400025.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 130/F. No. DG/M-3/Cal./35(1)(ii)[89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1162 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरोस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया :—

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष को 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च सोसाइटी लटूर-413510, महाराष्ट्र।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 131/फा. सं. डी.जी./एम-15/कल./35(1) (ii)/89-आ.कर(छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1162.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension

to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Vivekanand Medical Research Society,
Latur-413512,
Maharashtra.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 131/F. No. DG|M-15|Cal|35(1)(iii)|89-IT(E)]
(आयकर)

का. आ. 1163.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकाव्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

स्वामी रामानन्द तिर्य इंस्टीट्यूट ऑफ सोसियो इकॉनामिक, रिसर्च एण्ड नेशनल इंस्टीट्यूशन, 1-10-342, ब्राह्मणबादी, बेगम पेट, हैदराबाद-500016

(यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 132/फा. सं. डी.जी./एम-34/कल./35(1) (iii)/89-आ.कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1163.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Swami Ramanand Teerth Institute of Socio-Economic Research & National Integration.
1-10-342, Brahmanwadi, Begumpet,
Hyderabad-500016.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 132/F. No. DG|M-34|Cal|35(1)(iii)|89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1164 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसी/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों को एक प्रति अपनी प्राय-व्यय, आस्तियों एवं वेतनवारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक

अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकारों में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र को 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बम्बई नेचुरल हिस्टोरी सोसाईटी हॉर्नबिल हाउस ओप-
लायन गेट, बिहाइन्ड, भगत सिंह रोड, बम्बई-400023

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 133/फा. सं. डी. जी. /एम.-55/कल./35(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1164.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Bombay Natural History Society,
Hornbill House, Opp. Lion Gate,
Behind Bhagat Singh Road, Bombay-400023.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 133/F. No. DG|M-55|Cal|35(1)(ii)|89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1165:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमिकल इंजीनियर्स डा. एच.एल. राय, बिस्डिंग, राजा सुबोध मुल्लिक रोड पो.बा. सं. 17001, कलकत्ता-700032।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 134/पा. सं. डी.जी./डब्ल्यू.वी. 1/कल./35(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1165.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the

Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Institute of Chemical Engineers,
Dr. H. L. Roy Building,
Raja Subodh Mullick Road, Post Box No. 17001,
Calcutta-700032.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 134/F. No. DG/WB-1/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1166:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर

आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिसके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

द बिर्ला इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनमी एण्ड प्लेनीटैरियम साइन्स बिर्ला बिल्डिंग, 9/1, आर. एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 135/फा. सं. डी.जी./डब्ल्यू.बी. 3/कल./35
(1)(ii)/89-आ.कर(छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1166.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditures, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over then organisations, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

sion to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Birla Institute of Astronomy & Planetarium Sciences,
Birla Building, 9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 135/F. No. DG/WB-3/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1167.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैटीस/एक/दो) की उप धारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की महमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 78
सहद अमिर अली एव्यू कलकत्ता-700019।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की
अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 136/फा. सं. डी. जी./इन्स्यू. वी. 11/कल./35(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1167.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Birla Institute of Scientific Research,
78, Syed Amir Ali Avenue,
Calcutta-700019.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 136/F. No. DG/WB-11/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. अ. 1168.—सर्वाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

अरविन्द मेडीकल रिसर्च फाउण्डेशन 1, अन्ना नगर,
सादूरार्ई-625020।

यह अधिसूचना 1-4-89 से 31-4-90 तक की
अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 137/फा. सं. डी. जी./टी. एन.-14/कल./35(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1168.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research; and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.

- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Aravind Medical Research Foundaion,
1, Anna Nagar,
Madurai-625020.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 137/F. No. DG/TN-14/Cal/35(I)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1169.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीस/एक/दो) की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदनपत्र की 3 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंडियन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट लैबोराटरी प्लोट नं. 47, डेवेलपेड प्लोट फोर इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज सिव्हराम विलेज, फेरवागुडी मद्रास-900096।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 138/फा. सं. डी.जी./टी.एन.-15/कल./35(1)
(ii)/8-आयकर(छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1169.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research; and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Indichem Research & Development Laboratory,
Plot No. 47, Developed Plots for Electrical & Electronics Industries, Sesvaram Village,
Feruagudi, Madras-600096.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 138/F. No. DG/TN-15/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1170.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीस/एक/दो) की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्न-

लिखित शर्तों पर “संस्था” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

क्रिस्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ़ दि क्रिस्चियन मेडिकल कॉलेज, मेलूर-632004 तमिलनाडू

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 139/फा. सं. डी. जी./टी. एन.-31/कल./35(1)

(ii)/90-आय कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1170.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology, Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.

(iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/The Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Christian Medical College of the Christian Medical College Vellore Association, Vellore-632004.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 139/F. No. DG/TN-31/Cal/35(1)(ii)/90-IT(E)]

(अधिकर)

का. आ 1171:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(वैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हिमालयन इंस्टीट्यूट हास्पिटल ट्रस्ट, 113/89/स्वरूप नगर, कानपुर-208001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 140/फा. सं. डी. जी./यु. पी.-9/कल.

35(1)(ii)/89-आ. कर(छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1171.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of subsection (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Himalayan Institute Hospital Trust,
113/89, Swarup Nagar,
Kanpur-208001.

This Notification is effective for the period from 2-2-1990 to 31-3-1990.

[No. 140/F. No. D.G./UP-9/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1172.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीस / एक / तीन) की उप धारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है ।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा ।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित.

(क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा ।

(iv) अनुमोदन की अवधि के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशन (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक आयकर (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा । यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

सूर स्मारक मंडल ई-113-कमला नगर, अगिरा-5
उत्तर प्रदेश

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[संख्या 141/फा०सं० डी०जी०/यू०पी०-11/कल०/35(1)

(iii)/89 आयकर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1172.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of subsection (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will

also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Sur Smarak Mandal,
E-113, Kamla Nagar,
Agra-5, Uttar Pradesh.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 141/F. No. DG/UP-11/Cal/35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1173. —सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दि इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड एक्सन बी-4/22, आजाद एपार्टमेंट, न्यू दिल्ली-110016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 142/फा.सं.डी.जी.एन.डी.-10/कल/35 (1) (iii)/89-आ.कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1173.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Peace Research & Action,
B-4/22, Azad Apartments,
New Delhi-110016.

This Notification is effective for the period from 25-5-1989 to 31-3-1990.

[No. 142/F. No. DG/ND-10/Cal/35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1174. —सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उप धारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों

पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

जयरामदास पटेल सांख्यिकीय रिसर्च फाउण्डेशन
56/705, इरोज एपार्टमेंट, नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019

यह अधिसूचना 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 143/फा.सं. डी.जी./एन.डी. 17/कल.
35/(1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1174.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five[one/two]) of the In-

come-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Jayramdas Patel Scientific Research Foundation,
56/705, Eros Apartments, Nehru Place,
Delhi-110019.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 143/F. No. DG/ND-17/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1175.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औ

(ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट),
जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स 22 पालम मार्ग, वसन्त विहार
नई दिल्ली -110057

यह अधिसूचना दिनांक 01-04-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 144/फा.सं. डी.जी./एन.डी.-19/कल./35(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1175.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research; and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Development Alternatives,
22, Palam Marg, Vasant Vihar,
New Delhi-110057.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 144/F. No. DG/ND-19/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1175.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट), द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक आयकर (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेलमबे रगर जोइन्ट रिसर्च सेंटर
के./अप, बोटाल एण्ड नेचरल गैस कमीशन कैलाश,
छग तल्ला, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग

यह अधिसूचना दिनांक 6-12-88 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 145/फा.सं. डी.जी./एन.डी.-38 कल./35

(1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1176.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-

tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

ONGC-Schlumberger Joint Research Centre,
C/o. Oil & Natural Gas Commission,
'Kailash, 6th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 6-12-1988 to 31-3-1990.

[No. 145/F. No. DG/ND-38/Cn/35(1)(ii)/89-IT(E)]

आयकर

का.आ. 1177.—पर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीस एक/दो) की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर-नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महा-निदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के लिए अधीन अनुमोदन किया गया है।

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(iii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-

व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार, में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

पी० जे० इंस्टीट्यूट फार कार्डीयो पल्मोनेरी एण्ड यह अधिसूचना दिनांक 2-2-90 से 31-3-90 तक एलाइड मेडिसिन, खसरा नं. 798 काडीपुर, नई दिल्ली-36 की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 146/फा.सं. डी.जी./एन.डी.-45/कल./85
(1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1177.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category three "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research; and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

P. J. Institute for Cardio-Pulmonary & Allied Medicine.
Khasra No. 798, Kadipur,
Delhi-110036.

This Notification is effective for the period from 2-2-1990 to 31-3-1990.

[No. 146/F. No. DG/ND-45/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ 1178.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून, तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आम्नियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयुक्त, आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयुक्त, आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एशियन सेंटर फॉर आर्गेनाइजेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट 75, लाजपत राय रोड, लाजपत मार्ग-II नई दिल्ली-110024

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 147/फा.सं. डी.जी./एन.डी.-48 कल./35

(1)(iii)/90-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1178.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.

(iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities

(iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Asian Centre for Organisation Research and Development, 75, Lajpat Rai Road, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 147/F. No. DG/ND-46/Cal/35(1)(iii)/90-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1179.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त / आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मोडल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशनल रिसर्च बी.सी.
रोड, जम्मू-180001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 148/फा.सं. डी.जी./जे. एण्ड के. 1/कल./35/
(1)(iii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1179.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research; and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

1023 GI/90

NAME OF THE ORGANISATION

Model Institute of Educational Research,
B.C. Road,
Jammu-180001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 148/F. No. DG/J&K-1/Cal/35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

नं.आ 1180.—पर्वसाधारण की सूचना के लिए एनद्-द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(पैतीस/एक/ दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा - निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिरला रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार थ्रयलाइड साइन्स
बिरला ग्राम-456331 नागदा मध्य प्रदेश।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 149/फा.सं. डी.जी./एम.पी.-2/कल./35
(1)(ii)/90-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1180.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Research Institute for Applied Sciences,
Birlagram-456331,
Nagda, Madhya Pradesh.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 149/F. No. DG/MP-2/Cal/35(1)(ii)/90-IT(E)]

(आयकर)

कलकत्ता, 1 मार्च, 1990

का. आ 1181 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैबीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकार अर्थात् महानिदेशक, आयकर छूट द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्रवाइयों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान

विभाग औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली- 110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक आयकर छूट (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बेफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउण्डेशन "कामधूने", सेनापति बापट मार्ग, पुणे-411016।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 150/फा.सं. डी.जी./एम. 57/कल. 35(1)/
(ii)/89-अ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

Calcutta, the 1st March, 1990

S.O. 1181.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions)

having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

BAIF Development Research Foundation,
Kamdhenu,
Senapati Bapat Marg,
Pune-411016.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 150/F. No. DG/M-57/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

कलकत्ता, 5 मार्च 1990

का० आ 1182.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्रवाइयों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक सेवा परीक्षित वार्षिक लेखा की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतिषों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किसे गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिरला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी, मेसरा-735215
रांची, बिहार।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-87 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 151/फा.स. डी.जी.बी.-1 बल./35(1)

(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

Calcutta, the 5th March, 1990

S.O. 1182.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.

(iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.

(iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Institute of Technology,
Mesra-835215,
Ranchi, Bihar.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 151 F. No. DG/B-1/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 1183.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (i) के (ii) खण्ड के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित

प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डियन सोसायटी आफ सोयल साइन्स डिवीजन आफ सोयल साइन्स एंड एग्रिकल्चरल केमिस्ट्री इण्डियन एग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली-110012

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 152(फा.सं. डी.जी./एन.डी.-50/कल/35/ (1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1183.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of

Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.

- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Society of Soil Science.
Division of Soil Science and Agricultural Chemistry,
Indian Agricultural Research Institute.
New Delhi-110012.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 152 F. No. DG/ND-50/Cal/35(1)(ii)/89-IT(F)]

(आयकर)

का.आ. 1184.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एन.डी.आर. यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैसीम एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक, भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-16 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, (ग) आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महा-

निदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिरला एकादमी सूर्य किरण, 5वीं मंजिल, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 153(फा.सं. डी.जी./एम.डी.-52/कल./35/
(1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1184.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Academy,
Surya Kiran, (5th floor),
19, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 153/F. No. DG/ND-52/Cal/35(1)(ii)/89-IT(F)]

(आय-कर)

का. आ. 1185.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वाचित यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35

1023 GI/90—

(पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा का एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुजरात रिसर्च सोसायटी,
सम्सोधन सदन, राम कृष्ण मिशन मार्ग, वार, बम्बई-400052

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 154/फा.सं. डी.जी./एम.-24/कल./35(1)
(2)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1185.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the

Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it, for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Gujarat Research Society,
Samshodhan Sadan, Ramkrishna Mission Marg,
Khar, Bombay-400052.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 154/F. No. DG/M-24/Cal/35(I)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1186.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव,

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ना है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट (यू.पी.),
सेक्टर-डी, अन्तीगॉज (जॉ. एस. आई./ भवन के सामने)
लखनऊ-226020

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रवर्ती है।

[सं. 155/का.सं. डी.जी./यू.पी.-8/कल. 35 (1)
(iii)/89-प्रा. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1186.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/Three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

(INCOME-TAX)

Institute of Management Development (U.P.),
Sector-D, Aligenj (Near G.S.I. Building),
Lucknow-226020.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 155/F. No. DG/UP-8/Cal/35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1187.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उप धारा (1) के खण्ड (ii) के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महा निदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वि इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (भारत)

8, गोखले मार्ग, कलकत्ता-700020

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 156(फा.सं. डी.जी./इडब्ल्यू बी-26/कल./35 (1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

1023 GI/90

S.O. 1187.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General I.T. Exemptions in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Engineers (India),
8, Gokhale Road,
Calcutta-700020.

This Notification is effective for the period from 1-4-89 to 31-3-90.

[No. 156/F. No. DG/WB-26/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

कलकत्ता, 8 मार्च, 1990

(आयकर)

का. आ. 1188.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (iii) यह अधिसूचना को 30 जून तक, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वाषिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक, और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दि रिसर्च एसोसिएशन,

113, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 157/फा.सं. डी.जी./डब्ल्यू बी-17/कल./35
(1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 8th March, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1188.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three

months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Tea Research Association,
113, Park Street, Calcutta-700016.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 157/F. No. DG|WB-17|Cal|35(1)(ii)|89-IT(E)]

(आयकर)

फा. आ. 1189:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परिक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

(आयकर)

विमदर्श इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च.

10, तालकटोरा मार्ग, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[नं. 158/फा.सं. डी.जी./एन.डी. 47/कल./35
(1)(ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1189.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association", subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 on or before financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Mother's Institute of Research,
10, Talkatora Road,
New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 158/F. No. DG/ND-47/Cal/35(1)(ii)89-IT(E)]

फा. आ. 1190.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पेंतीस/एक/दो की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

जैन रिसर्च फाउण्डेशन सोसायटी
पो. आफिस-बालवाडा, जिला बुलसर, गुजरात-396108

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[नं. 159/फा.सं. डी.जी./जी.-3/कल./35 (1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1191.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Jain Research Foundation Society,
P.O. Valvada, Dist-Balsar,
Gujarat-396108.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 159/F. No. DG/G-3/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

आयकर

का.आ. 1192:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षण वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय; आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दिरिसर्च सोसायटी आफ दि ग्राण्ट मैडिकल कालेज एण्ड जे.जे. ग्रुप आफ हास्पिटल्स, वार्ड नं. 9, पहली मंजिल, मेन बिल्डिंग, जे.जे. ग्रुप आफ हास्पिटल्स बम्बई-400008

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 160/फा.सं. डी.जी./एम.-84कल./35 (1)
(2)/89आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1192.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner, of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

The Research Society of the Grant Medical College and J.J. Group of Hospitals, Ward No. 9, 1st Floor, Main Building, J.J. Group of Hospitals, Bombay-400008.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 160]F. No. DG[M-84;Cal]35(1)(ii)[89-IT(E)]

कलकत्ता, 9 मार्च, 1990

(आयकर)

का. आ. 1193.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पंतीस/एक/दो) की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महंगौली रोड, नई दिल्ली-10016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

- (4) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से उक्त निदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डियन कैंसर सोसायटी

लेडी रतन टाटा मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर,
महर्षि कार्वे मार्ग, को-ऑपरेज, बम्बई-400021

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 161(फा.पं. डी.जी./एम.-59/कल./35 (1)
(2)/89 आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 13th March, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1193.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Cancer Society,

Lady Ratan Tata Medical and Research Centre,
M. Karve Road, Cooperage,
Bombay-400021.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 161]F. No. DG[M-59;Cal]35(1)(2)[89-IT(E)]

कलकत्ता, 13 मार्च, 1990

(आयकर)

का. आ. 1194.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पंतीस/एक/तीन) की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016, को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गांधी लेबर इंस्टीट्यूट,
थॉलतेज मार्ग, भीम नगर, अहमदाबाद-380052

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 162(फा.सं. डी.जी./जी.-5/कल./35(1)
(3)/89-आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 13th March, 1990
(INCOME-TAX)

S.O. 1194.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the : (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions)

having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.

- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Gandhi Labour Institute
Thaltej Road, Mem Nagar,
Ahmedabad-380052,

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 162/F. No. DG/G.S/Ca135(1)(iii)89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 1195.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है :—

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि

प्रमाणों के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

संधाता मेडिकल रिसर्च सोसायटी,
एक्स्टेंशन क्षेत्र, मेराज-416410

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 163/फा.सं. डी.जी./एम.-44/कल./35 (1)
(2)/89-आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1195.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rule, 1982, i.e., the Director General (I.T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Sandhata Medical Research Society,
Extension Area,
Miraj-416410.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 163/F. No. DG[M-44/Cnl/35(1)(ii)/89-IT(E)]

आयकर

का. आ. 1196.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन

विहित प्राधिकारी अधीन महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रथम के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मराटे रिसर्च फाउंडेशन,
माने भवन, श्री गोविन्द राव जी मराठी मार्ग,
मेराज-416410 (महाराष्ट्र)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 164/फा.सं. डी.जी./एम. 81/कल./35 (1)
(2)/89-आ. कर, (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1196.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (I. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of The Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Marathe Research Foundation,
Mane Building,

Shri Govindraoji Marathi Road,
Miraj-416410. (Maharashtra),

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 164/F. No. DG/M-81/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

प्रायकर

का.आ. 1197:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरिस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी आय-व्यय, आस्तियों एवं देदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिसके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये, यह अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/

प्रायकर निदेशक (छूट) गिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से महानिदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये गये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हार्ट फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी-11, सिल्वर-आर्क गुजरात रेलवे क्रॉसिंग के सामने एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-89 से 31-3-90 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 165/का.स. डी.जी./अं.-24/कन/35(1)(ii)/89-

आ. कर (छूट)]

INCOME-TAX

S.O. 1197.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e., the Director General (J. T. Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year.
- (iii) It will submit to the (a) Director General (Income-tax Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure, and its assets and liabilities.
- (iv) It will apply in triplicate for further extension of the approval, to the Director General (Income-tax Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. It will also submit six copies of the application for extension to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

NAME OF THE ORGANISATION

Heart Foundation and Research Institute,
C-11, Silver ARC, Near Gujarat Railway Crossing,
Ellis Bridge, Ahmedabad-380006.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1990.

[No. 165/F. No. DG/G-24/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]